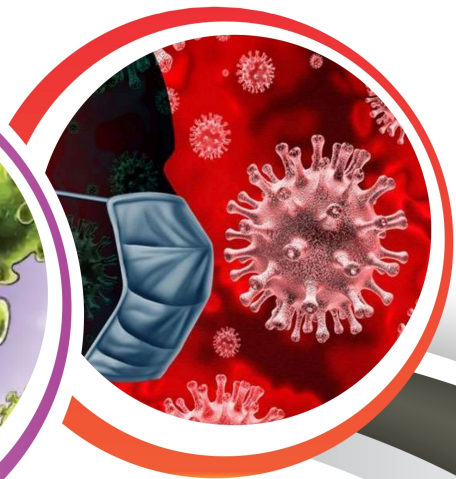
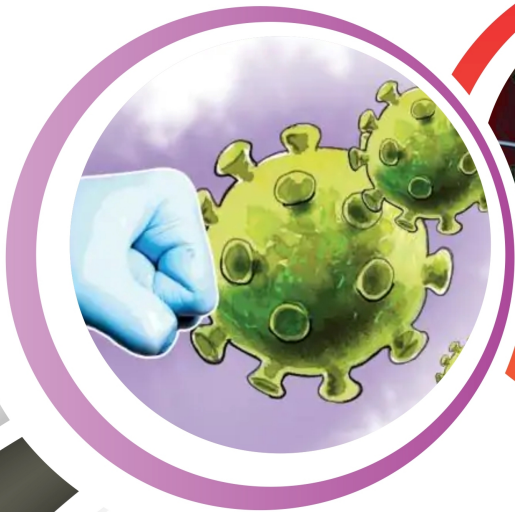


कोविड-19

चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीति



डॉ. अखिलेश शुक्ल

कोविड-19 चुनौतियों और भविष्य की रणनीति

कोविड-19 चुनौतियों और भविष्य की रणनीति

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक

पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड तथा
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड



सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

ISBN- 978- 81- 87364 81-8

रिसर्च जर्नल का वार्षिक विशेषांक

ISSN 0973-3914

Research Journal of Social & Life Sciences

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal Old No.40942, Impact Factor 5.125 IIFS

Indexed & Listed at: Ulrich's International Periodicals Directory©,

ProQuest, U.S.A (Title Id: 715205)

(An Official Journal of Centre for Research Studies, Rewa, M.P, India)

Registered under M. P. Society Registration Act, 1973 Reg. No. 1802

कोविड-19 चुनौतियां और भविष्य की रणनीति

©सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

प्रथम संस्करण : 2021

₹ 600.00

प्रकाशक

गायत्री पब्लिकेशन्स

186/1 लिटिल बैम्बिनोज स्कूल कैम्पस

विन्ध्य विहार कॉलोनी

पड़रा, रीवा (म.प्र.) 486001

फोन : 7974781746

E-mail- researchjournal97@gmail.com

researchjournal.journal@gmail.com

www.researchjournal.in

लेजर कम्पोजिंग - प्रेम ग्राफिक्स

रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: लीनेज ऑफसेट

रीवा (म.प्र.)

पुस्तक में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। पुस्तक के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

आमुख

आज हम अपने आप को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझते हैं परंतु क्या प्रकृति ऐसा समझती है, प्रकृति के लिए 84 लाख योनियों में पैदा हुए जीव बराबर हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार 84 लाख योनियाँ हैं और उनमें से एक मनुष्य योनि है। वैज्ञानिकों की बात माने तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, हम मनुष्य उनमें 7.6 बिलियन ही हैं, अर्थात् संपूर्ण जीवों का 0.1 प्रतिशत है और हम मनुष्य ही संपूर्ण योनियों के जीवों के लिए खतरा बने हुए हैं, तो क्या यह ज्ञान है? तो क्या यह विज्ञान है? तो क्या यह विवेक है? अब यह मनुष्य जाति को सोचना है। हम मनुष्यों ने जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है और यह वायरस भी मेरे मतानुसार कहीं ना कहीं इसका परिणाम है। प्रकृति की हर योनियों में पैदा किया गया जीव प्रकृति संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। एक कीट ही एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ढोकर पहुंचाता है और आपके चमन को बहार करता है, तो मनुष्य जाति धोखे में है कि वही प्रकृति का संचालन कर रही है।

इस वायरस से लड़ने के लिए विश्व और भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा प्रयास किये हैं और उन्हीं का परिणाम है कि हम किसी न किसी मात्रा में इस वायरस को नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। यहां मैं मीडिया की तारीफ भी करना चाहूंगा। यहां मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कई दशकों में यह देखने में आया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को मीडिया ने उतना महत्व प्रदान नहीं किया, लेकिन इस वायरस से हुए वैज्ञानिक नवाचार को मीडिया ने वैश्विक परितृश्य में और भारतीय जनमानस के सामने रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज या वायरस निरंतर अपना रूप बदल रहा है। आज पूरा का पूरा विश्व समुदाय कोरेना सेंट्रिक हो गया है और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं आत्मकेंद्रित हो गए हैं। हमारे अंदर एक भय और शंका का वातावरण बना हुआ है। आज हमारी सोच-विचार, रहन-सहन और जीवनशैली बदल गई है। अपने आप को समाज का सर्वोत्तम कृति समझने वाला मनुष्य जीवन जीने के लिए मोहताज है। आज हम एक-दूसरे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, पर हम स्वयं भयाक्रांत हैं, भयभीत हैं, हम सब एक-दूसरे को मरता हुआ देख रहे हैं। आज यह वायरस संपूर्ण वैश्विक समाज के लिए घातक

विषाणु बना हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए इसके मूल स्वरूप को समझना इसकी विस्तारवादी गतिविधि पर रोक लगाना और इसकी समाप्ति के लिए पूर्णता सफल वैक्सीन बनाना एक जटिल कार्य हो गया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अर्थात् मानव को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम सीमा पार करेंगे तो नुकसान मानवता को होगा फिर चाहे वह चीन हो या कोई भी देश। क्या आज चीन इससे पीड़ित नहीं है, क्या वहां मानवता रो नहीं रही है और अगर आज चीनी समुदाय के लोगों का साक्षात्कार लिया जाए तो उनका क्रुंदन ही हमारे सामने आएगा, पता नहीं उनके कितने अपने लोग किस वायरस के शिकार हो गए और उनका पता ही नहीं चला।

कोविड-19 ने हमको यह सिखाया कि परिवार क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक संबंधों का निर्वाह कैसे होता है, क्या यह जीवन सिर्फ भौतिकवादी दुनिया में दौड़ने के लिए ही है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, बस दौड़, दौड़, दौड़,.....। काहे के लिए धन संपदा, यह दौड़ किसलिए, किसके लिए और क्यों यह बात कोविड-19 से हमें समझ आई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के, बिना लोगों के, बिना व्यवहारों के, बिना प्रतिमानों के, वह जीवन बिना मूल्यों के नहीं जी सकता है। कोविड-19 ने बहुत सारी परिभाषाओं को बदल दिया परिभाषाओं के अर्थ बदल दिए, मूल्यों के प्रतिमान बदल दिए और लोगों को यह सिखाया कि जीवन का असली आनंद कहां है और किस तरीके से हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु यह एक लघु प्रयास है। हमेशा की भाँति आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत है।



डॉ. अखिलेश शुक्ल
सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	भारतीय समाज में कोरोना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव डॉ. अखिलेश शुक्ल	09
02.	कोविड-19 : महामारी और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की दोहरी चुनौती श्रीमती आभा सिंघल, डॉ. वर्चसा सैनी	19
03.	कोविड-19 और आत्मनिर्भर समाज चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ डॉ. गंगा देवी बैरागी	26
04.	कोविड और सतत् विकास लक्ष्य डॉ. विनोद शंकर सिंह, सिद्धार्थ मिश्र	31
05.	पर्यावरण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव डॉ. नीलम श्रीवास्तव	37
06.	कोरोना-19 महामारीका महिलाओं तथा बच्चों पर प्रभाव डॉ. आशा गोहे	43
07.	कोविड-19 के बाद बजट 2021.22 में राज्यों के सुधार हेतु उपाय डॉ. कुमुद श्रीवास्तव	53
08.	कोरोना महामारी का मानव के आर्थिक व सामाजिक स्तर पर प्रभाव डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव उमेश सिंह	60
09.	कोविड 19 और प्रवासी मजदूर डॉ. गजानन मिश्र	66
10.	कोविड-19 एवं शिक्षा: चुनौतियाँ एवं भविष्य की रणनीतियाँ डॉ. वीणा, डॉ. मिहिर प्रताप	72
11.	कोविड 19 के परिदृश्य में साहित्य और मीडिया डॉ. अमित शुक्ल	79
12.	कोविड -19 का जनजातीय शिक्षा पर प्रभाव (चम्बा जिले के पंगवाल अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में) लेख राज	84
13.	कोरोना संक्रमण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव (ग्राम हाटी, जिला सतना के विशेष संदर्भ में) विमलेश द्विवेदी, प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल	91

14.	कोरोना वायरस की चुनौतियां और भविष्य डॉ. अलका नायक	99
15.	नवीन परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा जन व्यवस्था और समाज सेवा (कोविड-19 के विशेष संदर्भ में) प्रो. प्रियंका तिवारी, प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल	104
16.	किशोरों पर वैश्विक महामारी का प्रभाव: मानसिक स्वास्थ्य पर एक चुनौती श्रीमती ज्योति बाला चौबे डॉ. श्रीमती रूपम अजीत यादव	113
17.	कोरोना काल के दौरान सुरसा की तरह बढ़ी बेरोजगारी डॉ. दयाशंकर सिंह यादव	118
18.	कोरोना - 19 का भारतीय समाज पर प्रभाव डॉ. सीमा श्रीवास्तव	125
19.	Psycho- Socio analysis of Covid-19 and effect of Gender Inequality in the Development of Women in India Dr. Mihir Pratap, Dr. Veena	132
20.	Impact of Covid-19 on Indian Economy- An Economic Analysis Dr. Vikram Singh	141
21.	Covid-19 Pandemic and Use of ICT in education Dr. Alka Saxena	149
22.	Companies and Policy Makers Can Create a Happier Future of Work Dr. Rajendrakumar Muljibhai Parmar Miss. Dipti Verma	152
23.	The Challenges of Parenting during Covid Times Dr. Sonal Singhvi Choudhary	168
24.	“Effect of Online Classes on Children and Teen's Mental Health: A Case Study of Howrah District West Bengal.” Dr. Anuradha Guha Thakurata	172

भारतीय समाज में कोरोना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• डॉ. अखिलेश शुक्ल

आज हम अपने आप को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझते हैं परंतु क्या प्रकृति ऐसा समझती है प्रकृति के लिए 84 लाख योनियों में पैदा हुए जीव बराबर हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार 84 लाख योनियाँ हैं और उनमें से एक मनुष्य योनि है। वैज्ञानिकों की बात माने तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, हम मनुष्य उनमें 7.6 बिलियन ही हैं अर्थात् संपूर्ण जीवों का 0.1 प्रतिशत है और हम मनुष्य ही संपूर्ण योनियों के जीवों के लिए खतरा बने हुए हैं, तो क्या यह ज्ञान है? तो क्या यह विज्ञान है? तो क्या यह विवेक है? अब यह मनुष्य जाति को सोचना है। हम मनुष्यों ने जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है और यह वायरस भी मेरे मतानुसार कहीं ना कहीं इसका परिणाम है। प्रकृति की हर योनियों में पैदा किया गया जीव प्रकृति संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। एक कीट ही एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ढोकर पहुंचाता है और आपके चमन को बहार करता है, तो मनुष्य जाति धोखे में है कि वही प्रकृति का संचालन कर रही है।

इस वायरस से लड़ने के लिए विश्व और भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा प्रयास किये हैं और उन्हीं का परिणाम है कि हम किसी न किसी मात्रा में इस वायरस को नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। यहां मैं मीडिया की तारीफ भी करना चाहूंगा। यहां मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कई दशकों में यह देखने में आया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को मीडिया ने उतना महत्व प्रदान नहीं किया, लेकिन इस वायरस से हुए वैज्ञानिक नवाचार को मीडिया ने वैश्विक परिदृश्य में और भारतीय जनमानस के सामने रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज या वायरस निरंतर अपना रूप बदल रहा है। आज पूरा का पूरा विश्व समुदाय कोरोना सेंट्रिक हो गया है और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं आत्मकेंद्रित हो गए हैं। हमारे अंदर एक भय और शंका का वातावरण

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

बना हुआ है। आज हमारी सोच-विचार, रहन-सहन और जीवन शैली बदल गई है। अपने आप को समाज का सर्वोत्तम कृति समझने वाला मनुष्य जीवन जीने के लिए मोहताज है। आज हम एक-दूसरे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, पर हम स्वयं भयाक्रांत हैं, भयभीत हैं, हम सब एक-दूसरे को मरता हुआ देख रहे हैं। आज यह वायरस संपूर्ण वैश्विक समाज के लिए घातक विषाणु बना हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए इसके मूल स्वरूप को समझना इसकी विस्तारवादी गतिविधि पर रोक लगाना और इसकी समाप्ति के लिए पूर्णता सफल वैक्सीन बनाना एक जटिल कार्य हो गया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अर्थात् मानव को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम सीमा पार करेंगे तो नुकसान मानवता को होगा फिर चाहे वह चीन हो या कोई भी देश। क्या आज चीन इससे पीड़ित नहीं है, क्या वहां मानवता रो नहीं रही है और अगर आज चीनी समुदाय के लोगों का साक्षात्कार लिया जाए तो उनका क्रुंदन ही हमारे सामने आएगा, पता नहीं उनके कितने अपने लोग किस वायरस के शिकार हो गए और उनका पता ही नहीं चला।

कोरोना वायरस ने हमें हमारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तात्कालिक समस्या से हमें कैसे निपटना चाहिए, दूरगामी योजनाएं हमारी क्या होनी चाहिए और आपातकाल स्थिति में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को हम कैसे बेहतर बना रख सकते हैं। यह प्रश्न शिक्षाविदों, समाज वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए चिंतन का विषय है। प्रकृति हमें बार-बार एहसास दिलाती है, लेकिन मनुष्य विकास और संप्रभुता की दौड़ पर कहां प्रकृति की बात मानता है। कहीं ना कहीं तो मनुष्य की सोच पर डिफाल्ट है। मुझे तो लगता है कि कहीं हम क्रूर एवं जहरीले बायोलाजिकल जैविक हथियार के युग में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ईश्वर करें मेरा यह मानना गलत हो, लेकिन पूरा का पूरा विश्व मंडल का यह परिदृश्य देखकर कहीं ना कहीं तो मन में यह विचार उत्पन्न होता है और उत्पन्न होना भी चाहिए क्योंकि यह वायरस प्रकृति की देन नहीं है।

इस वायरस ने मनुष्य की सामाजिक और दार्शनिक छवि को भी आईना दिखाया है। इस वायरस के संबंध में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे मानव जगत ने पैदा किया है, लेकिन यह मनुष्य की वैश्विक

संस्कृति को चुनौती देने की क्षमता रख रहा है। इस वायरस ने दुनिया की सामाजिकता की परिभाषा को ही बदल कर के रख दिया है, इसने उन लोगों के सामने भी चोट पहुंचाई है, जिन्होंने मानवीय सभ्यता को शिखर तक पहुंचाने का वादा किया था। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि हम इसे विश्वव्यापी इमरजेंसी कह सकते हैं। 200 से अधिक देश या यूं कहा जाए संपूर्ण वैश्विक समाज इस वायरस से पीड़ित हो चुका है तो गलत नहीं होगा। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और अब दूसरा क्रम जारी है। तीसरे क्रम के आने की संभावना जतायी जा रही है। इस महामारी का प्रारंभ कहते हैं, चीन से हुआ वाद-प्रतिवाद सामने आते रहे। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि, क्या वैश्विक समाज आधुनिकता भौतिकता और प्रभुत्ववादी सोच में इतना अंधा हो गया है कि उसे मानवता कहीं दिखती ही नहीं? यदि यह वायरस मानव निर्मित है तो यह मानवता के लिए शर्म की बात है। यह एक गंभीर निंदनीय नैतिकता विहीन कृत्य है, इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में वैश्विक संगठनों को रखना चाहिए।

आज के समाज में हम जितना प्रबुद्ध और वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, उतना ही हम मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बात चाहे कोरोना वायरस की हो या परमाणु बम की। मनुष्य स्वयं अपने विनाश की जमीन तैयार कर रहा है और फिर बेसहारा होकर निस्सहाय होकर ऊपर वाले की तरफ देख रहा है। अब तो डर लगने लगा है, अपनों से मिलने का अपनों से बात करने का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं? क्या यही विकास है? और अगर यही विकास है तो हमारी पुरातन सभ्यता, हमारी वैदिक सभ्यता लाखों गुना अच्छी है, जिसमें हमारी आवश्यकता कम है, संसाधन कम है, लेकिन सुख ज्यादा है, सुख भी कैसा बनावटी नहीं, वास्तविक आनंदमय।

आज मानव निर्मित वायरस हर दिन अपना रंग और रूप बदल रहा है। जैसे आश्चर्य नहीं है यह तो मानव की आधुनिक प्रवृत्ति है। वह क्या बोलता है, क्या करता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना, “मुंह में राम बगल में छुरी।” आइए इसका भावार्थ भी समझ ले अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बाहर से मित्र बना रहता है और अपने मन में हमारे प्रति बुराई लेकर पीछे-पीछे हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अब अगर कोरोना वायरस मानव निर्मित है तो यह बात सत्य और साबित सिद्ध होती

है। आज इस वायरस ने व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा कर दिया है।

आज समाज में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यह वायरस ऐसा है, जिसने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। जो व्यक्ति इस वायरस से पीड़ित हो जाता है, मुझे लगता है कि वह अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है, उसके अंदर मानसिक तनाव और अपराध बोध इतना ज्यादा हो जाता है कि वह सरवाइव नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसके कारण उसके परिवारजन उसके मित्रजन उसके सहकर्मी कहीं उसके कारण तो प्रभावित नहीं हो गए और यह अपराध बोध उसके मन में बैठ जाता है और वह उस वायरस से लड़ने में अपने नाकाम पता है, जो मजबूत है वह इस वायरस से लड़कर के बाहर आ जाते हैं और जो भावनात्मक रूप से कमजोर है, वह कहीं ना कहीं इस वायरस के शिकार हो जाते हैं। अब अगर बात करें हम लोग भारत की तो भारत सरकार ने इस वायरस का सामना करने के लिए जो त्वरित और सामाजिक निर्णय लिया उसकी सराहना होनी चाहिए, मामला थमा, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण आज हम फिर से इस वायरस के संक्रमण की चपेट में हैं।

इस वायरस से निपटने के लिए और इससे पीड़ित या इससे परेशान लोग जो लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों की तरफ चल पड़े थे। दिल्ली, मुंबई और ऐसे ही बहुत सारे बड़े औद्योगिक शहरों से मजदूरों का पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के भारतीय समाज के सामने उपस्थित हुआ। कामगार मजदूर हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर पैदल ही निकल पड़े, जिम्मेदार अधिकारियों और राजनेताओं कोई अंदाजा भी नहीं था लॉकडाउन की स्थिति में समूह बनाकर चल रहे इन कामगारों की तस्वीरों ने देश के सामने बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक कल्याणकारी कदम ऐसे कामगार मजदूरों के लिए निकाले। सवाल यहां पर यह था की घोषणाएं हुई कि पैसा मजदूरों के खाते में चला जाएगा, लेकिन जो मजदूर पलायन की दिशा में रास्ते में थे, उनकी समस्या यथावत थी। प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी, तीव्र गति से ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए रास्ते में रुकने उनके खाने-पीने और बस आदि की व्यवस्था करने में संवेदनशीलता दिखाई जो भारतीय नौकरशाही का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब सवाल यहां पर यह था कि इन समूहों से पहुंचे हुए

लोगों में अगर कोई संक्रमित है, तो वह पूरे के पूरे गांव को संक्रमित कर सकते हैं। प्रथम दौर पर तो सरकार ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन आज जो द्वितीय दौर का संक्रमण का चल रहा है, उसमें हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो जो प्रथम संक्रमण के दौरान थी।

इस दिशा में भारतीय समाज के लोगों ने सराहनीय कार्य किया और भारतीय संस्कृति का उदाहरण पेश करते हुए ऐसे लोगों की मदद की। पूरे भारत में जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया तो प्रवासी मजदूर बुरी तरह हताहत हुए। जब केंद्र और राज्य सरकार ने प्रतिबंध हटा दिए तब एक करोड़ से ज्यादा अंतर राज्य प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल ही चल दिए। रीवा बघेलखंड का एक प्रमुख नगर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के किनारे स्थित है और यहां से भी कई प्रवासी मजदूर पैदल होते हुए अपने राज्यों की तरफ निकले और रीवा के ग्रामीण अंचल में वापस भी आये, यहां के सामाजिक संगठनों ने उनकी मदद की जो मानवीय संवेदनशीलता का परिचायक है। कामगारों का पलायन इस वायरस के कारण एक मुख्य समस्या रही है। वर्तमान समय में भी केंद्र और राज्य सरकारों को यदि लॉकडाउन लगाना है तो यह बात उन्हें स्पष्ट रूप से जनमानस को बतानी चाहिए, उसके लिए उन्हें समय देना चाहिए ताकि वह व्यवस्थित रूप में अपने घर पहुंच सकें। ऐसा ना हो कि 2000 से 3000 किलोमीटर की यात्रा प्रवासी मजदूर या छात्र अपने घर के लिए करें। अगर लॉकडाउन करना हो तो इसके संबंध में केंद्र और राज्य सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए, ताकि लोग भी अपने को उसके अनुसार मानसिक रूप से तैयार कर ले और जैसा भी सरकार का दिशानिर्देश हो उसके अनुरूप कार्य करें।

इस वायरस कि अपनी इकोनामी है, इसने पूरी वैश्विक इकोनामी को चपेट में ले लिया है। हर जगह मंदी है, हर जगह बेरोजगारी है, हर जगह नौकरी में कमी है और डर का वातावरण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर सभी मतभेदों को बुलाते हुए इसकी रोकथाम के संबंध में कार्य करें। आज इस वायरस के साथ हमको जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आज इस वायरस ने हमारी जिंदगी और हमारे समाज दोनों के नजरिया को बदल दिया है और एक नये सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जन्म दिया है।

अब हमें इसी सोशल पर्सपेक्टिव के साथ इस वायरस के साथ

लड़ना पड़ेगा। अगर हम इस पर पर्सपेक्टिव के साथ इस वायरस से लड़ेंगे तो मानवता जीतेगी, मनुष्यता जीतेगी और वायरस हारेगा। यह वायरस कहीं ना कहीं हमको हमारे बिगड़ते पर्यावरण, वैश्विक तापमान और जैव विविधता का लगातार विनाश से हमें जोड़ता है, हमें सजग होना चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए और हमें मानवता को जिंदा रखने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, तभी हम आगामी पीढ़ी को कुछ ना कुछ दे पाएंगे।

हालातों की बात की जाए तो इतने गंभीर हो गए हैं कि उनका विश्लेषण करना यानी मानवता को शर्मसार करना है। आज स्थितियाँ यह हो गई हैं कि व्यक्ति अपने परिजन का अंतिम संस्कार इस वायरस के कारण नहीं कर सकता है। घर में रहते हुए वह अपनों से अलग रहने का प्रयास करता है। मां, बाप, भाई, बहन, पति-पत्नी के रिश्तों को इस वायरस ने दूर कर दिया है। एक सामाजिक दूरी, एक सामाजिक अलगाव इस वायरस ने पैदा कर दिया है।

कोरोना वायरस ने प्रभावित दुनिया में अलग-अलग सोच के आयाम पैदा किये हैं। यदि हम भारतीय संस्कृति के संबंध में सोचने का प्रयास करें तो हम यह पाते हैं कि हमारी संस्कृति और उसकी प्रकृति ने जीवन शैली को सदैव संक्रमण रोधी बनाया है। भारतीय संस्कृति के पंच तत्व अर्थात् पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और पेड़-पौधे आदि में संक्रमण को रोकने की क्षमता विद्यमान है। पश्चिमी संस्कृति में अधिकतर लोगों के बीच ठंडा भोजन तथा ठंडा पेय लेने की विशेषता पाई जाती है, जबकि भारतीय संस्कृति में गर्म- गर्म तथा ताजा भोजन करने की विशेषता है। यह गर्म भोजन और ताजा भोजन विषाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। भारतीय संस्कृति का खान-पान भी हमेशा से संक्रमण विरोधी रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि हम भी समय के साथ- साथ अपनी भारतीय संस्कृति के खान-पान, रहन- सहन के तरीकों को छोड़ते गए हैं और उसका परिणाम आज यह संक्रमण है। भारतीय संस्कृति हमेशा से शाकाहारी रही है और शाकाहारी संस्कृति अनेक प्रकार के संक्रमण को रोकती है, कहते हैं कि प्रकृति ने एक घास का तिनका भी अनुपयोगी नहीं बनाया है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है, सिर्फ यहां पर प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति के बनाए गए जीवों पर अत्याचार क्यों? यह कैसी मानवीय संवेदना है? यह वायरस भी इसी प्रकार के मांसाहार की संस्कृति का परिणाम है। उक्त स्थिति में हमें अपनी भारतीय संस्कृति और अपने भारतीय

दृष्टिकोण को फिर से पूर्णतया: अपनाने पर जोर देना पड़ेगा, तभी हम इस विपदा से और आने वाली विपदाओं उसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। आज हम इस वायरस के प्रभाव में आ जाने पर, बार-बार अच्छी तरह से हाथ धोने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है, वही पश्चिम के संस्कृति की बात करें तो हाथ धोने के बजाए टिशु पेपर से हाथ मुंह साफ कर लेना आम बात है। विश्व के विकसित देशों के नागरिकों में आपसी अभिवादन का तरीका हाथ मिलाकर या चूमने वाला देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही दूर रहकर हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाली परंपरा पाई जाती रही है, आज पूरी दुनिया इसी परंपरा का पालन कर रही है। भारतीय दर्शन में शव को जलाने की परंपरा प्रारंभ से पाई जाती रही है। आज यह साबित भी हो गया शवों को जलाने से ही सभी प्रकार के वायरस का अंत हो सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों ने अब तो त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदल दिया है। इस संक्रमण ने त्योहारों के स्वरूप को भी बदल दिया है।

इस वायरस ने समय के साथ समाज की विसंगतियों को भी हमारे सामने रखा है, चाहे वह विकसित समाज हो या विकासशील समाज। विशेषज्ञ सलाह देते हैं की भीड़ में जाने से बचे, अलग-थलग रहे तथा घर पर रहे, किंतु यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जो श्रमिक है, कम आय वाले अस्थाई नौकरी में है, दुकानों में काम करने वाले, नाई, धोबी, मोची और ऐसे बहुत सारे वर्ग इनके लिए तो परिवार चलाना कोरोना से भी अति आवश्यक है। परिवार का मुखिया यदि घर में बैठ जाता है, तो परिवार कैसे चलेगा, इस संक्रमण को जानते हुए भी वह मजबूरी में घर से बाहर निकलता है, रुपए कमाने का प्रयास करता है ताकि उसके परिवार की रोजी-रोटी चल सके, ऐसे लोगों के पास ना तो हेल्थ बीमा है ना सरकारी हेल्थ बीमा है तो इनकी मजबूरियों को भी हमें समझना होगा। इस संक्रमण ने हमें यह भी सिखा दिया कि कितने लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं, साफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले लोग ही अपने घर में बैठकर काम कर सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी खोदता है, पत्थर तोड़ता है, वह कैसे घर में बैठकर काम कर सकता है? भारत में लाखों ऐसे कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी है कि यदि संक्रमण की स्थिति में वह अनुपस्थित हो गए तो उन्हें उस दिन का वेतन भुगतान नहीं होगा। स्थिति क्या होगी, इसका विश्लेषण हम समाजशास्त्रियों

को करना चाहिए। विभिन्न शहरों और देशों में लॉकडाउन है। ऐसे में हम सभी को अपने आप से ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए कि एक सब्जी विक्रेता घर पर कैसे काम करता है? या, क्या एक दिहाड़ी मजदूर घर पर बैठ सकता है? और अपने अस्तित्व के साधनों से समझौता किए बिना खुद को सामाजिक रूप से अलग-थलग कैसे कर सकता है?

यहां हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को एक मूलभूत प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि भारत एक विकासशील देश है, जहां इस संक्रमण को रोकने में हमारे सामने काफी चुनौतियां हैं, सामाजिक असमानता भी यहाँ काफी है, समाज के उत्कृष्ट या इलीट वर्ग के आइसोलेशन में रहने के अनेक विकल्प हैं, लेकिन यह संक्रमण उन लोगों के लिए नैसर्गिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिनके लिए रोज की रोटी कमाना उनकी जिंदगी है। ऐसे समय पर सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करना चाहिए और मेरी तो यह उपकल्पना है कि ऐसे संक्रमण के दौरान गरीबों पर बीमारी और भुखमरी का ऐसा प्रकोप होता है कि उनकी जिंदगी जीवन-यापन के लिए दया मांगने लगती है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में लॉकडाउन और यातायात प्रतिबंध हो और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पूरी की पूरी वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है, कामगारों के वेतन पर कटौती भी की गई है। यदि ऐसी आपातकालीन स्थिति निर्मित हो जाती है तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के कुछ उपायों को हमें अपनाना चाहिए और क्योंकि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है और हमारे संविधान का यह मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कल्याण सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमें आपातकालीन स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए जो विश्व के अनेक देशों में उठाए भी गए हैं-

- इस वायरस के कारण जिनका काम छूट गया है उन्हें एतिहाद बरतते हुए कुछ वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं
- ऐसे व्यक्तियों को नगद भुगतान की व्यवस्था की जाए ताकि उनका जीवन यापन चलता रहे,
- व्यापारिक जगत में टैक्स में छूट प्रदान की जाए ताकि वाणिज्यिक

और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके, तथा

- संक्रमण से पीड़ित यदि कोई कर्मचारी है तो उसकी वेतन आदि का पूर्ण भुगतान किया जाए।

पर स्थिति यह है कि भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पास सामाजिक संरक्षण के यह संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमें कोई न कोई रणनीति तो बनानी ही होगी, योजनाएं और कानून हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और लोगों द्वारा उन्हें आत्मार्पित किया जाना अभी भी शेष है।

परिवार समाज की बुनियादी संस्था है, कोरोना वायरस ने परिवार को भी प्रभावित किया है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पिछले साल की तुलना में अधिक गंभीर होती जा रही है। पिछले वर्ष जब लाखों भारतीयों ने कोविड योद्धाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए अपने घरों में बिजली के बल्ब बंद कर दिए थे और मोमबत्ती एवं मिट्टी के दीप जलाए थे तब कई ने संभवतः यह सोचा होगा कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन तब से एक साल बीत गया है परंतु स्थिति और विकट हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान देश ने आर्थिक मंदी का दौर जरूर देखा, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण में सुधार, शिक्षा का डिजिटल होने सहित कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।

पूरे भारत में लॉकडाउन होने के कारण व्यवसाय व कारखानों, शिक्षण संस्थाओं अन्य निजी कार्य स्थलों के बंद होने से देश भर के लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। शासकीय सेवा के कर्मचारियों को तो वेतन मिलता रहा लेकिन जो छोटे-मोटे उद्योगों में कार्यरत श्रमिक थे, उनकी वेतन, उनके भत्ते, उनका आवास उनसे सब छिन गया, ऐसी स्थिति में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो सरकार और उद्योग संगठनों के बीच एक तालमेल पैदा कर सकती और इस समस्या को रोक सकती। प्रत्येक जिला प्रशासन को यह चाहिए था कि उनके जिले में कितने औद्योगिक संस्थान हैं और कितने लोग वहां काम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके औद्योगिक संस्थानों के मालिकों से मिलकर एक जन कल्याणकारी योजना का निर्माण करना चाहिए था। जिला प्रशासन को अपने यहां के औद्योगिक अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए थी और उनके यहां कार्यरत श्रमिकों को वहीं रहने की व्यवस्था की सलाह भी देनी

थी। अब प्रश्न यह उठता है की औद्योगिक संस्थान का मालिक बिना उत्पादन हुए उन श्रमिकों के वेतन का भुगतान कैसे करें, जब तक उत्पादन नहीं होगा, तब तक विक्रय नहीं होगा और पैसे नहीं आएंगे, यह मजबूरी औद्योगिक संस्थानों के मालिकों की थी। अचानक सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया, होना यह था की क्रमशः औद्योगिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने श्रमिकों को बुलाना चाहिए था और उत्पादन का कार्य अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए था। शासन औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन को वित्तीय सहायता प्रदान करती तो निश्चित रूप से जो प्रवासी श्रमिक थे, वह बिना सोचे- समझे अपने घरों की ओर न लौटते। यहां मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में उन लोगों के विचारों से सहमत हूँ जो यह मानते हैं कि जिन श्रमिकों के कारण औद्योगिक संस्थान के मालिक लखपति और अरबपति बने, उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान अपने श्रमिकों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। चंद रुपए उनके हाथों में थमा कर उनसे मुक्ति पा ली, जिनके कारण आज आपका औद्योगिक संस्थान, आप की हवेली, आपका बैंक बैलेंस है, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया, यह सामाजिक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी। भारतीय दर्शन यह कहता है कि जिसने हमारे लिए काम किया है, उसे हर हालत में हर परिस्थिति में हर संभव मदद हमें करनी चाहिए।

कोविड-19 ने हमको यह सिखाया कि परिवार क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक संबंधों का निर्वाह कैसे होता है, क्या यह जीवन सिर्फ भौतिकवादी दुनिया में दौड़ने के लिए ही है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, बस दौड़, दौड़, दौड़,.....। काहे के लिए धन संपदा, यह दौड़ किसलिए, किसके लिए और क्यों? यह बात कोविड-19 से हमें समझ आई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के, बिना लोगों के, बिना व्यवहारों के, बिना प्रतिमानों के, वह जीवन बिना मूल्यों के नहीं जी सकता है। कोविड-19 ने बहुत सारी परिभाषाओं को बदल दिया परिभाषाओं के अर्थ बदल दिए, मूल्यों के प्रतिमान बदल दिए और लोगों को यह सिखाया कि जीवन का असली आनंद कहां है और किस तरीके से हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं।

कोविड - 19 : महामारी और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की दोहरी चुनौती

•श्रीमती आभा सिंघल

••डॉ. वर्चसा सैनी

घरेलू हिंसा वह अभिशाप है जो महिलाओं के तन, मन और आस्था पर आघात पहुँचाता है। घरेलू हिंसा स्त्रियों के विकास को अवरुद्ध करने का हथियार है। ये स्थिति सदियों से रही है। सदियों पहले प्लेटो के युग में स्वयं प्लेटो ने इसका वर्णन किया है। उस युग में महिलाओं की दशा अत्यन्त शोचनीय थी और सामाजिक जीवन में उनकी स्थिति गौण थी। एथेन्स में पाए जाने वाली मातृ दासता, एंकागिता तथा नारी की महत्वहीनता के प्रति प्लेटो के हृदय में आक्रोश का भाव विद्यमान था, इसलिए प्लेटो ने अपने दार्शनिक विचार का प्रतिपादन करके इस समस्त बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन तब से आज तक हम इन बुराइयों को समाप्त नहीं कर पाए हैं। सेमिनार हो या गोष्ठी, वाद-विवाद हो या भाषण जब तक हम स्वयं दृढ़ विचारों से समाप्त नहीं करेंगे तब तक महिलाओं को यही दंश झेलना पड़ेगा। आज वैश्विक महामारी के समय यह लैंगिक असमानता व घरेलू हिंसा खुलकर सामने आ रही है। आज महिलाएँ ही सर्वाधिक परेशानियाँ झेल रही हैं। आज स्त्रियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का विषय सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, भौगोलिक, नस्लीय, जातीय सीमाओं को तोड़ते हुए सार्वभौमिक विषय हो गया है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है।

वर्तमान समय में संसार के अधिकतर देश चीन के वुहान शहर से आरम्भ हुए कोविड- 19 रुपी दानव के कारण प्रलयकारी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह कोविड- 19 रुपी दानव पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले चुका है तथा प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोगों की जीवन लीला भी समाप्त कर रहा है। आज इस कोविड- 19 को पूरे विश्व में वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। इस वैश्विक महामारी के समक्ष विश्व के शक्तिशाली

- असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी. कालेज मुजफ्फरनगर
- असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जैन कन्या पाठशाला, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर

देश जैसे, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देश शक्तिहीन साबित हो चुके हैं। इस महामारी ने संपूर्ण विश्व में उथल-पुथल मचा दी है। इस भयानक वैश्विक महामारी के सक्रमण से बचने के लिए विश्व के विभिन्न देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया तथा इस महामारी के साथ युद्ध करने के लिए लाकडाउन का बहुत सख्ती से पालन भी कर रहे हैं। यह महामारी न केवल संपूर्ण विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, वरन् यह महामारी विश्व को एक गंभीर आर्थिक सकंट की तरफ भी ले जा रही है। इस महामारी के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की गतिविधियाँ अवरुद्ध हो चुकी हैं। फैक्ट्री, स्कूल, कालेज, मन्दिर, कार्यालय, सिनेमा हॉल, बाजार जैसी धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व मनोरंजनात्मक संस्थाएँ सभी बन्द हो गयी हैं, सभी लोगों को इस वैश्विक महामारी के कारण अपने घरों में कैद होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप भुखमरी व बेरोजगारी जैसी समस्याएँ उभर कर सामने आई हैं। इस महामारी के कारण अब तक लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस महामारी ने संसार में स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था तक एवम् लोगों के आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है तथा संपूर्ण विश्व को खोखला करती जा रही है। इस महामारी के नकारात्मक प्रभावों से जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं बचा है।

वर्तमान समय में इस महामारी का नकारात्मक प्रभाव संपूर्ण विश्व की महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर भी दृष्टिगोचर होने लगा है। यह महामारी हमारे विश्व की महिलाओं के जीवन को भी अपने कुप्रभाव से सक्रमित कर रही है और इसका अप्रत्यक्ष व नकारात्मक प्रभाव परिवार में महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न, उनके अधिकारों के हनन तथा परिवार में उनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार के रूप में दिखाई दिया है। इस महामारी ने महिलाओं के पारिवारिक रिश्तों में भी सक्रमण पैदा किया है। इस महामारी ने जहाँ एक ओर विश्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा अनेक कम्पनियों, व्यापार, आवागमन एवं जनजीवन पर अपना बुरा प्रभाव डाला है, वहीं दूसरी ओर विश्व में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, लिंग के आधार पर परिवार में भेदभाव तथा महिलाओं के परिवार में उत्पीड़न व शोषण का भी भयावह चित्र प्रस्तुत किया है। इस वैश्विक महामारी के

कारण जो विश्व के अधिकांश देशों में जो लॉकडाउन हुआ है, उसने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को पनपने तथा विकसित होने के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की है, जिससे परिवार में महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार का एक भयंकर रूप दिखाई देने लगा है, जो कि दुनिया के सभ्य समाजों के लिए एक गम्भीर समस्या या चुनौती के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव “ऐटोनिया गुतसे” ने दुनिया के सभी देशों से अनुरोध किया है कि “वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के उपायों को कोरोना या कोविड - 19 के संक्रमण से निपटने की योजनाओं के साथ शामिल करें।” विश्व में इस महामारी के कारण महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड- 19 के कारण किए गए लॉकडाउन के पश्चात दुनिया भर में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस संक्रमण को रोकने के लिए जहाँ एक तरफ विश्व में लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है, वहीं इसने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि की है, जो अत्यन्त चिंताजनक विषय है। जहाँ संसार के समस्त देशों में इस महामारी के संक्रमण से जनता को बचाने के लिए सरकार के द्वारा व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करना, उनको सुरक्षा देना सरकार के लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य बन गया है।

संसार के अधिकांश शक्तिशाली देशों में यह समस्या तीव्रगति से बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन व स्पेन में इस प्रकार की घटनाएँ 20 फीसदी तथा फ्रांस में 30 फीसदी तक बढ़ गई है। आस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा की घटनाएँ 70 प्रतिशत तथा आस्ट्रेलिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य न्यूसाउथ वेल्स में इस प्रकार की घटनाएँ 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। अमेरिका के रोग नियंत्रण तथा रोकथाम केन्द्र के अनुसार चार में से एक महिला तथा सात में से एक पुरुष अपने जीवन साथी के द्वारा गंभीर शारीरिक हिंसा का सामना कर रहा है। यह वैश्विक परिदृश्य इस बात का संकेत देता है कि इस प्रकार की घरेलू उत्पीड़न व हिंसा की घटनाएँ न केवल किसी एक देश में वरन् संसार के विभिन्न देशों में धीरे-धीरे सामने आने लगी है, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। इस सन्दर्भ में विशेषज्ञों के द्वारा भयानक चेतावनी भी जारी की गई है तथा विशेषज्ञों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है।

वैश्विक महामारी के संकट के समय घरेलू हिंसा में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर- गृहस्थी में स्त्री के किए जाने वाले शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न से होता है। यह परिवार के भीतर होने वाली वह हिंसा है, जिसमें परिवार का कोई एक वयस्क सदस्य दूसरे सम्बन्धी को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करता है। सामान्यतः यह पति के द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार माना जाता है। यह दुर्व्यवहार भौतिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक, धमकी तथा मारपीट तक किसी भी रूप में देखा जा सकता है। यह एक प्रकार से घरेलू दुर्व्यवहार से सम्बन्धित होता है। कई बार यह दुर्व्यवहार पत्नी को पीटना, मारना, उसे गिरा देना, उसे किसी प्रकार की चोट पहुँचाना, उसे घर से बाहर निकालना, खर्चे के लिए पैसा न देना और उसे यह एहसास दिलाना कि वह बेकार है, के रूप में दिखाई देता है।

वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों के साथ-साथ भारत ने भी कोविड - 19 महामारी रुपी दानव का सामना करने के लिए लाकडाउन कर दिया है। लाकडाउन के कारण जहाँ एक ओर सभी लोग अपने घरों में बन्द रहने के लिए बाध्य हुए हैं, वहीं दूसरी ओर घरों में बन्द रहने के कारण इसका बुरा प्रभाव महिलाओं के जीवन पर भी देखने को मिला है।

लाकडाउन के कारण लोगों के सामने वर्तमान समय में ऐसी जटिल आर्थिक समस्याओं का उदय है, जिसके कारण लोगों के रोजगार समाप्त हो गए हैं, दफ्तरों में काम-काज रुक गया है, लोगों को घर से ही काम करना पड़ा है, वेतन में कटौती हुई है, नौकरियाँ छूटी हैं, आर्थिक गतिविधियाँ कम हुई हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को कार्य नहीं मिला है, जिसके कारण लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ है, रोजी-रोटी की चिन्ता दिखाई देने लगी है तथा धन के अभाव के कारण दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण व्यक्ति तनावग्रस्त, चिन्तित व क्रोधित हुआ है और इन सभी आर्थिक कारणों के कारण उत्पन्न हुये तनाव, निराशा व कुण्ठा का शिकार परिवार की महिलाएँ होने लगी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लाकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में 315 घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की गई है। ये सभी शिकायतें आयोग को ऑनलाइन एवम व्हाटसअप के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का

कहना है कि, उनको घरेलू हिंसा की घटनाओं की शिकायतें लाकॅडाउन के दौरान ई मेल के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रही हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएँ लाकॅडाउन के दौरान केवल भारत के किसी एक राज्य में ही नहीं वरन् देश के विभिन्न हिस्सों दिल्ली, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल आदि अनेक राज्यों के देखने को मिली हैं। घरेलू हिंसा की शिकायतें जो व्हाटसअप या ई मेल के माध्यम से भेजी गई हैं, उनमें कुछ शिकायत में तो पति का लॉकडाउन में व्यवसाय खराब होने के कारण महिला के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई है तथा अन्य शिकायतों में लॉकडाउन के कारण पत्नी का अपने माता-पिता के पास न जा पाने की विवशता का लाभ उठाकर परिवार में पति, सास, ससुर के द्वारा शारीरिक रूप से उसके प्रति हिंसा की जाने की घटना प्रकाश में आई है।

इसके अतिरिक्त अन्य शिकायत में एक लड़की के माता-पिता के द्वारा उसके जबरदस्ती विवाह करने की सहमति लड़की के द्वारा न देने का कारण उसके साथ शारीरिक रूप से हिंसा की बात कही गई है, जिसमें पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही करके उस लड़की को आश्रय गृह पहुँचाया है। इस प्रकार लाकॅडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की ऐसी अनेकानेक घटनाएँ घटित हुई हैं जिसमें महिलाओं को गुस्से में आकर पति के द्वारा गाली दी जाती है, थप्पड़ मारा जाता है, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से चोट पहुँचाई जाती है। वैश्विक महामारी के समय जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा एवम अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है उसके लिए आर्थिक कारण के अतिरिक्त कुछ अन्य दशाएँ भी उत्तरदायी हैं। वैश्विक महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, उससे आवागमन काफी बाधित हुआ है जिसके कारण महिलाएँ अपने प्रति होने वाली हिंसा व मारपीट की कहीं शिकायत करने के लिए ना तो जा सकती हैं और न ही अपने मित्रों, रिश्तेदारों एवम् साथियों के पास जाकर अपने सुख-दुख को साझा करने की स्थिति में होती हैं, इसी स्थिति का लाभ उठाकर महिलाओं के साथ परिवार में घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों की प्रवृत्ति मामूली बातों पर चिड़चिड़ा होने, क्रोधित होने व आक्रामकता की होती है, ऐसे व्यक्ति भी लॉकडाउन के समय घरों में कैद होने के कारण पहले से अधिक आक्रामक व क्रोधी हो जाते हैं और महिलाओं को गाली देना, मारपीट करने जैसे घृणित कार्य करते हैं।

यद्यपि महिलाओं को इस प्रकार के लैंगिक असमानता पर आधारित घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, मारपीट व शोषण से मुक्ति दिलाने व संरक्षण देने के लिए “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005” बनाया गया है जो, 26 अक्टूबर 2006 से लागू भी हो गया है, परन्तु महिलाएँ घर में परिवार के सदस्यों के द्वारा मारपीट, उत्पीड़न, हिंसा से पीड़ित होने पर भी न तो कोई शिकायत करती है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही करती है क्योंकि महिलाओं के ऊपर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने, अपने विवाह सम्बन्ध को न तोड़ने, अपने अपमान के भय का पुरुष पर अपनी आर्थिक निर्भरता का, पितृसत्तात्मक सोच का और समाज में अपनी आलोचना न होने का दबाव होना है। जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर भी महिलाएँ अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करके सुरक्षा प्राप्त नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के वैश्विक संक्रमण होने के कारण भी महिलाओं का अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा की शिकायतें करना और कानूनी मदद प्राप्त करना कठिन सा हो गया है। ऐसे कठिन समय में ना तो महिलाएँ शिकायत करने पुलिस के पास जा सकती हैं और न ही समाजसेवी संगठन, कार्यकर्ता या मित्र सम्बन्धी महिलाओं को मदद करने में समर्थ हो पा रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वैश्विक महामारी के इस संक्रमण काल में भारत की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को दर्ज करने के लिए व्हाट्सअप नम्बर लान्च किया है, जिससे महिलाओं को अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त महिला आयोग ने घरेलू हिंसा से सम्बन्धित शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई है। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन भी बनाई है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए विभिन्न राज्यों में पुलिस व प्रशासन ने अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय घर की व्यवस्था भी की गई है।

इसके साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस लाकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए देश भर में 50 हेल्पलाइन नम्बर भी शुरू की गई है। इस प्रकार जब देश की सरकार कोविड - 19 के संक्रमण के कारण देश के

लोगों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अनेक कदम भी गए हैं लेकिन जब तक समाज में घरेलू हिंसा के विरुद्ध जनचेतना नहीं होगी तब तक इस प्रकार की घटनाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी। समाज में जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, वही दूसरी ओर महिलाएं आज भी अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरूक नहीं हैं। जब तक महिलाओं के अन्तःकरण में स्वयं अपने अधिकारों को पहचानने व उनको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति जाग्रत नहीं होगी, तब तक महिलाओं को परिवार में घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, शोषण से आजादी मिलना कठिन है और ऐसे समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना अप्रासांगिक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. फडिया डॉ. बी.एल. और सिंघल, एस.सी.- पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन का इतिहास
2. सिंह, वी.एन. और सिंह जनमेजय- आधुनिकता और नारी सशक्तिकरण
3. महाजन, डॉ. धर्मवीर और महाजन, डॉ. कमलेश - समाजशास्त्र
4. न्यूयार्क टाइम न्यूज सर्विस, लाकडॉउन का साइड इफेक्ट, अमर उजाला, 8 अप्रैल 2020 मेरठ
5. news18.com>india
6. www.hindustantimes.com
7. www.economisttimes.com
8. www.thehindu.com
9. www.amerujala.com
10. www.drishtias.com

कोविड- 19 और आत्मनिर्भर समाज चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ

• डॉ. गंगा देवी बैरागी

कोविड- 19 नामक वायरस से होने वाली बीमारी ने सन् 2020 में पूरी दुनिया को गंभीर क्षति पहुंचायी है। इससे कई देशों में जन- धन की जो हानि हुई, उससे उबरने में कई वर्ष लग जायेंगे। चीन के वुहान से निकलकर, यह वायरस अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाले लोगों के साथ ही, कई देशों में पहुंच गया। हमारा भारत भी इससे अछूता न रह सका और महानगरो में जैसे दिल्ली, बम्बई, इन्दौर, भोपाल आदि में बड़ी मात्रा में लोग इससे संक्रमित होने लगे तथा कई हजार मौते भी हुई। प्रवासी मजदूर इसके डर से, रातों- रात अपने गांव की ओर भूखे प्यासे पलायन करने लगे। भारत सरकार ने त्वरित रूप से लॉकडाउन लगाकर, इस महामारी को फैलने से रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास में भारतीयों की जन हानि तो कम हुई परन्तु आर्थिक रूप से भारत आज भी अपने आप को उबार नहीं सका है। फिर भी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज मध्यम वर्ग और फुटपाथ में रहने वाले व्यक्तियों को देकर, आर्थिक रूप से उबारने का प्रयास किया है और कोविड- 19 रूपी महामारी से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से उबरने का प्रयास सरकार तथा जनता की ओर से निरंतर जारी है।

कोविड- 19 अर्थात् कोरोना एक ऐसा वायरस है, जिसने पूरी दुनिया के साथ - साथ हमारे भारत में भी आकर हमारे सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है और इस वायरस से होने वाली कोरोना नामक बीमारी ने हमारे देश की जनता को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्थिति को गंभीर क्षति पहुँचाई है।

कोरोना अर्थात् कोविड- 19 एक ऐसा वायरस है, जो हमारे शरीर के अंगों जैसे मुँह, नाक के द्वारा दूसरो के सम्पर्क में आने जैसे - छींकने, खाँसने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से फैलता है और यदि इसका

• सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

समय रहते उपचार नहीं किया गया, तो यह फेफड़ों को खराब कर के हृदय को साँस के लिए आक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। अभी तक हमारे भारत में 1,05,12,093 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,51,727 लोग इस बीमारी से अपनी जान गवां चुके हैं। किन्तु राहत भरी खबर यह है कि 1,01,29,111 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। फ्लू जैसे सामान्य लक्षणों वाली यह बीमारी दिन-ब-दिन जानलेवा होती जा रही है। आजकल बिना लक्षणों के (फ्लू) भी कोरोना की रिपोर्ट पाजिटिव आ रही है, जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है। जिससे इस बीमारी को पहचानने में मुश्किल हो रही है। कोविड-19 से जो हमारे समक्ष जीवन जीने की और अपना अस्तित्व बचाए रखने की जो चुनौतियाँ आ पड़ी हैं, वो इस प्रकार हैं -

इस बीमारी से बचाव- इस कोरोना नामक बीमारी से बचने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, तो कैसे हम इस बीमारी से अपने देश के लोगों को बचा सकते हैं, उसके बारे में निम्न सुझाव हैं-

1- कोरोना टेस्ट कराया जाए- ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट राज्य सरकारें कराएँ, तभी हम यह जान पाएँगे कि कौन संक्रमित है अथवा नहीं, तभी हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से अलग रखकर इसके प्रसार को रोकने में कामयाब हो सकेंगे।

2- संक्रमित लोगों की समुचित चिकित्सा हो- संक्रमित व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल में उचित चिकित्सा प्रदान की जाए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ और चिकित्सक उपलब्ध होने अति आवश्यक है।

3- जनता का साथ- जब तक भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में जनता स्वयं इस बीमारी से लड़ने में समर्थ नहीं होगी, तब तक हम इस कोरोना रूपी चुनौती को टक्कर नहीं दे पाएँगे। अतः हम सबको अपना सहयोग सामाजिक दूरी बनाकर मास्क को अनिवार्य मानकर स्वयं को साफ रखकर इस बीमारी को हराने में सरकार का सहयोग करना होगा।

4- चिकित्सकों की उपलब्धता- इस बीमारी के इलाज हेतु आजकल हमारे देश में चिकित्सकों की कमी हो रही है। मेरा सुझाव है कि चिकित्सकीय पढ़ाई कर रहे अन्तिम वर्ष के छात्रों को भी इस महामारी को रोकने हेतु

आधार-भूत प्रशिक्षण देकर हम उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और इस सेवा कार्य के बदले वेतन व प्रशस्ति- पत्र देकर हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे चिकित्सकीय कमी से होने वाली मृत्यु दर को रोका जा सकता है। सरकार कोरोना वायरस से डॉक्टरों की मृत्यु होने पर उनको सरकार द्वारा बीमा उपलब्ध कराया जाये।

5- रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर- हमारा भारत देश औषधियों और आयुर्वेद का एक गौरवशाली इतिहास लिए हुए है। हम आर्युवेदिक जड़ी - बूटियों द्वारा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इस कोरोना वायरस जैसी चुनौती को परास्त कर सकते हैं। योग व प्राणायाम के द्वारा भी हम कोरोना को हरा सकते हैं।

6- वैक्सीन का टीका लगाकर- वर्तमान समय में हमारे भारत में कोरोना नामक की बीमारी से बचाव के लिये वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई है, जिससे भविष्य में कोरोना रूपी महामारी से बचाव के लिये बड़ी मात्रा में टीकाकरण किया जायेगा जिससे हमारा देश और देश के लोगो का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

आर्थिक चुनौती

1- उद्योग- धन्धे बंद होना- कोरोना से होने वाले लॉकडाउन की वजह से छोटे - बड़े सभी उद्योग - धन्धे बन्द हो गए, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी के साथ - साथ राज्य को होने वाली राजस्व रूपी आर्थिक लाभ को भी हानि पहुँचायी है।

2-प्रवासी मजदूरों की समस्या- महानगरों में कोरोना संक्रमण होने तथा लॉकडाउन होने से उद्योग धन्धे बन्द होने के कारण भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाँवों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे उनमें रोजी- रोटी का संकट आन पड़ा है।

3-प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या- ये प्रवासी मजदूर, बेरोजगार हैं, इनके रोजगार और साथ- साथ इलाज की भी चुनौती हमारे सामने है।

समाज को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास और सम्भावनाएँ- हम हमारे समाज को इस कोराना रूपी महामारी से उबारकर कैसे आत्मनिर्भर बनाएँ, इस विषय में मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं-

- हमारा प्राचीन भारतीय समाज आत्मनिर्भर था। जैसे खाद्यान्न

आदि तथा कृषि कार्य द्वारा वस्त्र रूई से चरखे द्वारा बनाए जाते थे। तेल आदि भी गाँवों में निकाला जाता था। दूध, फल आदि सभी सुविधाएँ जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, ये गाँवों में ही थीं। इस प्रकार हम पुरानी पद्धति अपनाकर गाँवों के लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करके गाँवों को और अपने समाज को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

- सरकार द्वारा समाज को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे समाज के लोगों का आर्थिक जीवन सुदृढ़ हो। हमारी सरकार द्वारा यह प्रयास भी जारी है।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर और सुरक्षित रहकर स्वास्थ्य और दीर्घायु रहे। हम सब स्वस्थ होंगे तथा समाज को आत्मनिर्भर बनाएँगे तभी विकास के पथ पर अग्रसर होंगे।
- समाज को आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमें स्वयं उत्पादक तथा उपभोक्ता बनना होगा। जैसी हमारी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति रही है। तभी हम एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर, कोरोना रूपी बीमारी नामक चुनौती से उबर पाएँगे।
- प्रवासी मजदूरों को अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाये ताकि उनकी रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके।

कोरोना से उबरने हेतु संभावनाएँ -

- सामाजिक दूरी और मास्क को अपनी नियमित दिनचर्या के साथ शामिल करके, हम अपने काम में जुट जाएँ।
- दफ्तर, स्कूलों में सेनेटराइज की व्यवस्था हो तथा जाँच उपकरणों द्वारा वहाँ आने वालों पर निगरानी, हो ऐसे ही अब हमारा आगे का जीवन होगा। यह सोचकर हम हर कार्य सम्पादित करें।
- वर्तमान समय में हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, जिससे हम सबको इसका टीका लगाए जाने की तैयारी हो रही है, जिससे हम कोरोना रूपी महामारी से उबरने में कामयाब हो सकेंगे।
- कोरोना का स्थायी इलाज सरकार द्वारा लगाया जाने वाला लॉकडाउन नहीं है। इससे हमारे देश को अत्याधिक आर्थिक क्षति

उठानी पड़ी है। अतः हमें इससे लड़ने को तैयार होकर उद्योग धन्धो आदि को प्रारम्भ करना होगा।

मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रयासों द्वारा हम अपने समाज को कोरोना रूपी चक्रव्यूह से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नया कदम बढ़ाएँगे।

कोविड और सतत् विकास लक्ष्य

•डॉ. विनोद शंकर सिंह

•• सिद्धार्थ मिश्र

सतत् विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। “ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट” के संकल्प को, जिसे सतत् विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया था और इसे एक जनवरी 2016 को लागू किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा अपने यहां परिस्थितियों के मुताबिक लॉकडाउन को लागू किया गया ताकि कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लॉकडाउन ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा पहुंचायी है। संधारणीय भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता योगदान के तहत लक्ष्यों और संकल्पों की अनदेखी किये बिना, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और निर्णयों के सही विकल्पों के चुनाव के लिए सभी प्रमुख पक्षों का आह्वान करती है ताकि विश्व समुदाय बहुत आवश्यक परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर सके।

धरती के पास हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती, महात्मा गांधी की इस अभिव्यक्ति में निहित ज्ञान, ब्रंटलैड आयोग से बहुत पहले आया था, जिसे सतत् विकास की एक आधिकारिक तौर पर सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य परिभाषा का श्रेय दिया गया है। इस आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र में 1983 में किया था, जिसने 1987 में अपनी

-
- एसोसिएट प्रोफेसर (समाजकार्य), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट सतना (म.प्र.)
 - शोध छात्र (समाजकार्य, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट सतना (म.प्र.)

रिपोर्ट-हमारा सामान्य भविष्य प्रकाशित की थी। इसमें सतत विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान विकास की जरूरतों को पूरा करने वाला विकास परिभाषित किया गया था।

ब्रंटलैंड आयोग (1983-87 के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल रूप से पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के रूप में गठित) ने भी सतत विकास को परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार के उपायों से संसाधनों के दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास के उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन के प्रयासों में पूरे तालमेल से मानव आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के ये प्रयास 16वीं सदी के बाद की शताब्दियों के दौरान विचारकों की चिंताओं और सुधार के काम में उनके योगदान की परिणति थी। 1970 से आगे के दशकों को, स्थिरता, के मुद्दों को चर्चा में लाने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वास्तव में विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुतायत अन्तर-सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय सरकारों का सक्रिय समर्थन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।¹

सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो सतत विकास का अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता है और पौराणिक, गाथाओं, लोककथाओं, धर्मों, कलाओं और संस्कृति में वर्णित है। 'ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड : द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट' के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठकों में स्वीकार किया गया था और इसे एक जनवरी 2016 को लागू किया गया।²

सतत विकास लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यवाही प्रेरित करेंगे-गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और

खुशहाली, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी। इस समग्र एजेंडा में माना गया है कि अब केवल आर्थिक वृद्धि पर फोकस करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और अधिक समतामूलक समाज तथा अधिक संरक्षित एवं अधिक संपन्न पृथ्वी पर फोकस करना होगा। इसमें माना गया है कि शांति, न्याय, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के कार्य एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी परिवर्तन के अंग हैं। इसमें सबसे अधिक मान्यता इस बात की है कि वैश्विक और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए केवल वैश्विक और परस्पर जुड़े समाधानों की ही आवश्यकता है।³

सतत् विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, समूची दुनिया द्वारा सामाजिक-पर्यावरणीय-आर्थिक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के इरादे का पोषण करते हैं और विभिन्न सदस्य देशों में शांति तथा साझेदारी बढ़ाना सुनिश्चित करते हुए अपने कार्यों में तेजी लाकर जलवायु संकट से निपटने और संधारणीय भविष्य के लिए अपने निवेश को बढ़ाते हैं। सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति सतत विकास के अभियान ने 3 पी (पीपल-प्लेनेट-प्रॉफिट) और तीन आर (रिड्यूस-रीयूज-रीसाइकल) के अलावा और आयामों (शांति-साझेदारी) के समावेश को देखा है, जिसका उद्देश्य जलवायु संकट से प्रभावी रूप से और अधिक आयामों (रिकवर-रीडिजाइन-रिमैन्युफैक्चर-रीथिक-रिफ्यूज-रिप्लेस-रीपरपज) का समर्थन प्राप्त करना है। इनके अलावा एक और आर यानी रीज्वॉयस (पूर्ण आनंद) को भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों की समस्याओं को कम करने, समाधानों की उपयुक्तता बढ़ाने और स्थाई तरीके से विकास को प्राप्त करने के लिए इसे दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया।

जलवायु परिवर्तन के समाधान का अर्थ है, उचित समय पर उचित जलवायु कार्यवाही करना। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप यूएनएफसीसीसी को सदस्य देशों द्वारा शमन और अनुकूलन कार्यों सहित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने कार्यों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली

जलवायु योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु परिवर्तन का, सतत विकास लक्ष्यों से महत्वपूर्ण संबंध है, जो न केवल सतत विकास लक्ष्य 13 प्रतिशत जलवायु कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से अपने महत्व को पहचानता है, बल्कि भविष्य में इसके गंभीर रूप लेने की आशंका के कारण इसे सतत विकास के लिए बड़ा खतरा मानते हुए सभी सतत विकास लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए परोक्ष रूप से विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भी कृतसंकल्प है। जलवायु परिवर्तन के खतरों में शामिल है-विकास के लाभ कम होना, आगे की प्रगति में बाधा, कमजोर लोगों की आय तथा अवसरों में कमी, समुद्र का स्तर बढ़ना, वर्षा तथा सूखे के स्वरूप में बदलाव, समुद्र का अम्लीकरण, प्राकृतिक खतरों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ना, पानी की उपलब्धता और पहुंच का कम होना, खाद्य सुरक्षा की कमी, प्रवासन को बढ़ाना, आजीविका का कम होना, स्वास्थ्य में गिरावट, बुनियादी ढांचे को नुकसान और कई अन्य।⁴

कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा अपने यहां परिस्थितियों के मुताबिक लॉकडाउन को लागू किया गया ताकि कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लॉकडाउन ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में बाधा पहुंचायी है। इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में सतत विकास पर वर्चुअल हाइ लेवल पॉलिटिकल फोरम ने विभिन्न देशों की सरकारों और अन्य हितधारकों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने हेतु और अधिक प्रभावी नीतियों के निर्माण पर बल प्रदान किया है।⁵

दुनिया भर के देशों ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक ब्लू प्रिन्ट तैयार किया है, जिससे गरीबी हटाई जा सके और धरती व पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया है। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गयी थी। सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। महामारी के संकट से पहले ही दुनिया लक्ष्यों को हासिल करने में पिछड़ रही थी। अब स्थिति और बुरी होने वाली है।

एंटोनिया गुटरेस ने “प्रोग्रेस टुवार्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020” रिपोर्ट में कहा है कि भूखे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है,

जलवायु परिवर्तन अनुमान से तेज हो रहा है और आय की असमानता भी बढ़ रही है। उनका कहना है कि महामारी का असर और इसे कम करने के लिए किए गए उपायों ने दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र पर भार बढ़ा दिया है। इस महामारी ने व्यापार और फैक्टरियों को बंद कर दिया है और दुनिया के आधे श्रम बल की जिंदगी को प्रभावित किया है। इस महामारी ने सतत् विकास के लक्ष्यों की प्रगति की ओर धीमा कर दिया है। वर्तमान महामारी ने वैश्विक व्यवस्था की मूलभूत कमजोरियों को उजागर कर दिया है और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ तत्काल कार्यवाही पर बल दिया है और यह हमारे जीवन का सबसे बुरा मानवीय और आर्थिक संकट है।⁶

ऐसे समय में जब कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य आपात स्थिति ने इस सदी के सबसे खराब आर्थिक परिदृश्य की भविष्यवाणी की है, तब सही नीतिगत क्रियाएं जलवायु संकट के गहराने से उत्पन्न किसी भी जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा संकट की इस घड़ी ने हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों में फिर से समरसता लाने और परिभाषित करने का अवसर दिया है। मौजूदा स्थितियों में सरकारों को जलवायु के अधिक अनुकूल गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कोविड-19 के दौरान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दर्शाने वाला कॉरपोरेट क्षेत्र कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, जीवन चक्र आंकलन, जलवायु कार्यनीति की अति सक्रियता, चक्रीय अर्थव्यवस्था का अधिकतम उपयोग जारी रख सकता है और उसे इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।⁷

आर्थिक सुधार के लिए कोविड के समय में आत्मनिर्भर और लोकल के लिए वोकल को, कोविड के बाद के समय में प्रभावी रूप से जारी रखने से संभवतः जलवायु संकट से निपटा जा सकता है। कोविड-19 ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित करने के साथ पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया को बदल दिया है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग शिक्षा-प्रशिक्षण जागरूकता प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह मुक्त शिक्षा संसाधनों बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम पोर्टल, पॉडकास्टिंग, ई-लाइब्रेरी और सोशल मीडिया सामग्री को उचित रूप से उपयोग करने के लिए संरक्षित कर सकता है। वांछित गति और पैमाने की प्राप्त करने के लिए

प्रभावी और कुशल संयोजन पर जोर देने में सफल रहे इग्नू जैसे संस्थान प्रमुख मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के उपयोग में मदद कर सकते हैं।

यह सच है कि कोविड-19 के कारण भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इससे महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं की प्रक्रिया में अवरोध आ सकता है लेकिन हमें निराशावादी होने के बजाय कोविड-19 के अनुभवों का उपयोग सहयोग तथा बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से उबरने के लिए करते हुए स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हरित निर्माण और उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में करना चाहिए। कोविड-19 युग ने वैश्विक निहितार्थों के साथ सहयोग का उल्लेखनीय उदाहरण भी देखा है जो जलवायु संकट से निपटने में सहायक होगा। बहरहाल मुश्किल की यह घड़ी, संधारणीय भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता योगदान के तहत लक्ष्यों और संकल्पों की अनदेखी किए बिना, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और निर्णयों के सही विकल्पों के चुनाव के लिए सभी प्रमुख पक्षों का आह्वान करती है, ताकि विश्व समुदाय बहुत आवश्यक परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. योजना, नवम्बर 2020, पृ. 52-53।
2. Sustainable Development from amarujala .com
3. In.on.un.org.sustainable-Development.
4. योजना, नवम्बर 2020, पृ. 54
5. Dhyeyaias.com कोविड&19 महामारी
6. www.downtoearth.org.in.sustainable-Development
7. योजना, नवम्बर 2020 पृ. 56

पर्यावरण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव

• डॉ. नीलम श्रीवास्तव

सभ्यता के विकास से वर्तमान युग तक मानव ने जो प्रगति है, उसमें पर्यावरण की महती भूमिका है और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास मानव पर्यावरण समानुकूलन एवं सामंजस्य का परिणाम है। यही कारण है कि अनेक प्राचीन सभ्यतायें प्रतिकूल पर्यावरण के कारण पतन के गर्त में समा गईं तथा अनेक जीवों तथा पादप समूहों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं और अनेकों पर यह संकट गहराता जा रहा है। इतिहास कई ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जो यह साबित करता है कि महामारियों का गहरा प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ा है। कोविड-19 भी ऐसी ही महामारी का एक भयावह रूप है। कोविड-19 ने जहां एक ओर दुनिया भर में कई विकट चुनौतियां पैदा की हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के अदभुत-नजारे भी देखने को मिले हैं। कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक भी, जिनका कि प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है।

प्रस्तावना- पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े-मकोड़े, सभी जीव-जन्तु और पेड़-पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं संघटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रतिक्रियाएं आती हैं, जैसे-पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, इसी पर निर्भर करती है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। कहा जा सकता है कि पर्यावरण और जीवका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है।

पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ- 'पर्यावरण' शब्द का निर्माण दो शब्दों 'परि' और 'आवरण' से मिलकर हुआ है। जिसमें 'परि' का तात्पर्य हमारे

• असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग (बी.एड.), डी.बी.एस. कालेज, कानपुर

आस-पास या हमारे चारों ओर और 'आवरण' 'जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है' अर्थात् 'पर्यावरण' उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रिय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप जीवन, जीविका को तय करते हैं।

डेविस के अनुसार, "पर्यावरण से तात्पर्य भूतल पर मनुष्यों के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक रूपों से है जिनसे वह निरन्तर प्रभावित होता रहता है।" विगत कुछ माह से हमारी दुनिया एकदम बदल गई। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े। सब पर कोरोना वायरस (कोविड-19) का कहर टूटा, जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे उनका रहन-सहन भी बिल्कुल बदल गया। ये वायरस दिसम्बर-2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया, उसके बाद दुनिया में सब कुछ उलट-पलट हो गया। शुरूआत वुहान शहर से हुई जहाँ पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में बड़ी तादाद में इस वायरस से लोग मरे, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सब कुछ बंद करना पड़ा, लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए, दुनियां भर में उड़ाने रद्द कर दी गई, भारत में आवागमन के समस्त साधनों पर रोक लगी और अनेको संबंध सोशल डिस्टेंसिंग का शिकार हो गए। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया।

ये सब कदम इसलिये उठाए गए कि नये कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसकी किसी को उम्मीद भी न थी। इससे पर्यावरण पर अनेकों बदलाव भी देखने को मिले कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। 31 मई 2020 तक इस वायरस से 200 से ज्यादा देश और इलाके प्रभावित हुए। कोविड-19 महामारी जून 2020 तक पूरी दुनिया के लिये परेशानी का सबब बन गई। आज कोरोना वायरस से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को तथा मानव, प्रकृति और आर्थिक विकास के अंतर्संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध-पत्र के द्वारा हम पर्यावरण पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करेंगे।

प्रस्तुत शोध कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'वर्णनात्मक' एवं 'सर्वेक्षण विधि' का आश्रय लिया गया है।

पर्यावरण पर कोविड-19 का प्रभाव- कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में व्यवधान के परिणामस्वरूप पर्यावरण और जलवायु पर कई प्रभाव पड़े। नए कोरोना वायरस ने दुनिया के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में लिया। इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी दृष्टिगोचर हुआ। पर्यावरण पर इसके प्रभावों को हम दो वर्गों में विभक्त कर समझ सकते हैं-

- कोविड-19 के सकारात्मक प्रभाव
- कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव

पर्यावरण पर कोविड-19 के सकारात्मक प्रभाव- पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव निम्न प्रकार से देखा गया।

- यात्रा और उद्योग पर कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों और ग्रहों ने वायु प्रदूषण में गिरावट का अनुभव किया।
- दुनिया के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर मार्च एवं अप्रैल में नाटकीय रूप से बेहतर हुआ।
- लगभग समस्त देशों में सड़क उपयोग में गिरावट के कारण तेल के उपयोग में भारी गिरावट आई।
- वैश्विक कार्बन-डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 10 साल पहले के स्तर से 8 प्रतिशत या लगभग 2.6 गीगाटन तक गिरावट की सम्भावना।
- प्रदूषण में भारी कटौती हुई।
- प्रदूषण स्तर में कमी के कारण कई उत्तर भारतीय राज्यों से हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देने लगीं।
- प्रदूषण के प्रमुख औद्योगिक स्रोत जो जलीय परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करते हैं जैसे-औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, कच्चे तेल, भारी धातुएं और प्लास्टिक कम हो गए या पूर्णरूपेण बंद हो गए।
- गंगा, यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लॉकडाउन के मध्य देखने को मिला।
- कम पर्यटक, मोटर वोट, नहरें साफ हो गई जिससे पानी वाले जलीय जीव साफ दिखाई देने लगे।
- कोरोना वायरस लॉकडाउन ने मानवीय क्षति से प्रकृति को उबरने में मदद की।
- लॉकडाउन में सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं को बंद करने से

शोर का स्तर गिर गया।

- जहाज यातायात और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में कमी के कारण समुद्री जीवों ने महासागरों में स्वतंत्र रूप से घूमना शुरू कर दिया।
- भूकम्प गतिविधियों का पता लगाने वाले उपकरण अधिक सटीकता से काम करने लगे।
- लॉकडाउन के नियमों से हवा, सौर, जल, विद्युत और परमाणु बिजली के स्रोतों की ओर अग्रसर होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला।
- पूर्ण लॉकडाउन से देशों में ऊर्जा की मांग में औसतन 25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
- पानी की गुणवत्ता में 40-50 प्रतिशत का सुधार हुआ।

पर्यावरण पर कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव- कोरोना वायरस या कोविड-19 के सभी प्रभाव सकारात्मक ही नहीं रहे। इसके कुछ प्रभाव नकारात्मक भी दिखे-

- पर्यावरण संरक्षण श्रमिकों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अवैध वनों की कटाई, मछली पकड़ने और वन्य जीवों के शिकार में वृद्धि हुई।
- कई देशों में प्राकृतिक परिस्थिति की प्रणालियों के रख-रखाव और निगरानी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।
- पर्यावरण पर्यटन गतिविधि के ठहराव ने अवैध कटाई और अतिक्रमण के खतरे का बढ़ा दिया।
- स्थानीय समस्याएँ उभर कर सामने आईं।
- छोड़े हुए पी.पी.ई. किट, पहने मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर बोतलों से मेडिकल कचरे में वृद्धि हुई।
- एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में वृद्धि का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।
- चीन आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिये पर्यावरण नियमों को अस्थायी रूप से निलम्बित कर रहा है।
- अमेरिका वाहन उत्सर्जन मानकों और वायु गुणवत्ता रिपोर्टिंग मानकों में उल्लेखनीय रूप से कमी लाया है।

निष्कर्ष- आज कोविड-19 जैसी महामारी और पर्यावरणीय विसंगतियों

को दूर करने के लिये आर्थिक स्तर पर मूलभूत संरचनात्मक बदलाव लाने होंगे। कोविड-19 ने हमें यह अवसर दिया कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय राजनीति को परिस्थितिकी सम्मान और न्याय के तर्ज पर फिर से परिभाषित किया जाय। स्थानीय सेवाओं और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक संस्थाओं में सहयोग और निवेश को भी मजबूत किया जाना आवश्यक है। आज वर्तमान स्थिति को प्रकृति की ओर से दी जाने वाली चेतावनी समझनी चाहिये जो मनुष्य की जीवन-शैली और विकास प्रक्रिया के तौर-तरीकों को बदलने का अवसर प्रदान करती है।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि आज जब पूरी दुनियाँ पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के लिये उपयुक्त नीतियों के बारे में चिंतित है, तब यह वैश्विक महामारी (कोविड-19) एक निरपेक्ष रास्ता दिखाती है कि पर्यावरण को हुए नुकसान को कैसे कम किया जाय। कोविड-19 के फैलाने और दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति का विश्व अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है लेकिन हमारे पर्यावरण को भारी मानवजनित दबाव से राहत पहुंची है। आज सतत विकास लक्ष्यों के बारे में एक दीर्घकालिक विचार करने की आवश्यकता है। तमाम आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाने पर कोविड-19 संकट के कारण जो सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है वे फिर से पहले की अवस्था में चले जायेंगे।

आज न केवल हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय नवीनीकरण से जुड़े कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है बल्कि व्यक्तिगत, कानूनी व प्रबंधकीय स्तर पर भी परिस्थितिकी प्रबन्धन व संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इन तमाम प्रयासों, नवाचारों, पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत राजनीतिक, इच्छाशक्ति के सहारे हम इस संकट से उबरने में कामयाब हो सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- Shahanawaj. (199-). Environmental Awareness & Attitude, Surya Publications, Meerut, P.P. -67.
- Sapru, R.K. (1987). Environmental Management in India, Ashish Publishing House, New Delhi.

- वशिष्ठ, कमला, पर्यावरण शिक्षण, मैसर्स यूनीवर्सिटी बुक हाउस, प्रथम संस्करण, 2006
- Dassaman, R.D. (1976). Environmental Conservation, Wiley, New York.
- सिंह, एम.एन. एण्ड एल. प्रहलाद. (1981). सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन, N.C.E.R.T., नई दिल्ली, Pp-1-7.
- Rana, A.J. (1989). Evaluation of Environmental Studies, New Indian Publication, New Delhi, Pp-267
- Kothari, D.S. (1964-66). Indian Education Commission, 1964-66, N.C.E.R.T., New Delhi.
- N.C.E.R.T. (1997). Fifth Survey of Educational Research – 1988 – 92.
- पाठक, बिंदेश्वर, स्वच्छता का समाजशास्त्र (पर्यावरणीय स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और सामाजिक उपेक्षा), इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली (2009).
- Arvill, R. (1967). Man and Environment, Penguin, Hamondsworth.

कोरोना-19 महामारी का महिलाओं तथा बच्चों पर प्रभाव

• डॉ. आशा गोहे

वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार ने वैश्विक आबादी को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चल रही समस्त मानवीय गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर संपूर्ण लॉकडाउन को अपना लिया गया है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन का एकमात्र उद्देश्य अमूल्य मानवीय जीवन की रक्षा करना है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में यह एक प्रभावकारी उपाय साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस वैश्विक संकट के दौर में भी महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू हिंसा की वैश्विक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ऐसे हालात में महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में भयावह बढ़ती दर्ज किये जाने पर चिंता जताते हुये सरकारों से ठोस कार्यवाही का आह्वान किया, प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से कोरोनाकाल में महिलाओं और बच्चों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है यही जानने का प्रयास किया गया है

कोविड-19 ने समूची मानव जाति के जीवन को पलट कर रख दिया है, बिल गेट्स जैसे दूरदर्शियों को छोड़ दे तो पूरी दुनिया ने कभी भी यह कल्पना नहीं की होगी कि दुनिया को थाम देने वाली महामारी आएगी, इस कोविड-19 महामारी का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सभी पहलुओं पर प्रभाव दिखाई देता है, वहीं समाज का हर वर्ग इस महामारी से प्रभावित हुआ। इतिहास के कालखण्डों में कुछ साल ऐसे रहे हैं, जब भीषण युद्ध या बड़ी आपदा के चलते संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही जैसे दाँव पर लग गया। उन वर्षों की फेहरिस्त में 2020 को दर्ज जरूर किया जाएगा। एक ऐसा साल जिसने संपूर्ण मानव जाति को एक खतरनाक

• विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, शासकीय जटा.त्रि.स्ना.महा.बालाघाट

अनजान शत्रु से एकजुट होकर लड़ना, चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होना सिखाया। इस कोरोना काल ने महिलाओं और बच्चों पर क्या प्रभाव डाला प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। कोरोना काल और लॉकडाउन ने जिस तरह लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर किया, उससे कई तरह की सामाजिक विसंगतियां और घरेलू हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले या जेंडर बेस्ड क्राइम की घटनाएं पिछले सालों के मुकाबले पिछले दस महीनों में 24 फीसदी बढ़ गई हैं। वहीं बाल-विवाह के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, विश्व के अलग-अलग हिस्सों में कई देशों में कोविड-19 की वजह से लागू की गई तालाबंदी के कारण घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हिंसा करने वालों के साथ ही फंस गई हैं। चाहे अमेरिका हो या इंग्लैण्ड, फ्रांस हो या स्पेन यह समस्या हर जगह है।

एक उदाहरण मिलता है कि फ्रांस ने कोविड-19 से लड़ाई के बीच घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं पर भी अलग से ध्यान देना शुरू कर दिया है और उन्हें उनके प्रति हिंसा करने वालों से दूर हटाने में 20,000 कमरों की व्यवस्था करनी पड़ी थी। कोरोना काल में बाहर आने-जाने में रोक और लॉकडाउन जैसी स्थितियों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध और जेंडर बेस्ड हिंसा के 25607 मामले दर्ज किए गए। पॉली समाज नाम की संस्था से जुटाए गए, आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पिछले सालों की तुलना में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महिलाओं के हकों के लिए काम करने वाली यह संस्था बांग्लादेश के 64 में से 54 जिलों में सक्रिय है, इसके मुताबिक बाल-विवाह के मामलों इस दौरान 72 फीसदी बढ़े हैं। यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब कोरोना अपने चरम पर था, उस दौरान यानी 2020 की तीसरी तिमाही में बाल विवाह के मामले पहली तिमाही की तुलना में 571 फीसदी बढ़ गए, जबकि 2019 की तुलना में इस दौरान बाल-विवाह 219 फीसदी बढ़ गया। बांग्लादेश में 15 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी को बाल-विवाह की श्रेणी में रखा जाता है।

भारत की हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि जिसे दिन से तालाबंदी शुरू हुई है, उस दिन से घरेलू हिंसा के मामले

लगातार बढ़ रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि 24 मार्च से लेकर अभी तक उन्हें घरेलू हिंसा की शिकायत करते हुए 69 ईमेल आये हैं और यह आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। रेखा शर्मा का कहना है कि असली आँकड़ा इससे में ज्यादा होगा, क्योंकि आयोग को अधिकतर शिकायतें ई-मेल से नहीं बल्कि डाक के जरिये आती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि जिस दिन से तालाबंदी शुरू हुई उस दिन से घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पीड़ित महिलाएं शिकायत कर रही हैं, अगर उन्हें तालाबंदी से पहले थोड़ा समय मिल जाता तो कहीं और चली जाती। देश ने पहले देखा कि कैसे भूखे मर जाने के डर से प्रवासी श्रमिक अपने-अपने गृह राज्य लौट जाने के लिए तालाबंदी के बीच पैदल ही निकल पड़े, फिर खबरे मिल रही थी कि कैसे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए तालाबंदी अभिशाप बन गई है।

कोरोना काल में राजधानी दिल्ली में जहां अपराध का ग्राफ गिरा तो वहीं महिलाओं के प्रति अपराध में भी कमी आई। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से महिलाओं की मूवमेंट बेहद कम हो गई। ऑफिस व दूसरे संस्थान बंद हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी पाबंदी रही, ऐसे में यहां महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों में कमी पाई गई। लेकिन भारत के कई अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध जारी रहे। ताजा घटनाएं यू.पी. के अलीगढ़ और राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई। सवाई माधोपुर में क्वारंटीन में रह रही महिला के साथ गैंगरेप हुआ, लॉकडाउन की वजह से क्वारंटीन में रूकी एक महिला से सरकारी स्कूल परिसर में ही सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। देश में 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक पाँच राज्यों की 30 फीसदी से अधिक महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। एन. एफ. एच. एस. के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे बुरा हाल कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाणा और बिहार में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर ऐसी घटनाओं में वृद्धि की आशंका जताई है। इस सर्वेक्षण में देशभर के 6.1 लाख घरों को शामिल किया गया। इसमें साक्षात्कार के जरिये आबादी, स्वास्थ्य परिवार नियोजन और पोषण संबंधी

मानकों के संबंध में सूचनाये इकट्ठा की गई। एन. एफ. एच. एस. -5 सर्वेक्षण के मुताबिक कर्नाटक में 18 से 49 आयु वर्ग की करीब 444 फीसदी महिलाओं को अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। जबकि 2015-16 के सर्वेक्षण के दौरान राज्य में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 20.6 फीसदी थी। लॉकडाउन में बाहर सब कुछ बंद था तो, सबको घर पर ही रहने की मजबूरी थी। इस समय घर में मां या पत्नी केन्द्र बिंदु हो जाती है। महिलाओं की भूमिका कोविड -19 के दौरान एकदम बदल गई है। हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी में जहाँ ज्यादातर पतियों को हुक्म चलाने और अधिकार जताने की आदत रही है। लॉकडाउन ने महिलाओं के काम के बोझ को बहुत हद तक बढ़ा दिया है। बच्चों को सभालों, बुर्जुगों की देखभाल करो, हाउस हेल्प और काम करने वाली बाईयों के न आने से घर का हर काम का बोझ महिलाओं पर आ गया है।

ऑफिस जाने वाली महिलाओं को दफ्तर का काम भी लैपटाप से घर से ही करना है, इस कोरोना संकट ने महिलाओं ने इन सारे काम के बावजूद अपने लाभ में भी परिवर्तन किया है, जिनको शादी के बाद खाना बनाना नहीं आता था, वो आज कोरोना काल में खाना बनाना सीख रही हैं। महिलाओं का काम चाहे बढ़ गया हो पर वे नये-नये काम सीखने की कोशिश कर रही हैं। इस आपाधापी में भी घंटाभर थोड़ा व्यायाम के लिए समय निकाल रही हैं और नई-नई रेसिपी भी सीख रही हैं। कई महिलाएं कथक, संगीत, पब्लिक स्पीकिंग की ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, बच्चों को भी कुछ अच्छे ऑनलाइन कोर्स करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार आज कोरोना संकट के समय जो लोग मेडिकल में काम कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर महिलाएं ही हैं, जो फ्रन्ट लाइन में खड़ी हैं, सामान्य दिनों में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में किसी भी संकट में ज्यादा सतर्क और सक्रिय होती हैं। बेहतर प्रबंधन और बुरे हालात में भी बड़ी हिम्मत से परिवार और समाज को संभाले रहती हैं, ये बात अलग है कि जब संकट नहीं रहता है, तब वे परिवार और समाज दोनों में ही फिर से उपेक्षित हो जाती हैं। कोरोना के इस संकट में उन्होंने कई अतिरिक्त जिम्मेदारियों को निभाया था।

मध्यप्रदेश पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से दिसम्बर के बीच कुल 7 हजार युवतियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी,

लापता 7 हजार युवतियों में से पुलिस ने करीब 4 हजार की तलाश की है, जबकि 3 हजार का सुराग नहीं मिला है, इतनी बड़ी संख्या में बालिकाओं का लापता होना अत्यंत चिंता का विषय है। यदि हम विदेशों की बात करें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सर्वे के मुताबिक 50 प्रतिशत उच्च आय वाले देशों में यू.के. का 24वां स्थान है और यहां 18 से 34 साल की उम्र के 50 से 60 फीसदी युवाओं ने परिवार आगे बढ़ाने की योजना को एक साल के लिए टाल दिया है, उनका मानना है कि जब अनिश्चितता का माहौल है, तब वे तनाव काल में परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में यहां महिलाओं में पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर की समस्या भी तेजी से बढ़ी है, महिलाएं चिंतित होने से डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, तनाव लेने वाली महिलाओं के बच्चों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की आशंका 10 गुना तक बढ़ जाती है।

कोरोना के चलते कामवालियों और ऐसे दूसरे हेल्परों की गैर मौजूदगी ने महिलाओं की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों के लिए तीन महीने तक पाँच सौ रूपये की नगद सहायता के अलावा कई अन्य उपायों का ऐलान किया है। लेकिन महिला संगठनों की राय में यह काफी नहीं है। एक महिला संगठन की प्रमुख जानकी नारायण कहती हैं, लॉकडाउन का महिलाओं पर गंभीर असर होगा देश के ग्रामीण इलाकों के पुरुष सदस्य कामाने के लिए बाहरी राज्यों में जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके वापस नहीं लौट पाने के कारण परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की देखरेख और खानपान की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होगी। महिलाओं को खेतों में भी काम करना पड़ता है, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर हो सकता है देश की महिलाओं की बड़ी आबादी पहले से ही कुपोषण की शिकार रही है। महिला कार्यकर्ता सुचित्रा कर्मकार कहती हैं युद्ध या दैवीय आपदाओं में महिलाओं को ही सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव, शहर, गृहणी या कामकाजी कोई भी महिला इससे सुरक्षित नहीं हैं सरकार को इस आधी आबादी की सेहत और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

कोरोना वायरस एक त्रासदी है, जिससे पूरा समाज मौजूदा वक्त में जूझ में रहा है। समाज का शायद ही कोई वर्ग हो तो इसके प्रभाव से अभी अछूता होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया इस पूरी त्रासदी में सबसे ज्यादा

प्रभावित हुई है, जिसके कारण समाज में कई तरह की उथल-पुथल हुई है, लेकिन इस त्रासदी से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित है तो वो है वरिष्ठ नागरिक और बच्चे।

बच्चे जिनको प्रारंभिक अवस्था में एक उन्मुक्त और गतिशील वातावरण की आवश्यकता होती है, वह घर की चारदीवारी में कैद हो गये हैं। पहले लग रहा था, यह त्रासदी कुछ समय के लिए है, मगर अब लग रहा है बच्चों का एक लंबा अरसा घर की दीवारों के बीच बीतेगा, जो बचपन जमाने की तमाम दुश्वारियों से बेखौफ पाकों और आसपास घूमता था, उस पर कोविड-19 का पहरा लग गया है। जब कोविड का प्रकोप शुरू ही हुआ था, तो उसी समय स्कूल बंद हो गये फिर ऑनलाइन कक्षाओं का दौर चालू हुआ। घरों में कैद बच्चे, वैसे भी कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबावों से जूझ रहे हैं। उस पर इन बच्चों को स्कूल की पोशाक पहनाकर स्क्रीन के सामने 5 घण्टे बैठाना एक अमानवीय कृत्य है।

इस वायरस की वजह से मानसिक समस्याएँ भी बच्चों में देखने को मिल रही हैं। लॉकडाउन के बीच बच्चों और अंडर 25 युवाओं के बीच अजीब समस्याएं नजर आ रही हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है तो किसी की नींद संक्रमण के खौफ से टूट रही है। कई बच्चे नकारात्मक विचारों से घिर रहे हैं वहीं कैरियर को लेकर भी युवा चिंतित हैं। किशोर क्लिनिक में काउंसलर डॉ. दिव्या दुबे मिश्रा के अनुसार पहली बार ऐसा है कि लोग इतने लंबे समय तक घरों पर रह रहे हैं, टेलीफोनिक काउंसलिंग के दौरान बच्चों का पहला रिएक्शन यही होता है कि वे खुद को कैद में महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिनचर्या बिगड़ी तो उनकी सोच नकारात्मक होने लगी। हर समय संक्रमण की बात हो रही है। यहां तक कि बच्चे अपने आसपास के एरिया में संक्रमित मरीजों को भी गूगल पर सर्च कर रहे हैं। बच्चों के लिए डर की स्थिति घातक है। इससे बचाव को लेकर घर के अभिभावकों को ध्यान देना होगा। विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस के 9 में 1 मामला 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों से संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 नवम्बर 2020 तक 87 देश में आये 25.7 मिलियन संक्रमण के मामलों में से 11 प्रतिशत मामले बच्चों और किशोरों से संबंधित हैं। रिपोर्ट में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार कोरोना

वायरस संक्रमण के कारण विश्व के लगभग एक तिहाई देशों में नियमित टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में तकरीबन 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। विश्व के 135 देशों में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सेवाओं के कवरेज में 40 प्रतिशत की गिरावट है जिसका दीर्घकाल में खतरनाक परिणाम हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण वर्ष 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के 6 से 7 मिलियन से अधिक बच्चे वेस्टिंग (Wasting) और कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं, इसका सर्वाधिक प्रभाव सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में देखने को मिल सकता है। अप्रैल माह 2020 के अंत में जब विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लागू किया गया तो विद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिसके कारण विश्व के लगभग 90 प्रतिशत छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी और विश्व के लगभग 1.5 बिलियन से अधिक स्कूली छात्र प्रभावित हुए थे।

कोरोना वायरस के कारण शिक्षा में आई इस बाधा का सबसे अधिक प्रभाव गरीब छात्रों पर देखने को मिला है और अधिकांश छात्र ऑनलाइन शिक्षा के माध्यमों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण कई छात्रों विशेषकर छात्राओं के वापस स्कूल न जाने की संभावना बढ़ गई है। कई छात्रों को तो पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी के काम में लगा दिया गया कई बच्चे नशे की प्रवृत्ति में लिप्त पाये गये। लॉकडाउन और स्कूल बंद होने से बच्चों के विरुद्ध लैंगिक हिंसा की स्थिति की काफी खराब हुई है। कई देशों में घरेलू हिंसा और लैंगिक हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। जहां एक ओर बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर अधिकांश देशों में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम से संबंधित सेवायें भी बाधित हुई हैं।

वैश्विक स्तर महामारी के कारण वर्ष 2020 में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है और इसके अतिरिक्त 150 मिलियन बच्चों शामिल हो गए हैं। बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किये जाने वाले सभी अभावों/ कमी जैसे खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, निम्न जीवन स्तर, कार्य की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा आदि को समाहित किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 'चाइल्ड एब्ज्यूज इन

इंडिया' के मुताबिक भारत में 53.22 प्रतिशत बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का लैंगिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न हुआ है।

लॉकडाउन के ठीक 11 दिन बाद ही देश की सबसे बड़ी बच्चों से जुड़ी सरकारी संस्थाएं हेल्पलाईन, चाइल्डलाइन ने ये दावा किया है कि लॉकडाउन के बाद कॉल्स में 50 फीसदी इजाफा हुआ है और शुरूआती 11 दिनों में ही बाल हिंसा से जुड़े 92000 कॉल्स आये थे, जिसकी संख्या अब और अधिक बढ़ गयी है। इन कॉल्स के जरिये बाल हिंसा और उत्पीड़न को रोकने में मदद की मांग की गई थी, यह स्थिति इशारा करती है कि लॉकडाउन के बीच कई महिलायें बंधक जैसी स्थिति में हैं और कुछ बच्चों उत्पीड़न के आरोपियों के साथ ही घरों में फंसे हुए हैं। चाइल्ड लाइन इंडिया की उपनिदेशक ने बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से 20-31 मार्च 2020 के बीच चाइल्ड लाइन 1098 पर 3.07 लाख फोन कॉल आईं। इनमें 30 फीसदी यानी 92,105 फोन कॉल्स बच्चों से जुड़ी थी, जिनमें हिंसा और उत्पीड़न से बचाव की मांग की गई थी। बालिया के अनुसार 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसके बाद फोन कॉल 50 फीसदी तक बढ़ गईं।

वहीं लॉकडाउन के दौरान बच्चे ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं ऐसे में ऑनलाईन बाल शोषण के मामले सामने आ रहे थे, लॉकडाउन में बच्चे सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग जैसे अनजान खतरों के चंगुल में आए। साधारण भाषा में कहे तो अभद्र अश्लील भाषा, चित्रों और धमकियों से इंटरनेट पर किसी को परेशान करना साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। यू.एन. की रिपोर्ट के मुताबिक 200 देशों के 160 करोड़ बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, ऐसा पहली बार हुआ। भारत में 36 करोड़ बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। अमेरिकी स्टडी के मुताबिक बच्चे स्कूल लौटेंगे तो रीडिंग लेबल भी 30 प्रतिशत तक घट सकता है और बच्चे गणित में एक साल तक पिछड़ सकते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात सुधरने के बाद भी देश में स्कूल कॉलेज में 97 लाख बच्चों नहीं लौट सकेंगे। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं बच्चों व किशोरों पर पड़ा है।

यूनिसेफ का मानना है कि प्रत्येक बच्चा तभी सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है जब समुदाय के सदस्य बच्चों की उपेक्षा, हानि और

उन पर हिंसा को रोकने में जिम्मेदारी लेते हैं और एक योग्य और सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। समुदाय एवं अन्य कर्तव्यधारकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बाल अधिकार हनन को लेकर जागरूक हों जो कि बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जैसे बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के साथ हो रही हिंसा आदि साथ ही उन कानूनी प्रावधानों को लेकर भी जागरूक हो जो बाल पीड़ितों के हितों की संरक्षण में मदद कर सकते हैं।

विश्व के लगभग 19 प्रतिशत बच्चे भारत में निवास करते हैं भारत की कुल आबादी का एक तिहाई से भी अधिक हिस्सा लगभग 17 करोड़ बच्चे यानी कुल बच्चों का 40 प्रतिशत हिस्सा या तो जोखिम में हैं या फिर मानव तस्करी, बाल मजदूरी शारीरिक व मानसिक शोषण उत्पीड़न और हिंसा की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार महामारी की वजह से बच्चों की देखभाल को लेकर भी चुनौतियाँ सामने आई हैं। बच्चों की शारीरिक गतिविधियाँ भी रुक गई थी। लॉकडाउन में घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई थी और घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सी.टी. स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलीसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है। कई बच्चे अपने पिता से गुस्सैल, आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः चुपचाप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।

निष्कर्ष- इस प्रकार उपरोक्त कई पहलुओं का आंकलन करने से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस महामारी के कारण उपजी आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों और आवाजाही पर पाबंदी लगने से लगभग विश्व के सभी देशों में महिलाओं व बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई। इतना ही नहीं सभ्यता व शिष्टाचार के शिखर पर होने का दावा करने वाले पश्चिमी दुनिया के देशों में भी घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई। कोरोनाकाल में महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा का शिकार

होना पड़ा था और घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं हो पाता है। क्योंकि समाज में जब तक हिंसा की संस्कृति रहेगी तब तक स्त्री खौफ में जीयेगी, आज हम न केवल उस संस्कृति को बना रहे हैं, जी रहे हैं, बल्कि अनजाने में उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं, जब तक उस हिंसा की संस्कृति की कड़ी को नहीं तोड़ेंगे तब तक स्त्री की मुक्ति, संभव नहीं है। जैसा कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी सुझाव दिया था कि हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां हिंसा की स्थिति ही पैदा न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- आवाज संस्था भोपाल से प्राप्त दस्तावेज।
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2020
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2020
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 02.01.2021
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 12.01.2021
- www.indiatimes.com
- www.tv9hindi.com
- www.aajtak.in
- www.thewirehindi.com
- www.drishtias.com

कोविड - 19 के बाद बजट 2021-22 में राज्यों के सुधार हेतु उपाय

• डॉ. कुमुद श्रीवास्तव

कोविड- 19 ने विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने के लिये एक चुनौती प्रस्तुत की है। इस महामारी ने सतत् जटिल, अनिश्चित और गतिशील परिस्थितियों के दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक संकटों से निपटने के लिये नीति निर्माताओं की परीक्षा ली है। इस घटना ने चिकित्सा वैज्ञानिकों का भी परीक्षण किया है। महामारी की शुरुआत में अभूतपूर्व अनिश्चिता का सामना करते हुये भारत के दीर्घकालीन लाभ के लिये अल्पकालीन हानि की इच्छा से जीवन और आजीविका को बचाने के लिये ध्यान केन्द्रित किया। भारत ने अल्पकालीन व्यापार बंद को मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन की दोहरी जीत के रूप में बदल दिया। भारत अपनी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसांख्यिकी, परीक्षण और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के आधार पर देशों में अपेक्षित प्राकृतिक मामलों और मौतों की संख्या का अनुमान लगाकर यदि इन अनुमानों की वास्तविक संख्या के साथ तुलना करते हैं कि भारत में कोविड- 19 के प्रसार को 37.1 लाख तक रोका तथा 1 लाख से ज्यादा लोगो की जान बचाई। कोविड- 19 महामारी ने माँग और पूर्ति दोनो को श्रम, बाजारों की रूकावटें वित्तीय संकट से जूझ रही सुलभ आय, फर्मों, उत्पादन क्षमता, शिक्षा स्वास्थ्य संचार पूर्व से चल रहे सुधारों एवं विकास कार्यक्रमों सभी को प्रभावित किया है।

शोध के उद्देश्य-

1. कोविड - 19 काल में राज्यों का विश्लेषण
2. बजट 2021-22 में केन्द्र द्वारा राज्यों हेतु किये गये उपायों का विश्लेषण
3. राज्यों हेतु बजट आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अध्ययन
4. बजट में राज्यों को पूँजीव्यय हेतु विशेष सहायता का अध्ययन

• प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी (म.प्र.)

5. जी.एस.टी. राजस्व में नुकसान की व्यवस्था का अध्ययन
6. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एस.डी.आर.एफ.) हेतु बजट 2021-22 में किये गये प्रावधानों का अध्ययन।

शोध प्रवधि- प्रस्तुत शोध पत्र हेतु अध्ययन क्षेत्र भारत देश लिया गया है, अध्ययन की अवधि मार्च 2020 से जनवरी 2021 एवं बजट 2021-22 लिया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अध्ययन हेतु द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समंको के अंतर्गत प्रकाशित स्रोतों का प्रयोग किया है। प्रकाशित स्रोतों के साथ-साथ इंटरनेट, मीडिया, समाचार चैनल का भी प्रयोग किया है। तथ्यों का वर्गीकरण उपस्थित स्थिति का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया गया है।

भारत के विभिन्न राज्यों में तीव्र लॉकडाउन ने महामारी का प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने में मदद की है। भारत की विविधता को देखते हुये एक अन्तरराज्यीय विश्लेषण राज्यों का आँकलन करने के लिये जानकारी पूर्ण है जो कोविड 19 के प्रसार को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम थे। भारत में अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या एवं मृत्यु की संख्या अधिक थी। महाराष्ट्र ने मामलों की संख्या और मृत्यु में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। यदि महाराष्ट्र की तुलना उत्तर प्रदेश और बिहार से करते हैं तो पाया कि इन तीनों राज्यों में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है और महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग समान है। लेकिन महाराष्ट्र में बिहार और उत्तरप्रदेश दोनों की तुलना में कम जनसंख्या घनत्व है। फिर भी बिहार और उत्तरप्रदेश में मामले कम हुये, जबकि महाराष्ट्र में अधिक मामले हुये। केरल, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, दिल्ली को भी प्रभावी रूप से प्रबंधित किया। जिससे भारत को अच्छी स्थिति में रखा जा सका।

अभी तक जो भी विवेचना की गई वह कोविड-19 काल की है। वर्तमान में भारत कोविड 19 के मामलों एवं मौत के हिसाब से बेहतर स्थिति में है। कोविड 19 से सुधार की दर 98 प्रतिशत तक पहुँच गई है। भारत ने महामारी पर नियंत्रण पा लिया है तथा भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में महामारी के वजह से आर्थिक कार्यों को पूरी तरह से संचालित करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारत सरकार अगले वित्तीय

वर्ष में राज्यों को अपनी स्थिति को सुधारने के लिये आम बजट 2021-22 में कुछ उपायों की घोषणा की है। महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राज्य सरकार ने लगातार कदम उठाये हैं केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिये लगातार कदम उठाये हैं ये उपाय इस प्रकार हैं -

1-आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिये उधार की बढ़ी हुई सीमा- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी जो कि 4.27 लाख करोड़ रुपये के बराबर थी। राज्यों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत उधार की अनुमति दी गई। 005 प्रतिशत उधार की पहली किस्त सभी राज्यों के लिये खुला था जीएसडीपी का 1 प्रतिशत की दूसरी राशि चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन थी, जहाँ प्रत्येक सुधार का भार जी. एस.डी.पी. का 0025 प्रतिशत था।

अ- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन।

ब- व्यापार सुधार करने में आसानी

स- शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार और

द- पावर सेक्टर में सुधार

उपयुक्त सुधारों में से कम से कम 3 को अंतिम रूप देने पर अंतिम 005 उधार सशर्त था। 30 दिसम्बर 2020 तक 10 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू की है, 7 राज्यों ने ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया है और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किये हैं, कुल अतिरिक्त उधान अनुमति उन राज्यों को जारी की गई है, जिन्होंने सुधार किये हैं जो 51,682 करोड़ रुपये हैं।

2-पूँजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष सहायता के लिये योजना- वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड- 19 महामारी से उत्पन्न कर राजस्व में कमी के कारण राज्य सरकारों द्वारा सामना किये गये राजकोषीय वातावरण को देखते हुये पूँजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष सहायता की योजनाओं की मंजूरी दी गई है। जिसमें राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है जो कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

इस योजना में आठ उत्तर पूर्व राज्यों के लिये 1600 करोड़ रुपये

(प्रत्येक के लिये 200 करोड़) का ऋण शामिल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिये 900 करोड़ रूपये का ऋण (प्रत्येक के लिये 450 करोड़ रूपये) शेष राज्यों के लिये 7500 करोड़ रूपये (15 वें वित्त आयोग विचलन के अनुसार) और उन राज्यों के लिये 2000 करोड़ रूपये जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उधार प्रावधान के तहत उल्लिखित 4 सुधारों में से कम कम से कम 3 को पूरा करते हैं। ऋण राशि का उपयोग नई या चल रही पूँजी परियोजनाओं के लिये किया जा सकता है। जिन्हें इस तरह की परियोजना पर धन और/ या ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का निपटान करना चाहिये।

12 दिसम्बर 2020 तक 27 राज्यों के लिये 9879.61 करोड़ रूपये की पूँजी व्यय परियोजना को मंजूरी दी गई थी और इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 4939.81 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी।

3-जीएसटी राजस्व में नुकसान के लिये राज्यों को मुआवजा- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जी.एस.टी राजस्व के नुकसान में लिये राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष विंडो के तहत ऋण के मुद्दे के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को उधार लेने का एक विकल्प दिया था जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिया गया था (विकल्प 1) या बाजार ऋण (विकल्प 2) के मुद्दे के माध्यम से पूरी कमी को उठाये। सभी 28 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेश विधायिकी के साथ विकल्प 1 के लिये जाने का निर्णय लिया, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित बैंक-टू बैंक उधार शामिल है और जीएसटी मुआवजे के तहत प्रवाह के समान संसाधनों का स्थिर प्रभाव सुनिश्चित करेगा। 23 अक्टूबर 2020 से 1.1 लाख करोड़ रूपये की विशेष विंडो का परिचालन किया गया है और भारत सरकार ने पहले ही पाँच किस्तों में राज्यों की ओर से 54000 करोड़ रूपये की राशि उधार ली है और इसे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पारित किया है।

विकल्प 1 की शर्तों के तहत राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अनुमत 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी में से जीएसडीपी की 005 प्रतिशत की अंतिम किस्त उधार लेने की बिना शर्त अनुमति प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये 1.1 लाख करोड़ रूपये से अधिक विशेष विंडो से

बढ़कर 1007 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त जुटाने की राशि है।

इसके अतिरिक्त विकल्प 1 का चयन करने वाले राज्य अगले वित्त वर्ष के लिये वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अनुमत अतिरिक्त उधार की छत को आगे ले जाने में सक्षम होंगे जिससे प्रत्येक की पहली और अंतिम किस्तों को 005 प्रतिशत बिना शर्त के आगे बढ़ाया जा सके यदि राज्यों द्वारा इस वर्ष पहले से निर्धारित तारीखों के भीतर सुधार मानदंड पूरा करते हैं तो सुधार से जुड़े अंशों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

उच्च उधारी लागत से राज्यों को बचाने की दृष्टि से केन्द्र विशेष उधारी खिड़की के लिये लागत को सरकारी सिक्क्योरिटी (जी-सेक) उपज के करीब या उसके नजदीक रखने का प्रयास करेगा और लागत अधिक होने की स्थिति में यह सब्सिडी के माध्यम से सरकारी सिक्क्योरिटी (जी-सेक) और औसतन 50 बी.पी.एस. तक के राज्य विकास ऋण पैदावार के बीच का अंतर वहन करेगा। विशेष विड़ो के तहत उधार पर ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर/सैस के रूप में और जब यह संक्रमण की अवधि के अंत तक उठता है। संक्रमण अवधि के बाद मूलधन और ब्याज का भुगतान उपकर/सैस की आय से भी किया जायेगा जो कि आवश्यक अवधि के लिये संक्रमण अवधि से परे उपकर/सैस बढ़ाकर किया जा सकता है। राज्य को ऋण की व्यवस्था करने या किसी अन्य स्रोत से इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।

एस.डी.आर.एफ के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक बार के विशेष वितरण के माध्यम से कोविड - 19 को एक अधिसूचित आपदा के रूप में माना था। महामारी में निपटने के लिये राज्यों को मजबूत करने के लिये केन्द्र ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकारों को 11.92 करोड़ रुपये की एसडीआर की पहली किस्त जारी की थी। सितम्बर 2020 में एस.डी.आर.एफ को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च करने की राज्यों की सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी ताकि उन्हें कोविड 19 के नियंत्रण उपायों में समर्थन देने के लिये क्वारंटाइन सेंपल संग्रह और स्क्रीनिंग के उपायों सहित और कोविड- 19 की प्रतिक्रिया के लिये आवश्यक उपकरणों / प्रयोगशालाओं की खरीद की जा सके। इस शोध पत्र में किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि-

- वित्तीय वर्ष 2019-21 के कोविड 19 महामारी ने नीति निर्माताओं

के समक्ष बड़ा संकट पैदा कर दिया था।

- भारत में सही समय पर दिये गये लॉकडाउन ने बहुत बड़ी संख्या में लोगो का जीवन बचाया है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई हानिकारक प्रभाव पड़े है।
- भारत सरकार ने राज्यों को आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी है।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को राजस्व में कमी के कारण पूँजीगत व्यय के लिये राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप सहायता प्रदान की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी राजस्व के नुकसान के लिये राज्यों में क्षतिपूर्ति करने के लिये केन्द्र सरकार ने राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष विंडो के तहत ऋण के मुद्दे के माध्यम से जी.एस.टी. कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को उधार लेने का विकल्प राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने दिया गया था।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अंतर्गत बजट 2020-21 में कोविड - 19 ने अधिसूचित आपदा मानते हुये राज्यों के खर्च करने की सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ायी है।

कोविड 19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों को ठीक करने के उद्देश्य भारत सरकार ने बजट 2021-2022 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जी.एस.टी. राजस्व के नुकसान के लिये राज्यों ने मुआवजा, पूँजीगत व्यय के लिये राज्यों के लिये विशेष योजना तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल(एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत जो सहायता राज्य को दी जा रही इन उपायों की सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि इन उपायों का निष्पादन पूरी कार्य कुशलता एवं क्षमता के साथ किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020
- दैनिक भास्कर माह मार्च 30.3.20 से 01 जुलाई 2020
- दैनिक नई दुनिया माह 15 अप्रैल 2020 से 30 अगस्त 2020

- दैनिक पत्रिका माह अप्रैल 01.4.20 से 3 अगस्त 2020
- Govt of India Launch of the initiative, Aatmanirbhar Bharat Abhiyan new Delhi 12 may 2020

कोरोना महामारी का मानव के आर्थिक व सामाजिक स्तर पर प्रभाव

•डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव
••उमेश सिंह

कोरोना का असर 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहेगा और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था को इस महामारी के प्रकोप की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था आक्सफोर्ड इकोनामिक्स (Oxford Economics) ने आपने ताजा ग्लोबल रिपोर्ट में ये आंकलन रखा है कि 2025 तक भारत की पर-कैपिटा जीडीपी कोविड से पहले के मुकाबले 12 प्रतिशत तक नीची रहेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था आक्सफोर्ड इकोनामिक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है की 2020 से 2025 के बीच आर्थिक विकास दर कोविड महामारी से पहले अनुमानित 6.5 प्रतिशत से गिर सिर्फ 4.5 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है।

कोरोना से पहले ही कमजोर थी अर्थव्यवस्था- कोरोना वायरस के भारत में पहुंचने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक थी। कभी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की विकास दर बीते साल 4.7 फीसदी रही। यह छह सालों में विकास दर का सबसे निचला स्तर था। साल 2019 में भारत में बेरोजगारी 45 सालों के सबसे अधिकतम स्तर पर थी और पिछले साल के अंत में देश के आठ प्रमुख क्षेत्रों से औद्योगिक उत्पादन 5.2 फीसदी तक गिर गया। यह बीते 14 वर्षों में सबसे खराब स्थिति थी। कम शब्दों में कहें तो भारत की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब हालत में थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अब कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से जहां एक ओर लोगों के स्वास्थ्य पर संकट छाया है तो दूसरी ओर पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका मिल सकता है।

-
- प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
 - शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सरकार के प्रयासों का रियलिटी चेक- भारत में असंगठित क्षेत्र देश की करीब 94 फीसदी आबादी को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45 फीसदी है। लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र पर बुरी मार पड़ी है क्योंकि रातों-रात हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। इसीलिए सरकार की ओर से जो पहले राहत पैकेज की घोषणा की गई वो गरीबों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से हुई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की जिससे भारत के गरीब 80 करोड़ लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उनकी रोजी-रोटी चल सके। खातों में पैसे डालकर और खाद्य सुरक्षा का बंदोबस्त करके सरकार गरीबों, दैनिक मजदूरी करने वालों, किसानों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद कर रही है। विशेषज्ञ सरकार के इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, लेकिन वो यह भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को इस संकट के बुरे असर बचाने के लिए और भी प्रयास किए जाने की जरूरत है।

सरकार ने राहत पैकेज में किसानों के लिए अलग से घोषणा की है। सरकार अप्रैल से तीन महीने तक किसानों के खातों में हर महीने 2000 रुपये डालेगी। सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये पहले ही देती थी। अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं, “दो हजार रुपये की मदद पर्याप्त नहीं है क्योंकि निर्यात ठप्प हो चुका है, शहरी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि मांग बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कीमतें गिरेंगी क्योंकि किसान अपनी फसल बेच नहीं पाएंगे।” यह संकट बेहद गंभीर समय में आया है, जब नई फसल तैयार है और बाजार भेजे जाने के इंतजार में है। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कठिन लॉकडाउन की स्थिति में गांवों से खाने-पीने की ये चीजें शहरों और दुनिया के किसी भी देश तक कैसे पहुंचेंगी। अगर सप्लाई शुरू नहीं हुई तो खाना बर्बाद हो जाएगा और भारतीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत की कुल आबादी का 58 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है और देश की अर्थव्यवस्था में 256 बिलियन डालर का योगदान है।

विशेषज्ञ इस बात के लिए भी चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ने के पूरे आसार हैं। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद होने की

वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आई है। प्रोफेसर घोष का मानना है कि स्वयं रोजगार करने वाले या छोटे कारोबार में जुड़े लोगों को राहत देने के लिए सरकार ब्याज और टैक्स चुकाने में छूट देकर उनकी मदद कर सकती है ताकि कारोबार उबर पाए। अर्थशास्त्री विवेक कौल कहते हैं, “भारत में बेरोजगारी अब भी रिकार्ड स्तर पर है और अगर यह स्थिति जारी रहती है तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। छोटे कारोबार में काम करने वाले लोग या तो कम पैसे में काम करने को मजबूर होंगे या फिर उनकी नौकरी छिन जाएगी। मैं ऐसी जगहें जानता हूँ जहां कंपनियों में यह चर्चा चल रही है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाले जाने की जरूरत है।”

देश में होटल और रेस्टोरेंट चेन बुरी तरह प्रभावित हैं और कई महीनों तक यहां सन्नाटा पसरे रहने से बड़ी संख्या में लोगों को सैलरी न मिलने का भी संकट नजर आ रहा है। बंद की वजह से आटो इंडस्ट्री पर भी अछूती नहीं है और करीब दो अरब डालर का अनुमानित नुकसान झेलना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जिस राहत पैकेज की घोषणा की है वो देश के कुल जीडीपी का एक फीसदी है। सिंगापुर, चीन और अमेरिका की तुलना में यह राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को बड़े पैकेज की घोषणा जल्द करनी चाहिए ताकि कोरोना की तबाही में डूब रहे कारोबार को वापस पटरी पर लाया जा सके।

मिडिल क्लास को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जारी हर संकट के बीच मिडिल क्लास सबसे अधिक कमजोर होता है। सरकारों द्वारा जारी होने वाले राहत पैकेज में यह क्लास शामिल नहीं हो पाता है। आर्थिक संकट की घड़ी में अक्सर मिडिल क्लास कमजोर होता है और उसका एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में गरीब आबादी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वर्तमान में कोविड-19 का संकट भी कुछ ऐसा संकेत दे रहा है। यह संभव है कि अधिकतर छोटी सैलरी पर काम करने वाला मिडिल क्लास इस संकट में अधिक कमजोर हो और वह लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे की श्रेणी की तरफ शिफ्ट हो जाए।

आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी तथ्य का जिक्र किया है कि भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मिडिल क्लास की भी आर्थिक परिस्थितियों को प्रमुखता से ध्यान दिया जाए।

आर्थिक प्रभाव के अलावा सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं - अगर इस प्रश्न के उत्तर पर गहनता से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि इस महामारी के चलते पहला नकारात्मक प्रभाव तो आर्थिक ही होगा। मगर मेरा उद्देश्य यहां इस महामारी से उत्पन्न उन सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना है, जो तत्काल अथवा महामारी के उपरांत पूर्ण या आंशिक रूप से देखने को मिल सकते हैं।

महामारी का प्रथम प्रभाव- इस क्रम में इस महामारी का पहला और सबसे गंभीर प्रभाव तो उन परिवारों पर ही पड़ेगा जिनके सदस्य इस बीमारी के चलते मृत हो गए हैं। वे अगर परिवार के मुखिया थे तो ऐसे में परिवार संभालने की जिम्मेदारी, बच्चों का वर्तमान एवं भविष्य सब अनिश्चित हो जाएगा। चूंकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या हजारों में है। अतः इसका व्यापक असर उन देश के समाज पर भी देखने को मिलेगा।

महामारी का द्वितीय प्रभाव- महामारी का दूसरा सामाजिक प्रभाव 'नस्लभेदी प्रभाव' का उत्पन्न होना है। जैसा कि हमें मालूम है इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है इसलिए चीनी नागरिकों को आगामी कुछ वर्षों तक इस महामारी के चलते जाना-पहचाना जा सकता है। अन्य देशों के लोगों द्वारा उन पर ना केवल नस्लभेदी टिप्पणी की जा सकती है, बल्कि उन्हें उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ सकता है। भारत में तो नार्थ ईस्ट के भारतीयों पर पहले से ही चीनी, नेपाली, चिंकी-पिंकी, मोमोज जैसी नस्लभेदी टिप्पणियां होती रही हैं। अब इस क्रम में कोरोना का नाम भी जुड़ना तय है, जिसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।

महामारी का तृतीय गंभीर सामाजिक प्रभाव- तीसरा सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव उन समुदायों पर देखने को मिलेगा जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए हैं। मसलन, घुमंतू समुदाय के लोग, दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इत्यादि।

इन समुदाय के लोगों पर इस महामारी का दोहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहला प्रभाव तो रोजगार छूट जाने की स्थिति में वर्तमान

आय का शून्य हो जाना है। वहीं दूसरी तरफ किसी प्रकार की बचत ना होने की स्थिति में परिवार के भरण पोषण के दबाव से गुजरना एवं परिवारिक कलह जैसी समस्या का उत्पन्न होना है।

स्त्री विमर्श के नजरिये से महामारी का एक सामाजिक प्रभाव- महामारी का एक सामाजिक प्रभाव स्त्री विमर्श के नजरिये से भी देखा जा सकता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में परिवार की सुबह से रात तक की जरूरतों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसा कि सभी को ज्ञात है लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी अपने-अपने घरों में कैद हैं तो ना चाहते हुए भी इस महामारी के दौरान महिलाओं के घर के कामों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई है। जिसका प्रभाव महिलाओं की सेहत और मानसिक दबाव के रूप में देखने को मिल सकता है।

उपर्युक्त नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के इतर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इस कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 'पर्यावरणीय प्रभाव' है। चूंकि इस दौरान सभी प्रकार के प्रदूषणों पर पूरी तरीके से अचानक रोक लग गई है जिससे नदी, हवा सभी के साफ होने से लोगों को आगामी दिनों में लाभ मिलेगा।

दैनिक जीवन की व्यस्तता और काम के बोझ के चलते लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। तो इस महामारी ने उन सभी लोगों की शिकायतों को दूर करने का एक अवसर भी प्रदान किया है। मगर इन सकारात्मक पहलुओं की कीमत बहुत भारी है। इसलिए बेहतर तो यही है कि इस महामारी से जितनी जल्दी हो सके पूरा विश्व मुक्त हो जाए जिससे जन जीवन पहले जैसा सामान्य हो सके। इसके लिए हर देश के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।

सरकार एवं सुरक्षा उपाय संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस महामारी को हराने का यही एक मात्र उपाय है और इसके तमाम नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से बचने का भी। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कोरोना महामारी होने के पहले से ही बिगड़ी हुई थी। जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भारत के विकास दर के वृद्धि अनुमान में लगातार गिरावट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर है। ऐसे में कोरोना

महामारी के चलते जिस तरीके से भारत तथा विश्व के अधिकांश देशों में पूर्ण लॉकडाउन नीति अपनाई गई है, उससे ना केवल भारत को बल्कि विश्व के हर देश को इसकी आर्थिक एवं सामाजिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

- लॉकडाउन में राहत के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही अर्थव्यवस्था, जनसत्ता, 13 जुलाई 2020, अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- कोरोना के सामने घुटनों पर आई दुनिया की अर्थव्यवस्था', आज तक, मूल से 29 जून 2020 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियां, ORF मूल से 10 मई 2020 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- अहमद, जुबैर (1 मई 2020), कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ जाएगी?, BBC News हिंदी, मूल से 27 जून 2020 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 23 जुलाई 2020.
- कोरोना का प्रभाव, 2020 में 4.5 फीसदी GDP का अनुमान-सरकार, अमर उजाला, मूल से 9 जुलाई 2020 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.

कोविड 19 और प्रवासी मजदूर

• डॉ. गजानन मिश्र

कोरोना वायरस की शुरूआत चीन के वोहान शहर से हुई, जिसमें वायरस के लक्षणों में मामूली जुखाम से लेकर गम्भीर रोगों की वजह को स्वीकार किया गया। जिसे कि मिडिल ईस्ट रेस्पिटरी सिंड्रोम और सीवियर एम्बूट रेस्पिसरी सिंड्रोम कहा गया। कोरोना वायरस जूनोटिक है जिसका अर्थ है पशुजन्य रोग। यह वायरस इंसान और जानवर दोनों को चपेट में लेता भुगतते हैं। इस वायरस को सार्स-कोविड-2 नाम रखा गया। इसकी वजह से आने वाले बीमारी को कोरोना डिजीज 2019 संक्षिप्त में कोविड-19 रखा गया। रोजाना हजारों लोगों को शिकार बनाने के अलावा इसका प्रभाव स्पष्टतः समूची दुनिया में सामाजिक उथल-पुथल के रूप में आया व वायरस चुटकियों में पूरी दुनिया में फैल गया। विमान सेवार्यें बंद कर दी गई, पर्यटन उद्योग थम गया, मनोरंजन जैसे उद्योग व उत्पादन इकाईयां बंद हो गई व प्रत्येक देश अपने आप में सिमट गये एवं जनता पर ढेरों प्रतिबंध लगा दिये गये।

कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में ग्रामीण व नगरीय समाजों पर इसका प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। जिसके प्रभाव के फलस्वरूप शहरों से लोग अपने गृह ग्राम की ओर लौटने पर मजबूर हुए। प्रवासिता मुख्यतः व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की क्रिया को कहते हैं। प्रवर्जन की प्रक्रिया आदिकालीन समय से ही है, इसका मूल कारण व्यक्ति का घुमंतू जीवन है। आदिम अवस्था के प्रथम चरण में मनुष्य द्वारा जीवकोपार्जन या वनोपज संग्रहण हेतु प्रवास किया जाता था। प्रवास एक जननांकीय घटक है, जिसमें जनसंख्या का आकार, वितरण और संरचना प्रभावित होती है। जनसंख्या को जितना अधिक जन्म और मृत्यु प्रभावित करते हैं, उतना ही प्रवास। प्रवास एकाएक परिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है जिसमें एकाएक सामाजिक व्यवस्था और संरचना बदल जाती है।

• प्राध्यापक समाजशास्त्र, महात्मा गांधी महाविद्यालय, करेली

भारत में एक अरब दो करोड़ लोगों में से तीस प्रतिशत यानि तीस करोड़ सत्तर लाख लोग प्रवासी आधार पर दर्ज हैं। 1961 तथा 2011 की जनगणना के तुलनात्मक अध्ययन में 1961 में 14 करोड़ 40 लाख प्रवासी मजदूर थे। जबकि पिछले दशकों में इनकी वृद्धि 32.9 प्रतिशत हुई। सबसे ज्यादा प्रवासियों में महाराष्ट्र 97 लाख, इसके बाद दिल्ली 50 लाख, पश्चिम बंगाल 55 लाख तथा फिर अन्य शहर आते हैं। भारतीय पृष्ठभूमि में आंतरिक प्रवास सामाजिक जीवन का अपरिहार्य घटक है, जिसमें 70.7 प्रतिशत महिलाएं व 20 ग्रामीणजन व 15 करोड़ बच्चे रोजगार के कारण पलायन करते हैं, जिसमें उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा प्रमुख राज्य हैं। यहां से ग्रामीण महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा कर्नाटक की ओर रोजगार की तलाश में जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एवं सामाजिक सम्पन्नता में प्रवासी मजदूरों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये मूलतः घरेलू काम, कपड़ा उद्योग, यातायात खान-खदान में काम करने वाले लोग होते हैं। अधिकांश अल्पकालिक व पलायनकर्ता आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होते हैं, जिनकी शैक्षणिक उपलब्धियां न्यूनतम व सम्पत्ति सीमित होती है, संसाधनों के अभाव के कारण ये अल्पकालिक या दीर्घकालिक तौर पर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। कोविड-19 के प्रभावों के फलस्वरूप एकाएक जब भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की तब सारी संवेदनहीनता के साथ आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति से विषमकारी मजदूरों के पलायन की हृदय विदारक घटनायें सुर्खियों में रहीं। लाखों की तादाद में मजदूर शहर से अपने ग्रामों की ओर पैदल ही चल पड़े। उन्हें अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, वे भूखे-प्यासे नंगे पैर तपती दोपहरी में पीठ पर बोझ लादे बहवास अपने घरों की ओर लौटे। इसमें सबसे आवश्यक तथ्य ये है कि अगर प्रबंधक इन मजदूरों का विश्वास जीत लेते व रोटी पानी की व्यवस्था करते तो वे वापिस ही न लौटते। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूरा करने का विकास जो शहरी सभ्यता तक सीमित रहा इसलिए लोग शहरों की ओर चले गये और परिस्थितियां विपरीत होने पर फिर शहरों से ग्रामों की ओर प्रवास करने लगे।

लॉकडाउन के पश्चात् प्रवासी मजदूर अपने गृह ग्राम की ओर लौटे, वापिस आने और लगातार घर में रहने के कारण उनकी पारिवारिक स्थितियां क्या रहीं इसका मैंने मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के पांच ग्रामों के 202 परिवारों का, लॉकडाउन सप्ताह में पांच दिनों के लिए खुला तब साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उनकी पारिवारिक स्थिति को जानने का प्रयास किया, जो निम्न बिन्दुओं में समाहित है।

कोरोना लॉक-डाउन के पश्चात् प्रवासी मजदूरों की पारिवारिक स्थिति

ग्राम	क्या आपके पास जमीन है	ग्राम में रोजगार मिला	पारिवारिक स्थिति तनावपूर्ण	क्या आप रोजगार हेतु वापिस जायेंगे	कुल	प्रतिशत
बगासपुर	2 0.99	4 1.98	5 2.47	24 11.88	35	17.32
रामनिवारी	1 0.49	4 1.98	14 6.93	27 13.36	46	22.77
इमलिया	3 1.48	10 4.96	18 8.91	23 11.39	54	26.73
मानेगांव	2 0.99	8 3.96	10 4.96	18 8.91	38	18.81
चीचली	00 00	5 2.47	12 5.94	12 5.94	29	14.36
योग- प्रतिशत	08 3.95	31 15.35	59 29.21	104 51.48	202	99.99

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि प्रवासी उत्तरदाताओं से जब प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 से भयभीत होकर जब आप अपने गृह ग्राम लौटे हैं, तब कृषि कार्य के लिये क्या आपके पास जमीन है, इस पर उत्तरदाताओं में जिसमें ग्राम बगासपुर के 0.99 प्रतिशत परिवार, रामनिवारी के 0.49, इमलिया के 1.48, मानेगांव के 0.99 व ग्राम चीचली के 00 प्रतिशत परिवार के पास अपनी जमीनें हैं व ये कृषि कार्य करने के इच्छुक भी हैं। परन्तु इन जमीनों को वह पर्याप्त नहीं मानते। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या आपको शहर से वापिस ग्राम आने पर रोजगार मिला व आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं, तब ग्राम बगासपुर के 1.99 प्रतिशत परिवार, रामनिवारी के 1.98, इमलिया के 4.96, मानेगांव के 3.96 व चीचली के 2.47 परिवारों का ये मानना था कि थोड़ा बहुत काम करने के लिए रोजगार तो मिला परन्तु पारिवारिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए यह सम्पूर्ण नहीं है।

तीसरा प्रश्न था कि क्या आप परिवार में संतुष्ट हैं, जिसके उत्तर में ग्राम बगासपुर के 11.88 प्रतिशत परिवार, रामनिवारी के 13.36, इमलिया के 11.39, मानेगांव के 8.91 व ग्राम चीचली के 5.94 प्रतिशत परिवारों का ये मानना था कि लम्बे समय से ग्राम के पारिवारिक सदस्यों के बीच अंतःकलह से दम घुटने लगा है। अंतिम तौर पर पूछा गया प्रश्न यह था कि क्या आप परिस्थितियां अनुकूल होने पर वापिस जायेंगे? तब ग्राम बगासपुर के 11.88 प्रतिशत परिवार, रामनिवारी के 13.36, इमलिया के 11.39, मानेगांव के 8.91 व चीचली के 5.94 प्रतिशत परिवारों का ये मानना था कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर हम पुनः रोजगार हेतु शहर की ओर वापिस जायेंगे।

मूल रूप से ज्ञात तालिकाओं के आधार पर निष्कर्षतः एक बात निकलकर आती है कि इसे हम विवशता कहें या संवेदनहीनता की भावना जो मनुष्य में ही प्रकट रूप से विद्यमान होती है, संवेदनाओं का संवहन, निर्वहन व प्रतिपादन मनुष्य द्वारा सम्भव है। क्योंकि मनुष्य के पास मन है, अन्य किसी प्राणी में संवेदना का स्वर दुर्लभ है। यह मनुष्य का प्रकृतिदत्त गुण है। कोरोनाकाल के परिणाम स्वरूप मानवीय मूल्यों की कमी आई, वह जो आपके अपने लोग थे, घर वापिस आये, तब कुछ समय के पश्चात् ही पारिवारिक सदस्य संवेदनहीन होते चले गये। त्वरित सुख के लिए पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो उत्तरदायित्व थे वह कमजोर पड़ गये व संवेदनहीनता की वजह से अपने घर की ओर लौटे मनुष्य वापिस जाने के लिए बेताब होने लगे हैं।

कोरोनाकाल के पूर्व से ही प्रवासिता को रोकने के लिए कानूनी उपचार को राज्य शासन व केन्द्र शासन ने अपने स्तर पर लागू किया था, यदि यह सही ढंग से संचालित होता तो भागमभाग की स्थिति न बनती। केन्द्र सरकार द्वारा पलायन पर सुसंगत नीतिगत सुझाव दिये गये जो निम्न हैं -

- पलायन को समग्र तथा केन्द्रीय रूप से नीति दस्तावेजों तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में मुख्यधारा से जोड़ें तथा सार्वजनिक सेवाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों में प्रवासियों के लिए लक्षित घटक तथा विशेष प्रचार रणनीतियों को शामिल किया जाये।
- गरीबों के पक्ष में विकास रणनीतियां अपनाकर पिछड़े इलाकों में पलायन की व्यवस्था को न्यूनतम किया जाये इससे स्रोत क्षेत्रों में

टिकारू आजीविका के अवसर भूमि व सांझा भू-संसाधन तक पहुंच में वृद्धि, बेहतर व भौतिक संरचनाएं तथा शासन संस्थायें व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ले पाने की सुविधाओं का विकास शामिल हो। राज्य स्तरीय शोध संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाये कि वह राज्य की पलायन छवि विकसित करे, जिसमें प्रत्येक राज्य में पलायन की प्रकृति, समय अवधि तथा पलायन वृत्तों की व्यापकता शामिल हो। अंतरजिला तथा अंतरराज्यी समन्वय समितियां गठित करें ताकि मजदूरों को भेजने व पाने वाले क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों के बीच संस्थागत व्यवस्थाओं की सांझी योजना बनायी जा सके। इससे सेवाओं को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित हो सकेगा व बदहवाशीय स्थिति नहीं बनेगी। प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिक इकाईयां स्थापित की जाये व वित्तीय मानव संसाधन बढ़ाये जायें।

- कोरोना वायरस के परिणामस्वरूप वापस आने वाले चूंकि प्रवासी मजदूर समान श्रेणी के नहीं होते व लिंग, वर्ग, प्रजातीयता धर्म के आधार पर बटे होते हैं। जिसमें बालक व महिलाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील समूहों में होते हैं, मिल मालिकों ने इन बिन्दुओं का ध्यान नहीं रखा, इसलिए यह वापसी कर गये। यह आवश्यक है कि मौजूदा श्रम कानूनों को वरीयता दी जाये जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 व श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार इनको सुविधायें नहीं दी गईं। यह आवश्यक था कि मिल मालिक इनको वैयक्तिक सेवाओं के प्रसार व्यापक बनाकर स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान रखते तो ये वापस न पलायन करते।
- कोरोना वायरस के दौरान यह चाहिए था कि मिल मालिक इन्हें बुनियादी सुविधायें जैसे- रहाइश, भोजन व पानी तथा अन्य सुविधायें देते तो ये पलायन न करते। कुछ कानूनों तथा नीतियों में जैसे नियुक्ति तथा सेवा परिस्थितियों का नियामन कानून 1979 जैसे- अधिनियमों का ध्यान ही नहीं रखा गया।
- मिल मालिकों को चाहिये था कि जिन राज्यों से प्रवासी बड़ी

संख्या में आते हैं उनके रैन बसेरों व अल्प आवास गृहों की व्यवस्था की जाती एवं इन्हें कोरोना वायरस के दौरान बैंकिंग सुविधायें, अस्थाई राशन कार्ड जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होते, दिये जाते तो ये वापिस न लौटते। यदि हम कुछ व्यक्तियों को छोड़ दे तों समाज के अन्य जिम्मेदारों ने जो इनकी वापस लौटने की व्यवस्था उचित संसाधनों से करा सकते थे, नहीं कराई, इसलिए बदहवास की स्थिति पैदा हुई।

यह आवश्यक है कि आगामी समयों में नगर निगमों, नगरीय निकायों, सरकार के अंगों, राजनैतिक तथा सामुदायिक नेताओं, राज्य की अफसरशाही, नगर योजनाकारों व अन्य दावेदारों मय मीडिया को शहरी प्रबंधन व नियोजन में प्रवासियों को शामिल करने की आवश्यकता के प्रति शिक्षित, प्रशिक्षित तथा सुग्राही बनाया जाये, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करें कि वे पंजीकरण कर प्रवासियों की आवासीय स्थिति की पुष्टि करें तथा उसे प्रमाणित करें। इससे अनावश्यक तौर पर किसी भी विषम परिस्थिति के आने पर भगदड़ नहीं मचेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- डेनियर यू. 2011: प्रवासी बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का अद्यतन प्रस्तुति भारत में आंतरिक प्रवासन एवं मानव विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
- कुन्दू ए, 2012, भारत में प्रवासन एवं विशेष रूप से शहरीकरण आर्थिक और राजनैतिक पत्रिका, अंक-47, संख्या 26 एवं 27, पृष्ठ सं. 219-227
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण: भारत में आवास की स्थितियां और सुविधायें 2008-09 नई दिल्ली, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार।
- स्मिता, 2008, बच्चों की शिक्षा पर संकटमयी मौसमी प्रवास एवं उसके प्रभाव, ब्राइटन, अनुसंधान मोनोग्राफ संख्या 28 के लिए मार्ग निर्माण।
- डेशिंगकर, पी. एवं एस., भारत में प्रवासन एवं मानव विकास, मानव एक्टर 2009 विकास शोधपत्र 2009/13 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
- एड एट एक्शन, 2011, ईट भट्टों पर बच्चे, पांच राज्यों के अनेक स्थानों पर अध्ययन, भुवनेश्वर, प्रवासन सूचना एवं संसाधन केन्द्र।

कोविड-19 एवं शिक्षा: चुनौतियाँ एवं भविष्य की रणनीतियाँ

•डॉ. वीणा

••डॉ. मिहिर प्रताप

कोविड-19 नामक संक्रामक वायरस से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। इसकी विभिषिका एवं संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे वैश्विक आपदा घोषित कर दिया है। इस वैश्विक आपदा का असर समाज के हर तबके पर पड़ा है, जिसके काफी दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। परन्तु जब देश का भविष्य कहे जाने वाले हमारे विद्यार्थियों की बात हो तो चिन्ता स्वाभाविक है। इस वैश्विक आपदाकाल में पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। भारतवर्ष में लगभग 32 करोड़ विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्रियाकलाप पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अनिश्चितकाल के सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजों की बन्दी एवं परिक्षाओं का ना हो पाना, अपने मित्रों सहपाठियों शिक्षकों से दूरी ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है, इन्हें कई एक समायोजनात्मक, संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझना पड़ा है। ऐसी असमंजस की स्थिति में भारत सरकार एवं सभी शिक्षाविदों ने इस वैश्विक आपदा एवं एक तरह की शैक्षणिक चुनौती को संभावनाओं एवं अवसर में बदलने की भरपूर कोशिश की है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कुछ सार्थक प्रयासों पर प्रकाश डालना है, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों के साथ ही भविष्य की रणनीतियों हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं, जिससे भारतवर्ष के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में एक सकारात्मक सोच, मनोवृत्ति, आत्मविश्वास एवं एक आशावादी सोच का निर्माण हो सके और इस प्रकार की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को हम सभी सक्षम रहें।

- सहायक प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, एल.एन.कॉलेज, भगवानपुर, वैशाली बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
- एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, एल.एन.कॉलेज, भगवानपुर, वैशाली बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

चीन के हुबई प्रांत के बुहान शहर से दिसम्बर 2019 से निकले संक्रामक वायरस कोविड-19 ने पूरे विश्व में पाँव पसार लिए, इसकी विभीषिका एवं संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक आपदा घोषित कर दी। भारत वर्ष में 24 मार्च 2020 से पूरे देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके कारण भारत वर्ष की 135 करोड़ आबादी डर, घबराहट अनिश्चितता के माहौल में एक चारदीवारी में जीने को बाध्य हो गई। लॉकडाउन समय की माँग थी, परन्तु इसका समाज के हर वर्ग एवं तबके पर व्यापक असर पड़ा। जहाँ तक शिक्षा जगत की बात की जाए तो पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यूनेस्को (UNESCO) की अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण विश्व के 90 प्रतिशत विद्यार्थियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। 120 करोड़ छात्र और युवा कोविड-19 से प्रभावित हुए। भारत वर्ष में 32 करोड़ विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। चूँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सलाहानुसार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 'सम्पूर्ण लॉकडाउन' लाना समय की माँग थी। जिसके कारण पूरे भारत वर्ष के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पूरी तरह से बन्द करने पड़े। सभी चल रही परिक्षाएँ स्थगित कर दी गईं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपनी सारी परिक्षाएँ बीच में रोक दीं। यहाँ तक की संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भी सिविल सेवा 2019 के इन्टरव्यू को भी स्थगित कर दिया। सभी राज्य सरकारों ने भी सभी परिक्षायें स्थगित कर दीं। हालाँकि यह समय की माँग थी, परन्तु सम्पूर्ण शिक्षा जगत के विद्यार्थियों में एक हताशा, नकारात्मकता, निराशा का माहौल खड़ा हो गया। इस नकारात्मकता पूर्ण वातावरण का बुरा असर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। उन्हें कई एक संवेगात्मक, समायोजनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझना पड़ा। चूँकि संक्रमण की शुरुआत चीन से ही हुई थी इसलिए इसके प्रभावों पर अध्ययन भी सबसे पहले वहीं शुरू हुए। मार्च 2020 में 501 विद्यार्थियों पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक स्थिति संज्ञानात्मक स्थिति एवं दुश्चिन्ता और अवसाद (डिप्रेशन) की मात्रा का पता लगाना था। यह पाया गया कि बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए।

विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य पत्रिका "द लैसेट" की रिपोर्ट के अनुसार

कोविड-19 के संक्रमण के डर, दुश्चिंता, तनाव का घातक प्रभाव लोगों में पड़ा है और इस कारण वो मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी मात्रा में तनाव संबंधी रोगों के शिकार हुए हैं और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए।

राजकुमार(2020)ने कोविड-19 और मानसिक स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण शोध सर्वेक्षण किया उन्होंने 47 शोधपत्रों का अध्ययन कर यह परिणाम पाया कि कोविड-19 के संक्रमण काल में मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। चाहे वो विद्यार्थी हो या सामान्य जन इन सबको एक मनोवैज्ञानिक सलाह एवं सहायता की आवश्यकता है, तभी एक स्वास्थ्य समाज की स्थापना की जा सकेगी।

कोविड-19 और ऑनलाइन शिक्षा (समय की माँग)- वैश्विक डिजिटल युग में जब सारा विश्व ऑनलाईन शिक्षण पद्धति को काफी हद तक अपना चुका था। तब हमारे भारतवर्ष में अभी भी उतना लाभ स्कूली स्तर पर नहीं के बराबर चल रहा था। गुरु शिष्य की कक्षा-शिक्षण की भारतीय शिक्षण पद्धति परम्परा का निर्वाह हम सभी मार्च 2020 तक कर ही रहे थे और काफी सुविधापूर्ण वातावरण में शिक्षण कार्य चल रहा था। वैश्विक आपदा में जब शिक्षक छात्र पूरी तरह से निराशा असमंजस में थे, ऐसे में आशा की किरण के रूप में ऑनलाईन कक्षाएँ शुरू की गईं। “ऑनलाईन शिक्षण वो शिक्षण होता है, जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से हम सीखते हैं और इसमें विद्यार्थी अपने अनुसार समय, स्थान का चुनाव कर सकते हैं।” (सिंह एवं टर्मन, 2019)

ऑनलाईन शिक्षण विश्वस्तर पर काफी प्रसिद्धि पा चुका है क्योंकि इसमें समय एवं स्थान की बाध्यता नहीं होती और बहुत ही कम समय और खर्च में ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री पहुँचाई जा सकती है।(चेन 2010, खुराना 2016)

वर्ष 2020 कोविड-19 की चुनौतियों के साथ ही कई एक नई संभावनाओं को भी लेकर आया। “इस शैक्षणिक आपदाकाल ने शिक्षण संस्थानों को अपनी टेक्नोलॉजिकल ज्ञान और संसाधनों को मजबूत करने का पर्याप्त समय प्रदान किया।” (परावत, 2020), आशा की किरण के रूप में ऑनलाईन शिक्षण को खुले मन से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने स्वागत किया। शिक्षक इन्टरनेट के द्वारा विभिन्न

एपलिकेशन जैसे जूम, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, यू-ट्यूब विडियो और स्काईप जैसे एप्लिकेशन के द्वारा विद्यार्थियों से सम्पर्क साध कर सभी को धीरे-धीरे पढ़ाना शुरू किया। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी को सीखा एवं तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित किया।

ऑनलाईन शिक्षण से माध्यम से ही भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कई एक ट्रेनिंग कोर्स कराए गए। इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को ओरिएंटेशन एवं रिप्रेजर कोर्स के सारे 2020-2021 के कोर्स को ऑनलाईन कर दिया जिससे शिक्षकों को घर बैठे ऑनलाईन कोर्स करने की सुविधा प्रदान की गई। इस कोरोनाकाल में प्रत्येक शिक्षक एक छात्र बन चुका था।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम- कोविड -19 से उपजी निराशा को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के द्वारा कई एक ऑनलाईन पोर्टल खोले गए। कक्षाएँ डायरेक्ट टेलिविजन और रेडियो द्वारा चलाए गये। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के द्वारा MHRD ने कई एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जिनमें कुछ प्रमुख हैं -

दीक्षा पोर्टल- इस ऑनलाईन पोर्टल द्वारा 250 शिक्षकों की एक टीम द्वारा वीडियो लेकर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। इस पोर्टल द्वारा 80,000 ई-बुक उपलब्ध कराए गई हैं, जहाँ कक्षा 1-12वीं तक के CBSE और NCERT की पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में हैं।

ई-पाठशाला- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा इस पोर्टल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12वीं कक्षा के लिए कई एक पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो उपलब्ध कराए गए हैं। ई-पाठशाला बेब पोर्टल पर 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई-बुक और 504 Flip बुक उपलब्ध कराए गए हैं।

नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस (NROER)- इस पोर्टल द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु 14527 फाइल्स हैं, जिनमें 2779 डॉक्यूमेंट्स और 1345 इंटरैक्टिव सेशन, 1664 ऑडियो और 6153 वीडियो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं साथ ही ऑनलाईन टेस्ट भी उपलब्ध हैं।

स्वयं पोर्टल (SWAYAM)- यह माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बना एक ऑनलाईन प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1900 कोर्स हैं, जो 9वीं से 12वीं कक्षा और

उच्चतर शिक्षा, स्नातक एवं स्नात्कोत्तर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें मानविकी एवं इंजीनियरिंग और समाज विज्ञान, कानून एवं प्रबंधन से संबंधित सभी कोर्स को लिया गया है।

स्वयंप्रभा (SWAYAMPRAKASHA)- इस ऑनलाईन पोर्टल की परिकल्पना 32 DTH चैनलों के एक समूह के रूप में की गई है जो, GSAT-15 उपग्रह की उपयोग करके 24 x 7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। एन.पी.टी.ई. एल., आई.आई.टी., यू.जी.सी., सी.ई.सी., इग्नू, एनसी.ई.आर.टी. और एन.आई.ओ.एस. द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है।

ई.पी.जी पाठशाला- यह ऑनलाईन पोर्टल MHRD द्वारा ICT (NMEICT) के माध्यम से साक्षरता मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। जिसका संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) करता है। हमारे देश के सभी स्नात्कोत्तर करने वाले विद्यार्थी एवं शिक्षक इसका फायदा उठा सकते हैं। यह ऑनलाईन पोर्टल 700ई.बुक प्रदान करती है।

ऑनलाईन शिक्षण की चुनौतियाँ- कोविड-19 के वैश्विक शैक्षणिक आपदाकाल में भी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सही समय पर कई सराहनहीय कदम उठाए गए, जिनसे निराशा के घोर अंधकार में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को ऑनलाईन शिक्षा की दिशा में एक नई प्रकाश की किरण मिली।

परन्तु इन सारी सुविधाओं के बावजूद भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऑनलाईन शिक्षण की चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की है। इस वास्तविकता और कड़वे सच को स्वीकार करना ही होगा कि सुदूर ग्रामीण स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ एक बड़ी समस्या स्मार्ट फोन और कम्प्यूटर की अनुपलब्धता एवं एक मजबूत इन्टरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल कॉलेजों में आधारभूत संसाधनों की कमी है, जिसमें सबसे प्रमुख बिजली की समस्या है। इस कारण सरकार द्वारा ऑनलाईन शिक्षण की कई एक सुविधाएँ प्रदान करने के बावजूद कोविड-19 के आपदाकाल में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऑनलाईन शिक्षण के उपयोग एवं दक्षता में गहरा अन्तर है एवं इस कारण इन्हे इस सुविधा से वंचित होना पड़ता है।

कुछ सुझाव एवं भविष्य की रणनीतियाँ- ऑनलाईन स्कूली शिक्षा की यह

अचानक के 'स्विच मोड' स्कूल प्रबंधन से लेकर शिक्षकों छात्रों एवं अभिभावकों के लिए काफी कष्टकर रहा है। अधिकांश शिक्षक ऑनलाईन कक्षाओं में स्विच करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास इस लॉकडाउन की स्थिति में पर्याप्त संसाधन तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव था। इस शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा नुकसान हाशिए पर रहने वाले वर्ग को हुआ है। भारत सरकार को इस कोविड-19 की वैश्विक शैक्षणिक आपदा से एक सबक लेना होगा और इस दिशा में कारगर कदम उठाने होंगे कि सभी शैक्षणिक संस्थान, खासकर ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक संस्थानों में जरूरत के संसाधनों की उपलब्धता एवं निर्माण पर बल देना होगा। स्कूलों, कॉलेजों में विशेषज्ञों तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति करनी होगी। शिक्षकों हेतु कई एक तकनीकी शिक्षण कोर्स चलाने अनिवार्य करने होंगे। अभी आपदा टली नहीं है, शिक्षकों एवं प्रबंधकों को इस दिशा में योजना बनाने होंगे ताकि पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा को ऑनलाईन चलाया जा सके ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को आगे भी लागू रखा जा सके। सरकार को इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने की दिशा में सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। योजनाएँ बनाने में कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा।

निष्कर्ष- भारत वर्ष की गुरु-शिष्य परम्परा का लोहा पूरा विश्व मानता है, इस परम्परा को ऑनलाईन शिक्षा के द्वारा निर्वाह करने का समय आ चुका है। कोविड-19 की वैश्विक शैक्षणिक आपदाकाल ने हम सभी शिक्षाविदों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी भी समस्या आ सकती है। इसके लिए हमें खुद को और अपने विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर तैयार रखना होगा। ऑनलाईन शिक्षण आज के समय की माँग है। आज समय आ चुका है कि हम सभी शिक्षक एक छात्र की तरह नई टेक्नॉलॉजी को सहर्ष सीखें एवं परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करें। कोविड-19 के काल ने डिजिटल इंडिया के संप्रत्यय को समझाया है। जहाँ तक कि संसाधनों की कमी इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है तो इस दिशा के सरकार को सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। ताकि ऑनलाईन शिक्षण कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सही ढंग से संचालित हो सके और हाशिए पर पड़े वर्ग को भी इस शिक्षा पद्धति से फायदा पहुँच सके। आज समय आ गया है कि इस विपरीत समय की चुनौतियों को संभावनाओं में बदलकर चरमरायी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। ऑनलाईन शिक्षण 'कक्षा शिक्षण' का एक विकल्प नहीं है, लेकिन इसे

कक्षा शिक्षण का एक सहायक अंग बनाना ही होगा, जिससे विद्यार्थियों एवं शिक्षक भविष्य में तनावमुक्त सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 के फैलाव संबंधी रिपोर्ट तथा कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी किए गए जनवरी 2020 से अब तक के विभिन्न रिपोर्ट, www.who.in
2. जेहन हे. वांग एवं सहयोगी (जून 2020), "प्रीवेलेंस ऑफ एंजाइटी एण्ड डिप्रेशन सिम्पटम्स इन कॉलेज स्टूडेंट्स डयूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक" जर्नल ऑफ अफेक्टिव डीसॉर्डर, 275, पृ.सं.-188-193
3. यूनेस्को की कोविड-19 पर जारी रिपोर्ट (2020)
4. <http://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures>.
5. काव, डब्लू. एवं उनके सहयोगी (2020), द साइकोलोजिकल इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19, एपिडेमिक ऑन कॉलेज, स्टूडेंट्स इन चाइना, साइकियाट्री रिसर्च, 112934
6. द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ, साइकोलोजिकल स्टेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स डयूरिंग कोविड-19 एपीडिमिक (2020)
7. अग्रवाल एस. एवं सहयोगी, इम्प्लोईंग सी.बी.पी. आर.टू. अण्डरस्टैंड द वेल बिईंग ऑफ हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स डयूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया <https://ssrn-com/abstract=362845B>
8. राजकुमार आर.पी. (2020), कोविड-19 एण्ड मेंटल हेल्थ : ए रिब्यू ऑफ द रजिस्ट्रींग लिटरेचर, एशियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, 102066
9. रागामई, एम. वी. (2020), लेवल ऑफ फौमिली बॉडिंग अमंग यंग अडल्ट डयूरिंग नैशनल लॉकडाउन डयू टू कोविड-19, ISSN-0971-2143 यू.जी. सी. केयर जर्नल, 31(12), पृ.सं.-684-698
10. यूनेस्को की कोविड-19 पर 2020 की रिपोर्ट
11. <http://en.unesco.org>
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (20 मार्च 2020) कोविड-19 डिजिटल इनिशेटिव

कोविड 19 के परिदृश्य में साहित्य और मीडिया

• डॉ. अमित शुक्ल

कोविड 19 ने सब कुछ बदल दिया। अब ऐसा नहीं रहा। यह सत्य है कि कोविड 19 के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जीवन शैली में बदलाव हो जाएगा, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। वैक्सीन आ जाने के बाद भी लोगों के मन में कहीं न कहीं कोविड 19 के प्रति एक दहशत अभी भी है और यह दहशत ही मनुष्य की जीवन शैली को पूर्णतः बदल कर रख दिया है। फिर चाहे वह समाज का कोई कार्य क्षेत्र हो। साहित्य लेखन व मीडिया भी इसमें अछूता नहीं। अध्ययन और अध्यापन के तरीके गूगल मीट, यूट्यूब में परिवर्तित हो गये। एक नया अनुभव, नयी जीवन शैली साहित्य के नये प्रतिमान। हम क्या थे, क्या हो गए। अब तो ऐसा भी हो गया है कि मनुष्य अगर घर से बाहर जाने की सोचता है तो वह तभी निकलेगा जब बेहद जरूरी हो अन्यथा वह नहीं निकलेगा। एक दूसरे से दूरी बनाये रखना भी एक जीवन शैली है। शायद इस तरह हम अपने और एक दूसरे के आभा मंडल का सम्मान करना भी सीख रहे हैं और वेवजह किसी से चिपके रहने की आदत से भी परहेज कर रहे हैं। कोविड 19 ने व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति इस महामारी के बाद हम सभी को जागरूक कर दिया है। आज सम्पूर्ण विश्व कोविड 19 वायरस से जूझ रहा है। एक अदृश्य विषाणु ने विश्व में खलबली मचा दी है। विश्व शक्ति अमेरिका, चीन, जर्मनी भी इस महामारी की मार से अपने नागरिकों को बचाने में सफल नहीं हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस विषाणु से मयभीत हो अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन ला दिया है। देखा जाए तो आज जीवन कीमती हो गया है और पैसा जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया है। कोविड 19 महामारी का यह काल हर किसी के लिए आत्मचिंतन का काल हो सकता है। अरबी काहवत है कि नरक का रास्ता बुद्धिमान, ज्ञानवान लोगों से सरोबार है। चीन से निकले हुए इस विषाणु को पूरी दुनिया में फैलाने वाले लोग अत्यंत शिक्षित, संभ्रान्त और बुद्धिजीवी स्तर के लोग हैं। विश्व में आज पहली बार

• प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय ठकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि महामारी पृथ्वी से नहीं जहाज से फैली है। कोविड 19 के साहित्यिक परिदृश्य में साहित्य और मीडिया की दुनिया भी बदल गयी है। आज डिजिटल दुनिया ने लोकल से ग्लोबल तक मानव की सोच कार्यक्षमता और काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल दिये हैं। तकनीक हमारे जीवन की बुनियादी शर्त बन चुकी है। अब परम्परा के माध्यम पीछे होते जा रहे हैं। साहित्य, शिक्षा और समाज का हर पहलू नए जमाने की मीडिया के पीछे चल रहा है। इसका प्रभाव साहित्य लेखन में भी पड़ रहा है। कोविड 19 महामारी के कालखंड में साहित्य की पुस्तकें अब पढ़ी ही नहीं जा रही बल्कि उन्हें जिया भी जा रहा है। आज सूचना और संचार हमारे विचार व्यवहार का हिस्सा बन चुके हैं। कोविड 19 और ऑनलाइन पुस्तकों का अघोषित रिश्ता जुड़ गया है। घर पर उपलब्ध नई और पुरानी पुस्तक आलमारियों की कैद से मुक्त होती जा रही हैं। यह सत्य है कि कोविड 19 ने रचनाकर्म को पूरी तरह प्रभावित किया है। पुस्तकों के प्रकाशन से लेकर उनके वितरण तक में प्रभाव पड़ा तो दूसरी ओर यह साहित्य का स्वर्णकाल भी रहा। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में साहित्य को लाभ भी पहुँचा है। कोविड 19 के शुरूआती दौर में जहाँ पुस्तकों के प्रकाशन में रोक की वजह से नयी पुस्तकों का अभाव रहा। लाकडाउन के चलते मशीन ऑपरेटर से लेकर वाइंडर कटिंग करने वाले, किताबों के कवर बनाने वाले, प्रूफ रीडर, कंपोजर आदि लोग बेहद प्रभावित रहे, इससे रोजगार भी प्रभावित हुआ। पर मीडिया के कारण पढ़ने का क्रम जारी रहा। साहित्यिक गतिविधियाँ, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य मोबाइल पर होता रहा फिर वो साहित्य हो कला, संगीत, हर तरह की पुस्तकों का लाभ मीडिया ने दिया। कोविड 19 के शुरूआती दौर के पश्चात उत्तरार्द्ध में पुस्तकों के प्रकाशन ने गति पकड़ी। वर्तमान समय में प्रकाशन जगत ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पर कोविड 19 काल ने आनलाइन पुस्तकों की बिक्री को बढ़ावा दिया है। आनलाइन साहित्यिक चर्चा, गूगल मीट, वेबिनार, संगोष्ठी आदि ने जीवन के मायने बदल दिए हैं। कोविड 19 काल में ऑनलाइन साहित्यिक गतिविधियों का स्वर्णिम युग आ गया है। डिजिटल युग के इस नये दौर ने लाइव सेशन, वेबिनार बहुत हुए। इतने सेशन पहले कभी नहीं हुए जितने कोविड 19 काल में। अब वर्तमान समय की कोविड 19 को देखते हुए लाइव सेशन का दौर कायम है। साहित्यिक

मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रोज नए-नए साहित्यिक मंच सोशल मीडिया पर तैयार हो रहे हैं। स्त्री दर्पण नामक मंच ने लेखिकाओं की साहित्यिक दुनिया ही बदल दी है। कोविड 19 काल ने कई सुस्त साहित्यिक मंच को सक्रिय कर दिया है। जिनके नाम तक कोई नहीं जानते थे, वे पुराने साहित्यिक मंच भी सोशल मीडिया में सक्रिय होकर नये-नये विमर्श को अंजाम दे रहे हैं। कुछ नए मंच बन रहे, कुछ पुराने सक्रिय हो रहे, यह साहित्यिक स्वर्णिम युग का नया दौर जारी है। प्रकाशन जगत में ही लाइव गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं। सोशल मीडिया पर आज साहित्य छा गया है। कोविड 19 का सारा प्रतिबिंब आज साहित्य में उतर आया है। मीडिया पर आश्रित होकर सभी लोग लाइव साहित्य का आनंद विचार विमर्श चिंतन-मनन कर रहे हैं। पुस्तकें, लेखन कार्य सुकून खोजने के साधन बन गये हैं। लाइव आयोजनों में पुस्तकों, रचनाओं पर सार्थक संवाद हो रहे हैं। देखा जाए तो आश्चर्यजनक ढंग से आज हिन्दी पाठकों की संख्या बढ़ गयी है। कोविड 19 काल के समय का सदुपयोग साहित्यिक लाइव सुनने और डिजिटल किताबें, ब्लाग आदि पढ़ने में किया जा रहा है। लाइव कार्यक्रम अपनी उपयोगिता व महत्व को लेकर विवादस्पद भी रहे, परंतु सत्य यही है कि कोविड 19 से उबरने के लिए मीडिया ने हिन्दी साहित्य के परिदृश्य को जीवंत रखा और लोग भी अपनी बेचैनी, असुरक्षा, भय को भूलते हुए साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ते चले गये। अब बड़े मंचों की आवश्यकता कम नजर आ रही है, युवकों ने फेशबुक, पेज, ब्लाग आदि का आरंभ कर निरंतर साहित्यिक गतिविधियों को जीवंत कर रखा है। आज युवा साहित्यकारों की रचनाओं ने मीडिया पर धूम मचायी हुयी है। रश्मि मरद्दाज का लेखन भी इसमें शामिल है उनकी पुस्तक पोएट्री जंक्शन एवं जानकीपुल, हिन्दीनामा, रचयिता, स्त्रीकाल, हिन्दगी, समन्वय स्पेस, स्त्री दर्पण, जनसुलभ पुस्तकालय, आलोचना, चिंतन साहित्यिक संस्था आदि ऑनलाइन मंचों ने अपनी निरंतर सकारात्मक भागीदारी द्वारा कोविड 19 को रेखांकित किया और नए पाठकों को जोड़ा है।

कोविड 19 काल के मीडिया में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सोशल मीडिया से जुड़े युवा रचनाकार अविनाश मिश्र का कहना है कि डिजिटल प्लेट फार्म का महत्व कोविड काल से पहले भी था, बल्कि यह भी महसूस किया गया कि यह महत्व प्रिंट में आने वाली पत्रिकाओं से अधिक

है। इस बीच कोविड ने जैसे सब जगह सब माध्यमों को प्रभावित किया वैसे ही प्रिंट पत्रिकाओं को भी। देखा जाए तो कोविड 19 काल में डिजिटल माध्यमों को लेकर असमंजस्य की स्थिति होने पर भी हिन्दी साहित्यकारों और बौद्धिकों के बीच इसे लेकर पर्याप्त गंभीरता रही है, शुरूआती दौर में कुछ भिन्नता के कारण वो ये दिखावा करते रहे कि वो इन मीडिया माध्यमों में गंभीर नहीं हैं। परंतु धीरे-धीरे कोविड 19 काल की वजह से प्रत्यक्ष साहित्य विमर्श न हो सकने के कारण मीडिया की आवश्यकता व महत्व समझ में आने लगा और मीडिया साहित्य का प्रमुख अंग हो गया है।

देखा जाए तो लाकडाउन का सकारात्मक प्रभाव साहित्य में पड़ा। इस दौरान आनलाइन बिक्री को बढ़ावा मिला और पुस्तकों का महत्व बढ़ गया। जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सारी गतिविधियां ठप्प थीं, तब 14 अप्रैल 2020 को देखो अपना देश वेबिनार सिरीज की शुरूआत की गयी, जिसकी सहायता से कोविड-19 के प्रयास से बचते हुए भारत के प्रत्येक क्षेत्र के कार्य वेबिनार के माध्यम से सम्पन्न होने लगे। वेबिनार साहित्यिक परिदृश्य में वर्तमान कोविड 19 काल के समय की आवश्यकता बन गया है। अनेक साहित्यिक मंच ऑनलाइन तैयार होकर आयोजनों में व्यस्त हैं। साहित्यिक चर्चा, चिंतन, मनन, विचार-विमर्श की समस्त गतिविधियों को वैश्विक धरातल पर लाकर साहित्य मीडिया से जुड़ गया है। यह काल कोविड 19 के साहित्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा है।

निष्कर्ष यह है कि आज सम्पूर्ण विश्व कोविड 19 से जूझ रहा है। वैक्सीन भी आ चुकी है, पर आवश्यकता अभी भी सावधानी रखने की है, इसके प्रति सचेत होकर ऑनलाइन सारे कार्य करते हुए सामाजिक बातों का ध्यान रखते हुए समस्त कार्य करने हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, वह कोई भी काल हो उसका यथार्थ चित्रण करते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। कोविड 19 समय का साहित्य भी कुछ ऐसा ही है और उसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। महान कथा सम्राज्य प्रेमचंद्र ने कहा था कि कहानियां तभी सर्वकालीन बनती हैं, जब अपने आस-पास के परिवेश और घटनाक्रम पर लिखी जाती हैं। फिर साहित्य तो समाज का वह दर्पण है, जो समाज में हो रही गतिविधियों, घटनाओं, दुर्घटनाओं का वास्तविक दस्तावेज होता है। अतः वर्तमान परिदृश्य में की गई कोई भी चर्चा कोविड-19 का उल्लेख किये बिना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए इस

काल में जो भी कहा या लिखा जाएगा वह कोविड- 19 से प्रभावित हुए बिना नहीं कहा जा सकता। कोविड- 19 को दृष्टिगत रखते हुए अब हम सभी का यह दायित्व हो गया है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग भूमिका अदा करें। फिर वो चाहे मीडिया हों, वकील हो, साहित्यकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, पूंजीपति हों, व्यापारी हों, नौकर हों, अथवा मजदूर हों सभी को कोविड- 19 से टूटी हुई कड़ी को जोड़ते हुए पुनः सभी कार्य को सुस्थिर करना है। ऐसे परिवेश में साहित्य और मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

संदर्भ सूची -

1. जनसत्ता समाचार पत्र नई दिल्ली पृष्ठ 05, 08 जुलाई 2020।
2. अमर उजाला समाचार पत्र, इलाहाबाद 03 अगस्त/पृष्ठ 04, 2020।
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र जबलपुर, 25 सितंबर 2020 पृष्ठ 05।
4. दैनिक जागरण, समाचार पत्र, इन्दौर 28 नवंबर 2020 पृष्ठ 05।
5. स्वयं का सर्वेक्षण व निष्कर्ष।

कोविड -19 का जनजातीय शिक्षा पर प्रभाव (चम्बा जिले के पंगवाल अनुसूचित जनजाति के विशेष सन्दर्भ में)

•लेख राज

हिमांचल में अविष्कृत तथा नवाचार युक्त शिक्षा जैसे जनजातीय उप योजना में आश्रम स्कूल, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, मेघा प्रोत्साहन, ज्ञानदेय, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यक्रमों ने जनजातियों में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत की। आवासीय परिसर से युक्त आश्रम, छात्रावासों में छात्र-छात्राएं अपने भविष्य के सपने गढ़ने लगे। पालको में भी बच्चों के भविष्य को लेकर भविष्य की मुस्कान दिखाई देने लगी है। सरल सहज एवं सामान्य जीवन की अभ्यस्त जनजातियों के लिए कोविड-19 का छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर विशेष प्रभाव दिखाई दिया। विद्यालय बंद हुए, अधूरा पाठ्यक्रम, परीक्षा नहीं हुई, लॉकडाउन की लम्बी अवधि ने छात्रों के ज्ञान स्तर, सीखने की क्षमता तथा पढ़ाई के प्रति अभिरूचि को प्रभावित किया। ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से कुछ प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं। किन्तु यह अभ्यास का दौर है। निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे किन्तु यह प्रयोग जनजातीय शिक्षा की दशा और दिशा के लिए सबक होगा। घरेलू कमजोर आर्थिक दशाएं, कमजोर नेटवर्क, पालकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता, शिक्षकों के साथ सतत सम्पर्क का अभाव, शिक्षकों का अन्य शासकीय कार्यों में सलग्नता, परिवार के साथ छात्रों का रोजमर्रा का जीवनचर्चा में भागीदारी, कृषि जानवरों को चराने आदि में सहयोग आदि ऐसे तथ्य हैं, जो इस महामारी के दौर में जनजातीय शिक्षा की निरंतरता में बाधक रहे हैं।

पूर्ण देश की शिक्षा स्तर पर कोरोना का प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा

• सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शासकीय महाविद्यालय टाकीपुर
जिला कांगड़ा, हिमांचल प्रदेश

जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, जिसमें से 15.18 करोड़ छात्राएं एवं 16.25 करोड़ छात्र हैं। शिक्षा पर इस प्रभाव से स्पष्ट है कि अनेक परिवर्तनों और चुनौतियों के दौर में हमें अपने शैक्षणिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को मजबूती देने की आवश्यकता है। महामारी के बाद विद्यालयों की स्थायी तकनीक एवं अवसंरचना में बदलाव लाना होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण व उनके कार्य कौशल में सुधार लाने होंगे। परिक्षाएं पारम्परिक तरीके से पृथक ऑनलाईन माध्यम से कराने की आवश्यकता होगी। एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 का दौर बीतने के बाद डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की प्रवृत्ति बढ़ेगी, कम अवधि वाले पाठ्यक्रम प्रचलित होंगे। शिक्षा जगत में नए विचारों के उदाहरण प्रस्तुत होंगे। कोरोना के दबाव के कारण विद्यालयों में डिजिटल माध्यम का एक ही प्रयोग अधिकाधिक किया जाएगा व्हाटसएप, जूम गूगल मीट टीम एप्स ई- मेल के प्रयोग में बढ़ोतरी होगी। यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों में ऑनलाईन शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के दृष्टिकोण से भारत में अच्छी गति वाली इंटरनेट की सुनिश्चितता अभी नामुमकिन है। नैशनल सैम्पल 2017-18 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 42 प्रतिशत शहरी 15 प्रतिशत ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा है यदि एक माह में एक बार इंटरनेट का प्रयोग करने वालों के इंटरनेट से जुड़ा मानें तो केवल 34 प्रतिशत शहरी एवं 11 प्रतिशत ग्रामीण लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में संस्थानों की रैंकिंग एवं नीति का विश्लेषण करने वाली ब्रितानी कम्पनी का मानना है कि मंहगी पढ़ाई में निवेश पर मिलने वाला लाभ कम होगा और कोविड-19 के बाद रोजगार के अवसर कम होंगे।

अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत अध्ययन हेतु हिमांचल के चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी का चयन किया गया, उत्तरदाता के चयन हेतु पांगी विकास खण्ड के 15 गांवों का चयन किया गया। चयनित ग्राम में से 250 पंगवाल अनुसूचित जनजाति का चयन लाटरी पद्धति के माध्यम से किया गया। चयनित उत्तरदाताओं से तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन पद्धति के माध्यम से किया गया। अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिकांश अनुसूची फोन के माध्यम से भरी गयी। अध्ययन से सम्बन्धित द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु अप्रकाशित व प्रकाशित शोध पत्रिकाएँ, समाचार पत्र-पत्रिका, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया है।

परिणाम एवं विश्लेषण -

कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय योजना- हिमांचल सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी योजना का उद्देश्य बाधा मुक्त शिक्षा प्राप्त कर जनजातीय छात्रों की शाला त्यागने की प्रवृत्ति में कमी लाना। छात्र-छात्राओं के अन्दर शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियां विकसित करना। जिसके परिणाम स्वरूप जनजातीय क्षेत्र में शाला में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्कूल बंद होने के कारण जनजातीय शिक्षा में हुए प्रभाव कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश में लॉकडाउन किया गया। इस दृष्टिकोण से जिले में ऐहतियात के तौर पर सभी शैक्षणिक संस्थान को आगामी आदेश के लिए बंद करने के आदेश हुए।

तालिका क्रमांक-01**स्कूल बंद होने के कारण जनजातीय शिक्षा पर प्रभाव**

क्र.	स्कूल बंद होने के कारण जनजातीय शिक्षा पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	छात्रों की पढ़ाई के प्रति रूचि में कमी	46	18.4
2.	अधिकतम समय खेलकूद में बिताते हैं	70	28
3.	व्यवहार में परिवर्तन	90	36
4.	बच्चों में निरक्षा तथा उदासीनता बढ़ रही है।	35	14
5.	लागू नहीं	9	3.6
	योग	300	100

तालिका क्रमांक 01 में स्कूलों के बंद होने के कारण जनजातीय शिक्षा पर हुए प्रभाव के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अधिकतम 36 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। बच्चें अब जिद्दी तथा पालकों की आज्ञा का पालन नहीं करते। 28 प्रतिशत उतरदाताओं ने माना कि अधिकांश बच्चों का समय अब पढ़ाई से हटकर खेलकूद में ज्यादा लगने लगा है। 18.4 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति रूचि कम हो गई है। 14 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि बच्चों को स्कूल जैसा वातावरण नहीं मिलने के कारण बच्चे अब पढ़ाई से जी चुराने लगे हैं।

शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता- शहरी या अन्य आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्गों के बच्चों को सभी प्रकार की शैक्षणिक संसाधनों की पूर्ति उनके पालक कर सकते हैं किन्तु जनजातीय परिवारों में अधिकांश पालक अशिक्षित होते हैं, वे अपने बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों के सहयोगी के रूप में देखते हैं। वनोपज, जानवरों को चराने,

लकड़ी एवं खेती करने जैसे कार्यों में उनका सहयोग लेते हैं। अध्ययन के दौरान जनजातियों के घरों में शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता संबंधी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को तालिका क्रमांक 02 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक-02
शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवृत्ति

क्र.	शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	घर में विद्यालय जैसे सुविधाएँ नहीं होने के कारण छात्र पढ़ाई नहीं करते।	113	45.2
2.	नक्शा, प्रयोग सामग्री, लाइब्रेरी या अन्य शिक्षण सामग्री नहीं है।	70	28
3.	आर्थिक समस्या।	40	16
4.	लॉकडाउन के कारण शहर जाकर सामग्री क्रय नहीं कर पा रहे।	19	7.6
5.	लागू नहीं।	8	3.2
	योग	300	100

तालिका 02 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकतम 45.2 प्रतिशत उतरदाताओं ने घर में विद्यालय जैसी परिस्थितियाँ उपलब्ध न होने के कारण से बच्चों के लिए ऑनलाईन कक्षा को व्यावहारिक रूप से शिक्षा हेतु अनुपयुक्त माना। वहीं 28 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि उनके घरों में नक्शा प्रयोग सामग्री लाइब्रेरी या अन्य शिक्षण सामग्री का अभाव है 16 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि बच्चों को शिक्षण सामग्री की उपलब्धता के विषय में कोई ध्यान नहीं देते उनका अधिकांश समय खेल-कूद में ही बीतता है, परिवार की आर्थिक समस्या के कारण वे इन संसाधनों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं। 7.6 प्रतिशत उतरदाताओं का कहना था कि लॉकडाउन के कारण वे शहर जाकर सामग्री क्रय पाने में असमर्थ हैं। 3.2 प्रतिशत उतरदाताओं पर यह लागू नहीं होता।

अधूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पढ़ाई जारी रखने की समस्या स्कूल बंद होने के पश्चात कक्षाओं के लगने का क्रम भी बंद हुआ पाठ्यक्रम अधूरे रहे जिन्हे पूरा करने तथा कक्षाएँ पुनः जारी करने की चुनौतियाँ सामने आईं। अध्ययन के दौरान इन समस्याओं को ज्ञात करने का प्रयास किया गया प्राप्त तथ्यों को तालिका क्रमांक 03 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक-03**अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा कर पढ़ाई पुनः जारी रखने की समस्या**

क्र.	अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा कर पढ़ाई पुनः जारी रखने की समस्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पिछली पढ़ी अधिकांश पाठ भूल चुके।	100	40
2.	स्मरण शक्ति एवं सीखने की क्षमता कम हो गई।	50	20
3.	बच्चों में परीक्षा न होने की चिंता।	60	24
4.	पालकों की परेशानियां।	27	10.8
5.	लागू नहीं।	13	5.2
	योग	300	100

तालिका क्रमांक 03 में तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके बच्चे पिछली पढ़ी हुई अधिकांश चीजे भूल चुके हैं। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परीक्षा न होने के कारण छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके बच्चों की कक्षाएं बंद होने के कारण अभ्यास और सीखने का क्रम भी बंद हो गया, जिसकी वजह से उनकी स्मरण शक्ति कम हो गई है 10.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि छात्र के साथ पालकों के लिए भी उनकी छूटी पढ़ाई जारी रखने के लिए समस्यापूर्ण है। 5.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए यह प्रश्न लागू नहीं होता। **संचार साधनों का अभाव-** संचार क्रांति के दौर में जनजातीय समाज तक इनकी पहुंच का स्तर आज भी न्यून है।

तालिका क्रमांक 04**संचार साधनों का अभाव**

क्र.	संचार साधनों का आभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	टेलीविजन नहीं है।	40	16
2.	परिवार में मात्र एक मोबाईल है।	98	39.2
3.	समाचार पत्र नहीं पढ़ते।	60	24
4.	बिजली एवं पक्की सड़क नहीं है।	42	16.8
5.	लागू नहीं।	10	4
	योग	300	100

अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका क्रमांक 04 में प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकतम 39.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में एक ही मोबाईल है, जो घर का मुखिया चलाते हैं। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के

अनुसार वे समाचार पत्र नहीं पढ़ते क्योंकि उन तक समाचार पत्र नहीं पहुंच पाती। वहीं 16 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि उनके घर में टेलीविजन नहीं है। 04 प्रतिशत उतरदाताओं के लिए यह प्रश्न लागू नहीं होता।

निष्कर्ष एवं सुझाव- कोविड-19 की अनिश्चितता के समय में लॉकडाउन से हुए दुष्प्रभावों के कारण शैक्षणिक संस्थाओं के बंद होने से छात्रों में शिक्षा के प्रति रूचि विकसित करना चुनौतियों से भरा होगा। कोरोना संकट के दौरान ऑनलाईन पढ़ाई विद्यार्थियों का सहारा तो बनी लेकिन बच्चों को मोबाईल की लत लग गई। विद्यालय बंद होने से छात्रों की शिक्षा के प्रति रूचि कम हो रही है। मोबाईल पर वर्चुअल कक्षाओं ने बच्चों के आंख-कान कमजोर कर दिए हैं, कईयों की सुनने की शक्ति कमजोर हुई तो कईयों की आंखें बच्चे मोबाईल एडिक्शन डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। इनमें चिड़चिड़ापन आ गया तथा वह अकेले में रहना पसंद करने लगे हैं। पढ़ाई की जगह बच्चों का रूझान सोशल मिडिया और गेम्स खेलने की तरफ बढ़ गया। छात्र अब मोबाइल तथा खेलकूद में अधिक समय बिताने लगे। आर्थिक स्थिति से कमजोर जनजातीय परिवारों में एनड्राइड मोबाईल नहीं होता है, जिसमें वो ऑनलाईन कक्षा में भाग नहीं ले पा रहे। गिने चुने परिवारों में मात्र एक ही स्मार्ट फोन है जो उनके पालक रखते हैं। कमजोर नेटवर्क की समस्या के कारण भी ऑनलाईन कक्षाएं प्रभावित हो रही। कई इलाकों में बिजली भी समस्या के रूप में है। संचार सुविधा के कमी के कारण कोई भी सूचना छात्रों तक सही समय पर नहीं पहुंचा पा रही। अधिक समय तक मोबाईल के उपयोग के कारण आंखों में जलन, सिरदर्द जैसी समस्या छात्रों में हो रही है। अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने व पुनः कक्षाएं प्रारम्भ करना छात्रों एवं पालकों के लिए चिंतनीय विषय है।

सुझाव- शिक्षकों व छात्राओं को डिजिटल तकनीकी से युक्त शिक्षण प्रणाली हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाईन कक्षा हेतु सहायता से पालक एवं छात्रों को ऑनलाईन शिक्षा की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी दी जानी चाहिए। लाउडस्पीकर के माध्यम से मोहल्ले में सोशल डिस्टैंस बनाकर कक्षाएं लगाना बेहतर विकल्प हो सकता है। छूटे हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु छात्र, शिक्षक के साथ पालकों के भी सहयोग की आवश्यकता होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. हसनैन, नदीम, जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर, नई दिल्ली, 1977
2. Negi, T.S., Scheduled Tribes of Himachal Pradesh. A profile, Merruit, 1976.
3. Chudhary, Minakshi, Exploring Pangi Himalaya, Indus publication company, New Delhi, 1998.
5. <https://www.google.comamp/s/m.punjabkesri.in/blog/news/locked-down-corona-virus-study-unesco-1177955%3famp>.

कोरोना संक्रमण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव (ग्राम हाटी, जिला सतना के विशेष संदर्भ में)

• विमलेश द्विवेदी

•• प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल

प्रस्तुत शोध पत्र का विषय कोरोना संकट के कारण ग्रामीण समाज पर प्रभाव है। इस शोध पत्र के अध्ययन के लिए सतना जिले के ग्राम हाटी का चयन किया गया है। इस शोध पत्र में अध्ययन के लिए सविचार निदर्शन प्रणाली के माध्यम से 50 ग्रामीण समाज के व्यक्तियों का चयन किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं का अध्ययन कर हमने पाया कि ग्रामीण समाज के व्यक्तियों को कोरोना वायरस से रोकथाम की जानकारी है। आज इस वायरस ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किया है। कोविड-19 के प्रभाव से निम्न वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के लोगों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा ग्रामीण समाज के लोग अपने गाँव तक ही सीमित रह गये हैं।

शोध समस्या: अवधारणात्मक विवेचना - कोरोना वायरस बीमारी (कोविड - 19) एक संक्रामक बीमारी है, जो एक नये वायरस की वजह से हो रही है, कोविड - 19 की चपेट में आये ज्यादातर लोगो को हल्के से लेकर मध्यम लक्षण अनुभव हुए हैं और वर्तमान समय में यह वायरस निरंतर अपना स्वरूप बदल रहा है। इसलिए इस बीमारी के लक्षण भी समय-समय के साथ बदलते जा रहे हैं। कोविड- 19 बीमारी वाला वायरस उन बूंदो से फैलता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छीकने या सांस लेने से पैदा होता है, ये बूंदे बहुत भारी होती है, इसलिए ज्यादा देर तक हवा में नही रह पाती है और तुरन्त ही फर्स या सतह पर पर गिर जाती है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत नजदीक हो तो कोविड - 19 से पीड़ित है तो सांस लेने पर आप भी संक्रमित सतह को छूते है और उसके बाद आँख, नाक या मुंह छूते हैं तो ऐसा करने पर आप भी संक्रमित हो सकते है।

- शोधार्थी, समाजशास्त्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)
- प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) 486001

कोविड - 19 की महामारी मानवता के लिये इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कोविड - 19 की व्यापकता और इसका प्रभाव इतना है, जो अब से पहले किसी अन्य महामारी में नहीं देखा गया था। इसने न केवल मानव जीवन और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है, लाखों लोगो की नौकरियां इस महामारी के चलते चली गईं। आज पूरा विश्व वायरस की चुनौती से जूझ रहा है। सरकारों के सामने चुनौती इस बात की है कि वो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को रफतार देने का काम कैसे करें। कोविड- 19 की वैश्विक महामारी ने दुनिया के आर्थिक सामाजिक आयाम को एक नए संकट की तरफ खड़ा कर दिया है।

भारत में कोरोना वायरस की स्थिति- भारत में कोविड-19 के संक्रमण में मार्च 2021 के महीने से बड़ा इजाफा देखने को मिला है। इस ट्रेंड को लोग कोरोना की भारत में दूसरी लहर के रूप में देख रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हालात को लेकर आगाह करते हुए कहा कि आने वाला समय और भी बुरा साबित हो सकता है। अखबार ने देश की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ. वी.के. पाल के हवाले से कहा है, ये चिंता की स्थिति है। कुछ राज्यों में चिंता विशेष रूप से ज्यादा है, लेकिन कोई भी राज्य आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। रुझान बता रहे हैं कि वायरस अभी भी बहुत सक्रिय है और हमारे डिफेंस को तोड़ने में सक्षम है और जब हम सोच रहे थे कि हमने वायरस को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, तो यह वापस आ गया। पकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 31 मार्च को खत्म होने वाले सप्ताह में हर दिन औसतन 62,000 नए मामले सामने आए। यह पाँच महीनों में दर्ज किए गए नए मामलों का सबसे अधिक साप्ताहिक औसत है।

16 सितंबर 2020 को खत्म होने वाले सप्ताह में कोरोना की भारत में पहली लहर देखी गई जब लगभग 93,000 सामने आए। वर्तमान में, रोजाना सामने आने वाली टैली इसका लगभग 67 प्रतिशत है, और ये संख्या अभी भी बढ़ रही है। सितंबर 2020 के मध्य में देश में दैनिक कोरोना संक्रमण की रफतार उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी। उन दिनों यह हर दिन

93 हजार के स्तर पर पहुँच गई थी। लेकिन इसके बाद इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। फरवरी 2021 के मध्य तक हर दिन सिर्फ 11 हजार मामले आ रहे थे। हर दिन मरने वालों का साप्ताहिक औसत भी घट कर 100 के नीचे पहुँच गया था। इस तरह दिसंबर 2020 तक भारत में यह मान लिया गया था कि अब कोरोना वायरस नियंत्रित हो गया है और भारत अब इस समस्या से निजात पा चुका है। इसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भी कहा था कि अब भारत को लेना संक्रमण के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। किंतु फरवरी 2021 के आखिर में चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों की 824 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों को चुनने वाले वोटों की संख्या 18.60 करोड़ है। 27 मार्च 2020 से शुरू हुई वोटिंग को एक महीने से भी अधिक समय तक चलना था। पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव का एलान किया गया। इसके बाद चुनाव प्रचार पूरे जोर-शोर से शुरू हो गए। इन चुनाव क्षेत्रों में न तो कोई सेफ्टी प्रोटोकाल अपनाया जा रहा था और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। इस बीच, मध्य मार्च 2021 में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच दो अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों को देखने के लिए एक लाख 30 हजार दर्शकों को इजाजत दे दी गई। इनमें से ज्यादातर बगैर मास्क पहने आए थे और फिर इसके एक महीने के अंदर मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। भारत एक बार फिर कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गया। कोरोना संक्रमण की यह दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है और इसने भारत के शहरों को बुरी तरह जकड़ लिया है। इस वजह से कई जगहों पर नए सिरे से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में मध्य अप्रैल 2021 तक हर दिन संक्रमण के लगभग एक लाख मामले आने लगे।

अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत शोध आलेख कोरोना कोविड -19 के कारण ग्रामीण समाज पर प्रभाव के तथ्यों सामाजिक मापदण्ड एवं कारकों को विश्लेषित करने के उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत किया गया है, इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- कोविड- 19 की व्यापकता और इसका प्रभाव कितना है इसकी जानकारी प्राप्त करना।
- कोरोना संकट के कारण ग्रामीण समाज पर कितना प्रभाव पड़ा है

इसकी जानकारी प्राप्त करना।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना नुकसान हुआ है, इसका पता लगाना।
- भविष्य में कामकाजी वर्ग का स्वरूप कैसा होगा इसकी जानकारी प्राप्त करना।
- कोविड-19 के बाद के दफ्तर और दूसरे कामकाजी स्थल कैसे होंगे, इसका पता लगाना।
- कोविड-19 के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना।
- कोविड-19 का सामाजिक, आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण- प्रस्तुत शोध में सविचार निदर्शन प्रणाली द्वारा 50 ग्रामीण उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। निदर्शन विधि द्वारा चुने गये उत्तरदाताओं से प्राथमिक सामग्री के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार विभिन्न स्रोतों से सामग्री संग्रहित करके द्वितीय स्रोतों का भी प्रयोग किया गया है। संकलित स्रोतों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया है।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण - प्रस्तुत शोध क्षेत्र गाँव हाटी है, हाटी सतना जिले से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 2858 है, जिसमें 45 प्रतिशत महिलाएँ 10 प्रतिशत बच्चे और 50 प्रतिशत पुरुष हैं। उक्त ग्राम में ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ग के लोग निवास करते हैं। ग्राम पंचायत हाटी में स्कूलों की संख्या 03 है। 01 चिकित्सालय है तथा इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल भी निर्मित हैं। यहां पर रेलवे स्टेशन भी स्थापित है, जहां पर रेल रुकती है व आती जाती है।

उपकल्पना - इस शोध पत्र के विषय से संबंधित हमारी उपकल्पनायें इस प्रकार हैं-

1. कोविड - 19 से बचने के लिए सार्वजनिक जगहों को बेहतर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है।
2. इस महामारी से बचने के लिए ग्रामीण समाज में सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है।
3. इस महामारी से बचने के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है।

4. शैक्षणिक विकास के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है।
5. कोविड - 19 के कारण ग्रामीण समाज के अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।
6. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा - कोरोना वायरस के संबंध में डॉ. रंजना, डॉ. शेखर सी माण्डे, डॉ. शैलजा वैद्य गुप्ता, डॉ. गीता वाणी, डॉ. अनुराग अग्रवाल, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वाई माधवी आदि ने हाल ही में कुछ अध्ययन किए हैं।

तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण - प्रस्तुत शोध पत्र तैयार करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हुए उत्तरदाताओं के पास कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए तथ्य एकत्रित किए गए जिनका विश्लेषण नीचे तालिकाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है-

सारणी क्रमांक- 01

क्या आप माक्स पहनते हैं?

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	माक्स पहनते हैं	45	90 प्रतिशत
2	माक्स नहीं पहनते हैं	05	10 प्रतिशत
	कुल योग	50	100

उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कोरोना संकट का ग्रामीण समाज पर प्रभाव “ग्रामीण समाज के 50 व्यक्तियों से प्रश्न पूछा गया कि क्या आप माक्स पहनते हैं या नहीं तो उनके उत्तर 90 प्रतिशत ने कहा है, हाँ हम पहनते हैं, सावधानी ही सुरक्षा है और 10 प्रतिशत व्यक्तियों के उत्तर नहीं थे। जिनके उत्तर नहीं थे, उनमें अशिक्षा और अज्ञानता पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में कोरोना संकट की जानकारी का स्तर ज्यादा है।

सारणी क्रमांक- 02**क्या आप सामाजिक दूरी का पालन करते हैं?**

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	सामाजिक दूरी का पालन करते हैं	47	94 प्रतिशत
2	सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं	03	06 प्रतिशत
	कुल योग	50	100

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में कोरोना से संबंधित 50 व्यक्तियों से प्रश्न पूछे गये कि आप सामाजिक दूरी का पालन करते हैं, तो 94 प्रतिशत व्यक्तियों ने हाँ कहा है तथा से सामाजिक दूरी का पालन करते हैं और 06 प्रतिशत लोगों के उत्तर नहीं थे इसमें वे व्यक्ति शामिल थे जो व्यक्ति वृद्ध हैं व घर से नहीं निकलते हैं और कुछ में शिक्षा की कमी पाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हैं उनमें कोविड-19 की जानकारी ज्यादा है।

सारणी क्रमांक- 03**क्या आप कोविड वैक्सीन को महत्व देते हैं?**

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कोविड वैक्सीन को महत्व देते हैं	46	92 प्रतिशत
2	कोविड वैक्सीन को महत्व नहीं देते हैं	04	08 प्रतिशत
	कुल योग	50	100

उपरोक्त सारणी क्रमांक 03 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के 92 प्रतिशत लोग वैक्सीन को महत्व देते हैं और 08 प्रतिशत व्यक्ति के उत्तर नहीं थे, उनमें अशिक्षित वर्ग के व्यक्ति तथा वृद्ध महिलाएँ तथा पुरुष शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के व्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीन की जानकारी का स्तर ज्यादा है।

सारणी क्रमांक- 04**क्या आप लॉकडाउन से सहमत हैं?**

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	लॉकडाउन से सहमत हैं	10	20 प्रतिशत
2	लॉकडाउन से सहमत नहीं हैं	40	80 प्रतिशत
	कुल योग	50	100

उपरोक्त सारणी क्रमांक 04 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के 20 प्रतिशत लोग लॉकडाउन से सहमत है उनका कहना है कि जब बाहरी व्यक्ति गाँव के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा तो कोविड -19 से बचाव हो सकता है, और 80 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तियों का जवाब न था जिन्होंने न कहा है जिनमें श्रमिक वर्ग के महिला व पुरुष है, जिनका जीवन यापन मजदूरी या अन्य कार्यों से चलता है। इसमें स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के व्यक्तियों को लॉकडाउन की जानकारी का स्तर ज्यादा है।

सारणी क्रमांक- 05

क्या इस वायरस से शिक्षा प्रभावित हुई है?

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षा प्रभावित हुई है	45	90 प्रतिशत
2	शिक्षा प्रभावित हुई नहीं है	05	10 प्रतिशत
	कुल योग	50	100

उपरोक्त सारणी क्रमांक 05 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के 50 व्यक्ति से प्रश्न पूछ गये कि इस वायरस से शिक्षा प्रभावित हुई तो 90 प्रतिशत व्यक्तियों का कहना था हाँ इस वायरस ने शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित किया है और 10 प्रतिशत लोगों के उत्तर न थे जिनमें अशिक्षित वर्ग के व्यक्ति भी शामिल थे। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के व्यक्तियों को इस वायरस से शिक्षा प्रभावित हुई है जिसकी जानकारी का स्तर ज्यादा है।

निष्कर्ष - आई. आई. टी. के वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ग्रामीण समाज में गति उतनी नहीं दिखी, जितनी अपेक्षित थी। ग्राम हाटी में कोविड-19 की जानकारी आधिक दिखाई देती है। उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज के 100 प्रतिशत में 90 प्रतिशत लोग माक्स पहनते हैं। 94 प्रतिशत व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हैं और केवल 06 प्रतिशत व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं। 100 प्रतिशत में 92 प्रतिशत व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन को महत्व देते हैं और 08 प्रतिशत लोग नहीं देते हैं। 20 प्रतिशत लोग लॉकडाउन से सहमत हैं और 80 प्रतिशत लोग लॉकडाउन से सहमत नहीं हैं। उनमें निम्न वर्ग और श्रमिक वर्ग के व्यक्ति हैं। ग्रामीण समाज के व्यक्तियों में 100 प्रतिशत में 90 प्रतिशत व्यक्तियों का कहना है कि इस वायरस से शिक्षा प्रभावित हुई है और 10 प्रतिशत लोग के उत्तर न थे

इसमें शिक्षा की कमी पाई गई है। अतः कोविड-19 के कारण ग्रामीण समाज पर प्रभाव अत्यधिक मात्रा में देखने को मिला है।

सुझाव -

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के लिए साफ-सफाई को विशेष महत्व दिया है। तथा साफ-सफाई को विशेष तौर पर महत्व देना चाहिये, जिससे कोविड-19 से बचा जा सकता है।
2. जो लोग छींक रहे हों, उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए।
3. लोगो को बार-बार अपने चेहरे, नाक और आँखो को छूने से बचना चाहिए।
4. कोरोना वायरस के इंफेक्शन से बचने के लिए अपने कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखे, इससे इस वायरस के कम होने की संभावना होती है।
5. दरवाजे, खिड़कियों को खुला रखकर बाहरी हवा में सांस ले तो कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है।
6. अगर आपको बुखार, खांसी और जुखाम हो तो खुद को अपने घर या किसी सरकारी सुविधा वाली जगह पर क्वारंटाइन में रखें।
7. लोगो को एक-दूसरे से दूर रहना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों में भीड़ नही बढ़ानी चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार धोना चाहिए तथा छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए।
8. हाथ धोने के बाद टिशू का प्रयोग करे तथा निश्चित रूप से माक्स को लगाये रहें तभी कोविड-19 से बचा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. मुखर्जी रवीन्द्र नाथ (2000) सामाजिक शोध व सांख्यिकी विवेचना, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली यू. ए. जवाहर नगर नई दिल्ली
2. भारत की जनगणना
3. इन्टरनेट
4. न्यूज पेपर
5. टेलीविजन
6. <https://www.bbc.com/hindi/india>

कोरोना वायरस की चुनौतियां और भविष्य

• डॉ. अलका नायक

कोरोना महामारी 2019-20 की शुरुआत कोरोना वायरस संक्रमण के रूप में चीन के बुहान प्रांत से हुई। खुली अर्थव्यवस्था के इस दौर में वैश्वीकरण उदारीकरण के इस युग में एक देश की घटना का संक्रमण का, गतिविधियों का पूरे विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि व्यापारिक तौर पर सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी देश से कच्चा माल लिया जाता है कहीं पर किसी दूसरे देश से तकनीकी और किसी देश में उसका निर्माण होता है और अन्य देश में जाकर उसका व्यापार होता है, बाजार होता है अतः सभी देशों में एक दूसरे का आना-जाना अर्थात् व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध बना रहता है अतः कोरोना वायरस जिसकी चीन से शुरुआत हुई, दिसंबर 2019 में ही चीन में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए थे। 31 दिसंबर 2019 में डब्ल्यूएचओ ने इसे संज्ञान में लिया था, फिर 4 जनवरी 2020 में डब्ल्यूएचओ ने उसको गोल-मोल भाषा कहते हुए इसे साधारण संक्रमण करार दिया था। इसके उपरांत 11 मार्च 2020 में डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी के रूप में चिन्हित किया तब तक संक्रमण काफी देशों में फैल गया था। कई देशों से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग चिन्हित किए जा रहे थे। धीरे-धीरे अन्य देशों में भी फैल गया। साधारण खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया से व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी और वेंटीलेटर तक होता हुआ मौत के मुंह में चला गया।

इसे तृतीय युद्ध के रूप में भी देखा जा रहा है जो मिसाइल राकेट परमाणु बम से न लड़कर बायोलॉजिकल युद्ध के रूप में हो रहा है जिससे मानव अस्तित्व खतरे में आ गया है। विश्व स्तर पर यह भी एक चुनौती है कि कोरोना वायरस बायोलॉजिकल युद्ध है या स्वाभाविक रूप से प्रकृति द्वारा होने वाला संक्रमण है, जिसने महामारी का रूप धारण कर लिया है। यह महामारी पहली महामारी नहीं है। इससे पहले भी 1918-20 में स्पेनिश फ्लू, 1957 में एशियाई फ्लू, 2002 में सारस वायरस के द्वारा महामारी 2009 में

• एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गांधी महाविद्यालय उरई

h1 n1 फ्लू, 2016-18 में ईबोला वायरस द्वारा अधिकांश संक्रमण फैला, यह बात अलग है कि इसका असर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हुआ। विश्व स्तर पर अवलोकन करने पर स्थितियां बड़ी भयावह हैं विश्व स्तर पर से 196 देशों को प्रभावित करने वाला कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण और उसके उपरांत मौत के आंकड़े निम्नवत् हैं।

कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की संख्या में अमेरिका, भारत, ब्राजील, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली आदि रहे, जिसमें विश्व स्तर पर कुल कोरोना वायरस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 170257758 और कोरोना से मरने वालों की संख्या 3540440 एवं कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वाले केस 15, 22 98832 रहे भारत में कोरोना संक्रमित केस 27,7 52,96 2 हैं एवं 25,2 27,740 लोग ठीक हुए एवं 3, 22,982 लोग काल कवलित हो गए। कोविड-19 ने सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक कई चुनौतियों को विश्व स्तर पर रख दिया है। लगातार बड़े-बड़े शोधकर्ताओं चिकित्सा से जुड़े हुए विशेषज्ञों, जानकार लोगों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं तथा वैक्सीन वैक्सीनेशन को महत्व देते हुए कोशिश की जा रही है, अधिकतम लोगों को वैक्सीन लग जाए ताकि संक्रमण की चैन सिस्टम टूट सके।

कोविड-19 के समक्ष चुनौतियां- कोविड-19 कम्युनिटी इंफेक्शन है अतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति संक्रमित होता है, ऐसी स्थितियों में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा अभियान चलाया गया। लॉकडाउन लगाया गया, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू, 25 मार्च 2020 से लगातार लॉकडाउन कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, थोड़े समय के लिए जरूर ऐसा लगा कि कोरोना कि वेव लहर थम गई किंतु दोबारा की दूसरी लहर आई, जिसने भारत को बहुत हिला दिया क्योंकि भारत दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं था पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।

कोविड-19 के सामाजिक प्रभाव- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में सभी लोगों की सुख-दुख को बांटने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। एक दूसरे के सहयोग से सभी कार्य किए जाते हैं। शादी-विवाह में लोगों की उपस्थिति की संख्या, श्मशान घाट में क्रिया-कर्म करते वक्त भी एक निश्चित संख्या में लोगों की उपस्थिति अनिवार्यता बन गई और लोग

एक-दूसरे के इन दुख और सुख में भी शामिल ना हो सके। कोविड-19 की लहर ने लोगों को आत्मकेंद्रित कर दिया। मानवीय संवेदनाओं की धज्जियां उड़ गईं। लोग अपने प्रियजनों के इलाज के लिए उनकी मौत पर जाने में संकोच करने लगे, उनसे बात करने में संकोच करने लगे, अस्पृश्यता जैसा भाव लोगों के अंदर जागृत हुआ यह खतरनाक स्थिति हुई। लॉकडाउन की स्थिति में लोग घरों में कैद हो गए घरों में भी अलग-अलग कमरों में सिर्फ टी.वी., मोबाइल जैसे उपकरण उनके साथी रह गए, इंसान से इंसानियत चली गई, धार्मिक स्थल बंद हो गए, धार्मिक आस्थाओं को भी चोट पहुंची।

कोविड-19 के राजनैतिक प्रभाव- जिन राज्यों में कोविड-19 के दौरान अस्पतालों में सही व्यवस्था ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की उपलब्धता डॉक्टरों द्वारा कार्य की अधिकता एवं संक्रमण रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई, वहां आगामी चुनाव में जीत के लिए नए तरीके से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है, जनता में एक आक्रोश है, जिसका सामना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करना पड़ रहा है।

कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु सब्जी, किराना, दवाई आदि दुकानों को छूट दी गई, उनके लिए समय निश्चित किया गया ताकि आम जनता तक वह पहुंच सके, वहीं राजस्व प्राप्ति हेतु शराब की दुकानों का खुला होना और शराबियों का कोविड-19 के नियमों का पालन न करना, आपस में लड़ाई-झगड़ा और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं एक चुनौती के रूप में उभरी। राजनीतिक दलों द्वारा तरह-तरह के एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना, जाति विशेष की राजनीति करना, धार्मिक ध्रुवीकरण चिंता का विषय बना।

कोविड-19 का शिक्षा पर प्रभाव- शिक्षा का अर्थ सीखना है, जिसमें अनुभव द्वारा विवेक जागृत होना शामिल है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना, धन आपूर्ति नहीं है। शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास में नैतिक मूल्यों संवेदनाओं का विकास आध्यात्मिक विकास भी शामिल है, लेकिन शिक्षा से यह भाव पहले ही विलुप्त हो रहे थे, कोविड-19 ने स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थानों को लगातार बंद किया। शिक्षा बाधित हुई, शैक्षिक गतिविधियां अवरोधित हुईं। नए सिरे से ऑनलाइन फार्म ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुईं, जिसकी वजह से केवल बच्चों को शिक्षा या शिक्षकों से संस्थानों से जुड़े रखने जैसा कार्य चल रहा है, लेकिन शिक्षा में जो एक

आपसी तालमेल, सद्भाव, शिक्षण विधियाँ, शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ शामिल होती, उनका विलोपन निश्चित तौर पर एक चुनौती के रूप में उभरा है।

कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव- समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जीडीपी का गिरना, शेयर बाजार, सोना बाजार, वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की मांग, पर्यटन, व्यापार सभी प्रभावित हुआ। असंगठित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार का उपलब्ध ना होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मध्यमवर्ग पर पड़ा है क्योंकि वह ना तो भीख मांग सकते हैं ना तो छोटे कार्य कर सकते हैं ना ही उनके पास इतना धन संचय है कि बरसो बैठ कर खा सकते हों। सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से जनता के पास धन उपलब्ध हो इसके लिए ब्याज दरों में भी काफी कटौती की जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है ताकि लोग बैंकों के माध्यम से ऋण ले सकें और अपने उपभोग को बढ़ा सकें, क्योंकि अगर उपभोग का स्तर गिरेगा तो उत्पादन स्वतः ही गिरेगा।

मजदूरों और किसानों की चुनौतियाँ- लगातार लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों गरीब मजदूर प्रभावित हुए कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का धंधा चौपट हो गया लोगों के पास पैसों की इतनी किल्लत हो गई कि उनके लिए दो जून की रोटी भी मुश्किल हो गई अतः खाद्य सुरक्षा एवं खाद उपलब्धता एक चुनौती बन गई।

कोविड-19 का भविष्य- कोरोना महामारी के महासंकट में वैश्विक नेतृत्व का अभाव साफ नजर आ रहा है सभी देश तरह-तरह की वैक्सीन को कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर मान रहे हैं, किंतु कोई वैक्सीन पूर्णता सुरक्षित होने की बात नहीं कही जा सकती, अतः सुरक्षित वैक्सीन के लिए नए-नए म्युटेंट के लिए वैक्सीन की खोज जारी रहेगी एवं भविष्य में भी ऐसी आपदा के लिए सभी देश सजग रहेंगे। अनुसंधान करते रहेंगे, तैयारियां रखेंगे ताकि यह भयावह स्थिति पैदा ना हो। मानवता उस दिशा में बढ़ गई जहां पर सरहदें घरों पर दस्तक दे रही हैं एवं साइबर दुनिया में हलचल मच गई है। साइबर क्राइम एवं सामान्य वारदातें चोरी, डकैती, अपहरण यह सारी बातें देखने को मिल सकती हैं। दफ्तरों कमरों घरवाली मानव सभ्यता ने वर्चुअल मानव समाज को जन्म दे दिया है। वर्क फ्राम होम जैसा कांसेप्ट आया। मानवता का इतिहास दोनों

अलग-अलग सभ्यताओं का तालमेल करने पर करने वाले चौराहे पर खड़ी है। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के देशों में कामकाज के तरीकों में व्यापक बदलाव किए हैं और भविष्य में भी इन्हें ध्यान में रखते हुए दफ्तरों, कालेजों, ऑफिस को सुसज्जित किया जाएगा जहां पर सुरक्षा का, मास्क अनिवार्यता का, थर्मल स्क्रीनिंग का, कर्मचारियों की संख्या का उनकी आपस में दूरी का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा, साथ साथ कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पूर्ण नहीं होती है, एक ही लिफ्ट से लोगों का आना-जाना होता है जो कि संक्रमण का प्रमुख स्रोत है। विश्व स्तर पर चिंतन और विचारणीय महत्वपूर्ण बात है इस तरह के जीव रक्षा के अजैविक हमले वाले हत्यारों पर पूरी तरह से पाबंदी एवं जैविक तकनीकी के विकास और रिसर्च पर बड़ी कड़ी निगरानी हो ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। विकसित देश और विकासशील दोनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताएं विशेष तौर पर समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, उनके लिए अन्य बजट व्यवस्था भी करनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के बाद की दुनिया व्यापक आर्थिक मंदी के संकेत दे रही है।

वैश्वीकरण की परिभाषा वर्तमान स्वरूप भविष्य में अपने मूल स्वरूप को खो देगा क्या देशों के बीच व्यापार समझौते चलते रहेंगे? डब्ल्यूएचओ जैसी वैश्विक संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर गंभीर आरोप लगाए एवं डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली सहायता राशि को भी बंद कर दिया कि वह विश्व अर्थव्यवस्था को बदलने एवं चीन को विकासशील देश मानते हुए विशेष लाभ और सहयोग कर रहा है और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली सहायता राशि की कटौती, बहु प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र की विफलता कोविड-19 पर चर्चा पर रोक लगाना उसे भी संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बनते इन नए समीकरणों के बीच हर देश अपनी नई भूमिका को स्थापित करने की कोशिश करेगा। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा नई तकनीकी नए-नए विश्वास के साथ अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेगा।

नवीन परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा जन व्यवस्था और समाज सेवा (कोविड-19 के विशेष संदर्भ में)

• प्रो. प्रियंका तिवारी
•• प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल

नवीन परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संदर्भ में पुलिस द्वारा जन व्यवस्था और समाज सेवा के दो दृष्टिकोण, प्रथम कानून व्यवस्था का पालन कराना और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने को क्रियाशील करना भारतीय समाज के समक्ष आए। लॉकडाउन को जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया। पुलिस के कार्यों में जनता सेवा एक प्रमुख आयाम के रूप में अपने आप जुड़ गई। पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी संकटग्रस्त नागरिकों की मदद में जुट गए और बीट आरक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्र में खाने पीने की आवश्यक सामग्री और दवाओं के दैनिक वितरण की जिम्मेदारी को अपना लिया, ऐसे कई उदाहरण मध्यप्रदेश में हमारे सामने आए। कुछ जिलों में तो भुखमरी से बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इंदौर में कोविड-19 के बारे में पुलिस थानों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित महिलाओं के स्वयंसेवी दल “ऊर्जा” नामक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय स्वयंसेवकों को संगठित करके वयोवृद्ध लोगों के घर जाकर उन्हें खाद्यान्न और दवाएँ वितरित करवाई हैं। लोगों से दान लेकर पुलिस की गाड़ियों से चक्कर लगाते हुए पुलिसकर्मियों ने सड़क पर रहने वाले लोगों में साबुन, पानी और भोजन बाँटा है। उज्जैन में जिला पुलिस ने प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के अधिकारियों के साथ मिलकर झुगियों में रहने वाले लोगों और नगर से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन बाँटने का काम किया है। पुलिस

-
- शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा शोध केन्द्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
 - प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर एक अस्थाई रसोईघर बनाया है, जिसमें हर रोज 15,000 पैकेट भोजन बनाकर उन्हें जरूरतमंदों में बाँटा जाता है। जबलपुर के एक कांस्टेबल ने बताया कि बच्चों के साथ कुछ महिलाएँ उसके पुलिस थाने में आईं और अपनी दुर्दशा की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे झुग्गी में रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहाँ के निवासी कई दिनों से भूखे हैं। कांस्टेबल ने एक स्थानीय एनजीओ से संपर्क करके उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई और उसके बाद उस एनजीओ ने झुग्गी में रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था कर दी। खाद्य सुरक्षा से भी आगे बढ़कर पुलिस अधिकारी जन स्वास्थ्य संदेशवाहकों की नई भूमिका निभाने लगे हैं और पुलिस स्टेशन भारत के जन स्वास्थ्य अभियान के केंद्र बन गए हैं। जिला पुलिस के प्रमुख अधिकारियों ने कोविड-19 की आपात फोन लाइनें शुरू कर दी हैं ताकि नागरिकों की आवश्यकताओं की शीघ्रता से पूर्ति की जा सके। कुछ थानों के बाहर तो सामाजिक दूरी बनाये रखने और हाथ धोने के महत्व को समझाने के लिए बैनर भी लगा दिये गए हैं। कुछ अधिकारी तो यातायात के विराम स्थलों पर हाथ धोने की तकनीक का प्रदर्शन भी करने लगे हैं। इसी प्रकार के प्रयास पुलिस संगठन के अंदर भी चल रहे हैं, उदाहरण के लिए ग्वालियर जिले के कांस्टेबलों ने अपने इलाके के साथियों के बचाव के लिए कपड़े से मास्क भी बनाये हैं।

आज निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल एवं अंतरराष्ट्रीय आपदा में जीवन जी रहे हैं। हम सब एक अज्ञात शत्रु के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, जिसकी समयावधि की कोई जानकारी नहीं है। हमें हमेशा सतर्क रहकर एवं एक होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा तथा जो भी उपाय विशेषज्ञों ने बताए हैं, उन्हें अपना कर अपने शरीर और समाज की रक्षा करना भी आवश्यक है। संपूर्ण विश्व के साथ-साथ भारत में कोरोना वायरस ने पूरे के पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। इस समय पूरे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति है। इससे पूर्व भी भारतीय समाज में अनेक महामारियों को झेला है, किंतु कोरोना वायरस से फैली महामारी ने पूरे भारतीय समाज को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस महामारी से निपटने में चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी अपनी महत्वपूर्ण

भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की भी अहम जिम्मेदारी है और भारतीय पुलिस ने इस महामारी के दौरान यह सिद्ध किया है कि उसका उद्देश्य देशभक्ति और जन सेवा है।

पुलिस के समक्ष इस महामारी ने अनेक नई सामाजिक चुनौतियां खड़ी की हैं, जैसे लॉकडाउन तथा धारा 144 लागू हो जाने के समय शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना और इसके लिए पुलिस को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। ड्यूटी पर उपस्थित महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों को जितना संभव हो, उतना आराम भी देना पड़ेगा तथा उनके ड्यूटियों को बदलना भी पड़ेगा। फेस मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन अथवा सेनेटाइजर तथा कुछ सुरक्षात्मक वीयर (सेफ्टी किट्स) यह हर हालत में सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभाग द्वारा देना होगा।

पुलिसकर्मी दिन-रात अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और इस कारण देश में अनेकों पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के शिकार भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। भारतीय जनमानस उन्हें नमन करता है। वर्तमान समय में इस नई समस्या से उत्पन्न हुई नई प्रकार की ड्यूटी से पुलिसकर्मियों को भी कहीं न कहीं तनाव हो रहा है। दिन-रात पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर अनवरत रूप से लगे हुए हैं। जब कभी किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना वायरस की पाजिटिव आ जाती है, तब चिकित्सा कर्मचारी के साथ संक्रमित व्यक्ति या व्यक्तियों को आइसोलेशन अथवा क्वारेंटाइन करने में पुलिस को स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करनी होती है। यहां पर देखा जाए तो स्वास्थ्यकर्मियों के पास वायरस से सुरक्षित रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में ही इस प्रकार के दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, जो एक चिंता एवं जोखिम का विषय है। वायरस के प्रथम चरण के दौरान वायरस से संक्रमित व्यक्ति को पुलिसकर्मियों को पकड़ना पड़ता था और उसे क्वारेंटाइन करवाना पड़ता था। अभी हाल ही में दिल्ली में एक पढ़े-लिखे दंपति ने पुलिस कर्मी को मास्क पहनने के लिए कह देने पर अनेक प्रकार की बातें सुनाई जो अशोभनीय हैं। मास्क पहनने के लिए

अनुरोध करने पर पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करने वाले दिल्ली के दंपती को आखिर जेल की हवा खानी पड़ी। पश्चिम पटेल नगर निवासी पंकज और आभा कार से कहीं जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें बिना मास्क के देखा तो उनकी गाड़ी रुकवाकर मास्क पहनने की अपील की। इस पर दोनों भड़क गए। दोनों ने पुलिसवालों के साथ जमकर बदसलूकी की। बार-बार खेद जताने के बाद भी पति-पत्नी बदतमीजी करते रहे। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जब पढ़े-लिखे लोग इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से बन पाएगी।

ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान ईरान, इटली और जर्मनी में कानून व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न ही नहीं हुई थीं। आस्ट्रेलिया में समुद्री बीच पर बहुसंख्यक पर्यटक पहुंच गए थे, जिनको हटाना पड़ा। जर्मनी में भी लोग लॉकडाउन के दौरान पार्कों में घूमने निकल पड़े थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल भारत में ही इस लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है, परंतु अन्य देशों में भी हो रहा है और इससे निपटने की जिम्मेदारी अंत में पुलिस के ही कंधों पर आती है। वर्तमान समय में पुलिस के समक्ष एक नई प्रकार की चुनौती है। पुलिसकर्मी जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनमें संक्रमण हावी ना होने पाए। लॉकडाउन के कारण श्रमिकों का वापस आना, बेरोजगारी की दर बढ़ जाना आदि ऐसे कारक हैं जो आने वाले समय में अपराध की दर को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, पुलिसकर्मियों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा।

इस वायरस और इससे फैली महामारी ने पुलिस को अपनी भूमिका के बारे में एक एक नए सिरे से सोचने को मजबूर किया है। सोशल मीडिया आदि पर फैलती अफवाहों और उनसे शांति और व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से भी पुलिस को निपटना है। स्थानीय स्तर पर चिकित्सा विभाग, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, नागरिकों से लगातार सामंजस्य और वार्ता करके ही पुलिस अपनी नई भूमिका पर सफल हो सकती है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए और इस प्रकार की नई भूमिका का निर्वाह करने के लिए भारत में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार प्रति एक लाख नागरिक पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 144 ही है। मतलब,

हर 450 भारतीयों पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती होनी चाहिए लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 694 हो गया है। हमें पुलिसकर्मियों की संख्या और उनके संसाधनों को बढ़ाना होगा तभी हम वास्तविक मायने में पुलिस का आधुनिकीकरण कर पाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना की और कहा कि पुलिस बल राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से पुलिस बल निबटा और शहर में शांति कायम कर सका। शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा, “उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा से निबटना हो, कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद घोषित लॉकडाउन हो या फिर प्रवासी मजदूरों का आवागमन हो, दिल्ली पुलिस ने लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। समाज का हर तबका इस मानवीय चेहरे की तारीफ कर रहा है। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने भी म.प्र. पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है और अपनी कर्तव्यपरायणता से प्रदेश को इस संकट से उबारने में सफल होगी। लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया है, ऐसे में दिहाड़ी मजदूर पलायन कर रहे हैं। सिंगरौली जिले से दो दर्जन से ज्यादा मजदूर 200 किलोमीटर दूर रीवा के लिए पैदल निकल पड़े, लेकिन बरगवां थाना पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया। सभी मजदूरों में कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। पुलिस को जब पता चला कि मजदूर सुबह से भूखे हैं तो उन्होंने फौरन खाने के पैकेट का इंतजाम कराया और सभी मजदूरों को भोजन कराया। बरगवां टीआई मनीष त्रिपाठी और उनका पूरा स्टाफ इस इंतजाम में लगा रहा। ऐसा कम देखने को मिलता है, जब पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आता है। मजदूरों के लिए सिंगरौली आए इन मजदूरों को लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी और वह यहां आकर फंस गए थे। ऐसे कई उदाहरण देश के हर कोने में हमें देखने को मिल रहे हैं जो पुलिस की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करते हैं।

डीजीपी विवेक जौहरी ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस के कर्तव्य निर्वहन की सराहना की है। जौहरी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, रेल पुलिस अधीक्षकों, विशेष सशस्त्र बल के सेनानियों एवं थाना प्रभारियों को अर्ध शासकीय पत्र लिखकर हौसला अफजाई की है। उन्होने कि लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं कि निर्बाध आपूर्ति, बीमार लोगों को बिना देरी सेवा मुहैया कराना, असंगठित श्रमिक एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को भोजन आदि सेवाएं मुहैया कराने में पुलिस, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के जवानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इन सभी इकाइयों के जवान दिन-रात अथक मेहनत कर इस भूमिका का बखूबी ढंग से निर्वहन भी कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस बल के जवानों से अपील की है कि इसी समर्पण भाव से कार्य करते रहें ताकि देश और अपने प्रदेश को कोरोना के संकट से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि वे खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। साथ ही अपेक्षा की है कि लॉकडाउन का पालन कराते समय हमारा सख्त व्यवहार किसी भी हालत में लोगों के प्रति दुर्व्यवहार में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना का कवरेज करने वाले मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी सहयोगात्मक रवैया रखें। डीजीपी ने 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और बीमारियों से ग्रस्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगाने के लिए कहा है कि जहां जनता से सीधा संपर्क स्थापित न होता हो। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस जवानों को यूनीफार्म बदलने के लिए भवन तय करें। पुलिस कर्मचारियों की यूनीफार्म धुलवाने की बेहतर व्यवस्था भी कराई जाए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को साफ तौर पर ताकीद करें कि अपने घर में घुसने से पहले वर्दी को पूर्व से ही बाल्टी में रखे गए घोल में डालकर नए कपड़े पहनें। डीजीपी ने 14 दिन तक पुलिस वालों को घर जाने से बचने के लिए कहा है। जिन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगी है वे अधिकारी व कर्मचारी 14 दिनों तक अपने घर जाने से बचें। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षक से कहा कि उनकी रहने की, भोजन और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था बेहतर ढंग से करें।

महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी के प्रति निष्ठा का एक उदाहरण यहां उल्लेखनीय है, नवरात्र के पांचवें दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। जो हमें अपना फर्ज निभाने के लिए प्रेरित करती है।

कोरोना काल में महिला पुलिस ने मां दुर्गा के समान शक्ति बन अपनी ड्यूटी को निभाया। महिला पुलिस को शहर के आंतरिक हिस्सों में ड्यूटी पर तैनात किया गया, जहां से महिला-पुरुषों पर लॉकडाउन का पालन कराना था। ऐसे में महिला पुलिस ने भी पुरुष पुलिस कर्मचारियों के बराबर ही अपनी ड्यूटी को निभाया। ऐसी ही महिला पुलिस अधिकारी हैं, महिला थाना पुलिस प्रभारी प्रवीण कौर। जिन्होंने कोरोना काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया। ड्यूटी भी की और बच्चों व वृद्ध सास-ससुर को भी संभाला। उनके पति भी पुलिस विभाग में ही तैनात हैं। वे भी अपनी ड्यूटी पर थे। साथ ही परिवार व बच्चों के साथ-साथ ड्यूटी को बाखूबी निभाया। कोरोना काल में लॉकडाउन के साथ ही पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई थी। महिला पुलिस को शहर के सबसे व्यस्त चौकों पर ड्यूटी पर तैनात किया गया। इन चौकों से ही शहर के आंतरिक हिस्सों में लोगों की आवाजाही थी। एसआइ प्रवीण कौर की ड्यूटी भी लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघन करने वालों को रोकने के साथ-साथ के साथ-साथ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में लगाई गई थी। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। कोरोना योद्धा बन उन्होंने अपनी ड्यूटी की। महिला थाना प्रभारी प्रवीण कौर का कहना है कि कोरोना काल के दौरान हर समय यही डर रहता था कि कहीं उनका परिवार उनके कारण इस बीमारी से संक्रमित न हो जाए। वे ड्यूटी से घर जाने के बाद तब तक परिवार के साथ नहीं मिलती, जब वह जरूरी नियमों की पालन नहीं कर लेती थी। उसके बाद वे बच्चों से दिन में आनलाइन क्लास के बारे में जानकारी लेने और बुजुर्ग सास-ससुर की कुशलक्षेम पूछती थी। उनका कहना है कि पुलिस की नौकरी दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। परिवार से पहले ड्यूटी है, वे इसे पूरी इमानदारी से निभाती हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण की लड़ाई में डटी रही पुलिस ने इसे मात देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और सबसे आगे आ खड़ी हुई है। कोरोना काल में संकट के समय पुलिस लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटी। बात चाहे बीमार लोगों के लिए आक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाने की हो या फिर जान गंवा चुके लोगों का साथ देने की, हर जगह पुलिस अपने फर्ज को पूरी इमानदारी से निभा रही है।

पुलिसकर्मी की मानवता का एक उदाहरण यहां और उल्लेखनीय है डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंगित प्रताप सिंह को 23 अप्रैल की सुबह साढ़े आठ बजे किशनगढ़ थाना पुलिस को काल मिली। कालर पल्लवी ने बताया वह किशनगढ़ स्थित एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहती है। वह बेहद मुसीबत में है। उनके पति राकेश की कोरोना के कारण मौत हो गई है। वह घर में अकेली है। उसे पति का अंतिम संस्कार करवाने के लिए एम्बुलेन्स की जरूरत है। कोशिश करने के बाद भी एम्बुलेन्स नहीं मिल रही। इस पर कांस्टेबल संदीप को इस महिला की मदद का जिम्मा दिया गया। वह महिला के घर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्हें पीपीई किट मुहैया करवायी। इसके बाद सफदरजंग अस्पताल से शव शमसान घाट तक ले जाने के लिए एम्बुलेन्स का इंतजाम किया। एम्बुलेन्स के मौके पर पहुंचने पर शव को पल्लवी और उसके कुछ जानकार लोगों के साथ अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। इससे पहले गोकुलपुरी इलाके में सोनू नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने कारोना के डर उसके शव को नहीं लिया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उसके शव को अंतिम संस्कार करवाया।

वर्तमान समय में भारत के अस्पतालों में आक्सीजन का संकट उत्पन्न हो गया है ऐसे समय में आक्सीजन को पहुंचाने का दायित्व भी पुलिस अपने कंधों पर ले रही है। ऐसा एक उदाहरण यहां उल्लेखनीय है नार्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी एंटो अल्फोंस को सुबह सवा सात बजे सिविल लाइंस थाने को तीरथ राम शाह हास्पिटल की ओर से काल मिली। बताया गया उन्होंने अपने वाहन को आक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए बवाना सेंटर भेज रखा है, जो अभी तक नहीं आ सका है। मदद की गुहार लगाने पर पुलिस की एक टीम फौरन बवाना भेजी गई, जहां से ग्रीन कारिडोर बनाकर आक्सीजन सिलेंडर को हास्पिटल तक पहुंचाया गया। नौ बजे तक आक्सीजन के 33 सिलेंडर हास्पिटल को मिल गए, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ राहत की सांस ली।

इस वायरस से उत्पन्न हुई महामारी और लॉकडाउन के समय महिलाओं और बालकों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी पुलिस के कंधों पर है, जिसे पुलिस बखूबी निभा रही है। कोविड-19 को फैलने से रोकने और इस पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों से बच्चों पर संरक्षण जोखिम हो

सकता है। घर पर, किसी केंद्र में, या किसी क्षेत्र में क्वारंटाइन और आइसोलेशन के उपाय बच्चों और उनके परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। घरेलू हिंसा बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। लॉकडाउन के पिछले कुछ सप्ताह में उदाहरण के लिए, चाइल्डलाइन, बच्चों के लिए एक आपातकालीन हेल्पलाइन, ने संकट में पड़े बच्चों से काल में 50 प्रतिशत बढ़त की सूचना दी। कोविड-19 के दौरान, परिवार इसका सामना करने के लिए कुछ नकारात्मक उपायों का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि बाल श्रम या बाल विवाह। हाल में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से चाइल्ड लाइन की कोशिशों के जरिए 898 बाल विवाह रोके गए हैं। ऐसे हालात में, पुलिस को एक जरूरी भूमिका निभानी है। चाहे संकट में पड़े बच्चों की मदद करना हो, शिविरों और अस्थायी आश्रयों में प्रवासी आबादी के प्रति होने वाली हिंसा को रोकना सुनिश्चित करना हो, बाल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की सूचना देने में सतर्क बने रहना और जिम्मेदार बनना हो या बच्चों को बाल संरक्षण सेवाओं में भेजना सुनिश्चित करना हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

- एस अखिलेश, (2002), आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली
- एस अखिलेश, (2008), पुलिस और समाज, गायत्री पब्लिकेशंस रीवा मध्य प्रदेश
- एस अखिलेश, (2010), पुलिस प्रक्रिया, गायत्री पब्लिकेशंस रीवा मध्य प्रदेश
- <https://www-bhaskar-com/>
- <https://www-unicef-org/india/hi/story/covid&19>
- <https://hindi-theprint-in/opinion/in&the&time&of&coronavirus&crisis&the&police>

किशोरों पर वैश्विक महामारी का प्रभाव: मानसिक स्वास्थ्य पर एक चुनौती

• श्रीमती ज्योति बाला चौबे

•• डॉ. श्रीमती रूपम अजीत यादव

हाल ही में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के सायकियेट्री प्रोफेसर बेट्टी पेफरबॉम ने अपने रिसर्च पेपर में उन कारकों की पहचान की है जो चिंता, तनाव एवं निराशा बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया महामारी की अनिश्चितता, उपचार संसाधनों में कमी, तंगी, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। भारत के सन्दर्भ में क्वारंटीन एवं सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने वाले हैं, निराशा का माहौल उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त हैं। हम क्या सोचते हैं? हमारे किशोर बच्चों पर इनका प्रभाव क्या नहीं पड़ेगा? निश्चिततः कोविड 19 के काल की ये भावनात्मक निराशाएं मनोविकारों को बढ़ाने में योगदान देंगी। सभी मनोवैज्ञानिक इस विषय पर एकमत हैं कि ऐसे मानव भय व चिंताओं का प्रभाव हमारे शरीर, मस्तिष्क, हमारी भावनाओं एवं व्यवहारों पर पड़ता है।

किसी भी वैश्विक महामारी का मनोवैज्ञानिक परिणाम हम सब के मनोसामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सामाजिक ताने-बाने को भी अछूता नहीं छोड़ता, चाहे व्यक्ति वायरस से प्रभावित रहा हो या नहीं भी रहा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रथम महानिदेशक ब्रॉक चिशहोम, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक भी थे उनकी प्रसिद्ध उक्ति है कि- बगैर मानसिक स्वास्थ्य के उचित शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को नहीं पाया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर एवं अभिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, चूँकि व्यक्ति एक समाज में रहता है, इसीलिए व्यक्ति का मनोसामाजिक स्वास्थ्य उसके शारीरिक स्वास्थ्य की दशा पर भी निश्चिततः असर डालता है।

-
- असिस्टेंट प्रोफेसर-मानव विकास, भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-९ भिलाई
 - असिस्टेंट प्रोफेसर-आहार एवं पोषण, भिलाई महिला महा., सेक्टर-९ भिलाई

संक्रमणकारी महामारियां जन सामान्य में चिंता एवं घबराहट के पैमाने को बढ़ाती हैं, इनसे हमारे अपने समाज का वह वर्ग अधिक प्रभावित होता है, जो संवेदनशील अधिक है आयु की दृष्टि से भी एवं समझ और सतर्कता बरतने की दृष्टि से भी। किशोर आयु के बच्चे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, प्रतिबंधों में नहीं। किशोरों के समूह ने वैचारिक आदान-प्रदान के दौरान बताया कि लॉकडाउन आरम्भ में तो अच्छा लगा कि परिवार जन सदा साथ रहेंगे, स्कूल कॉलेज जाने की कोई जल्दी नहीं रहेगी, देर से सोयेंगे, देर से उठेंगे। कुछ ने कहा निश्चिंत रहकर घर के कार्यों में हाथ बंटाएंगे, किन्तु ये दिनचर्या अब कुछ दिन बीत जाने के बाद परेशान करने लगी है।

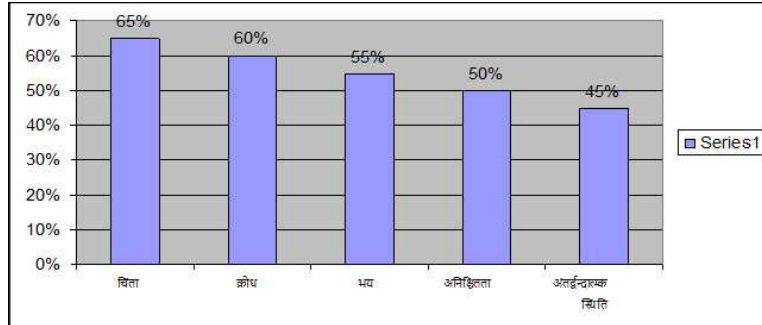
किशोरों की इस पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) के दौरान (कोरोना समयावधि में) उनकी भावनात्मक स्थिति जानने के लिए 60 किशोर बच्चों (जिनमें लड़के-लड़कियां सम्मिलित थे), से एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। इसमें सेलफोन, व्हाट्स एप्प एवं टेलीफोन का उपयोग किया गया। परिणामों ने उनकी स्वाभाविक चिंता, क्रोध, भय, अनिश्चितता, मनोबल में कमी एवं निराशा को दर्शाया।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली मनोवैज्ञानिक पारुल खन्ना कहती हैं, लॉकडाउन के कारण कोचिंग क्लासेस, स्कूल कॉलेज का बंद हो जाना, बाहर नहीं निकलना, कोरोना समाचारों को आवृत्ति पूर्ण देखना हमारे साथ साथ किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। किशोर बच्चों ने अपनी चिंता, भय, डर, आत्म विश्वास में कमी एवं अंतर्द्वंदों की निम्नांकित वजहें बताई हैं-

1. स्व-संक्रमण का भय
2. स्वजनों के संक्रमित होने सम्बन्धी चिंता
3. पिता, मुखिया की नौकरी, कारोबार सम्बन्धी अनिश्चितता
4. ऑनलाइन अध्ययन, परीक्षा की ऑनलाइन/ऑफलाइन विधि- अनिर्णय व अन्तर्द्वन्दात्मक स्थिति
5. सामाजिक मेल मिलाप पर प्रतिबन्ध व घर पर ही सीमित रहने की मजबूरी के कारण क्रोध

किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति- कोरोना काल की इस पूर्ण बंदी में माता पिता के कार्य दायित्वों का बोझ बढ़ने से परिवार में वैचारिक टकराव की स्थिति, पैसों की तंगी होने पर भी बच्चों की जरूरतों को पूर्ण

करने की विवशता इन सब का असर बच्चों की मनःस्थिति को विचलित करने वाला होता है। किशोर लड़कों की तुलना में लड़कियों में माता-पिता की इन विवशताओं ने उनकी चिंता एवं निराशाओं को बढ़ाया है।



कोरोना महामारी ने दुनिया भर के माता पिता की जीवनचर्या बदल कर रख दी है। अमेरिका के 2021 तक के आंकड़े चिंताजनक हैं। 2020 में अमेरिका में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 15 लाख माताओं (8 प्रतिशत) को कामकाज छोड़ना पड़ा एवं इसी आयु के बच्चों के 5.6 प्रतिशत पिताओं को भी काम छोड़ना पड़ा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी कालेज लंदन से जुड़े ऐलिस पॉल कहते हैं कि, ब्रिटेन में कई माता-पिता उच्च स्तर की चिंता एवं तनावों से जूझ रहे हैं। जाहिर है परिवार की ये हालत बच्चों की मनोदशाओं को उद्धेलित करने के लिए पर्याप्त है। हम सभी के लिए किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की दशाओं को इस दौरान पृथक-पृथक समझना जरूरी है कि वे किस प्रकार किशोर बच्चों को प्रभावित करती हैं

1. **शरीर पर प्रभाव-** भूख में कमी, सिर दर्द, थकान, रक्त चाप में उतार चढ़ाव, शरीर प्रतिरोधी क्षमता में कमी।
2. **भावनात्मक प्रभाव-** चिंता, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उदासी, उलझन में रहना, असुरक्षा का भाव।
3. **मस्तिष्क पर प्रभाव-** स्वयं से ज्यादा स्वजनों के संक्रमित होने का भय, आर्थिक असुरक्षा के फलस्वरूप समय पर फीस का भुगतान ना कर पाना सम्बन्धी भय, परीक्षा में ना बैठ पाने का डर, कार्य में एकाग्रचित ना हो पाना, उचित अनुचित में निर्णय ना कर पाना, अंतर्द्वन्द्वत्मक स्थिति

4. **व्यवहार पर प्रभाव-** ज्यादा टीवी देखने की अवधि में वृद्धि, दिन भर चैटिंग में लगे रहना, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय देना, बात-बात पर नाराज होना या चुप्पी साध लेना।

उपरोक्त प्रभाव यदि तीव्रता एवं आवृत्ति में कम हैं तो कोई विशेष चिंताजनक परिणाम नहीं होंगे किन्तु यदि स्थिति इसके विपरीत होगे, तो किशोरों के व्यक्तिगत विकास के लिए घातक सिद्ध होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 10 से 13 फीसदी बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत सहित दुनिया के सभी देशों में मानसिक रूप से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका है।

हम सभी को इस समय बच्चों एवं किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक कुशलता के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। वर्ष 2020 में “मानसिक स्वास्थ्य को” एक केन्द्रीय विषय के रूप में महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य को मानवाधिकार के रूप में स्थापित करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश 2015 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र परामर्श प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपील जारी करते हुए कहा है कि शैक्षिक संस्थानों के परिसरों में मानसिक एवं मनोसामाजिक चिंताओं के निवारण हेतु स्वस्थ जानकारी चार्ट, पोस्टर के रूप में सूचनाएं, स्लोगन्स के रूप में लगाए जाने चाहिए एवं परामर्श इकाई (कॉउंसलिंग सेल) की स्थापना अवश्य होनी चाहिए।

सभी स्कूलों एवं कालेजों में छात्र परामर्श दाता (कॉउंसलर) होने चाहिये एवं मनोवैज्ञानिक शंका समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा भी निश्चित तौर पर होनी चाहिए।

यूनिसेफ की चाइल्ड लाइन ऐसे कठिन समय में अभिभावकों, केयर गिवर्स एवं स्वयं किशोर बच्चों के सपोर्ट के लिए खड़ी है हेल्प लाइन नंबर 1098 सहायता हेतु उपलब्ध है। यूनिसेफ के अनुसार- A single call can change the life of the child if they are in distress. चाहे पूर्ण बंदी (लॉक डाउन) में हो या संक्रमण के समय संगरोध (क्वारेन्टीन) की स्थिति में एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने एवं

करवाने में अभिभावकों की अहम् भूमिका होती है। बार- बार टीवी पर समाचार देखना चिंता एवं असुरक्षा को उत्पन्न करता है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवं रोग नियंत्रण केन्द्रों ने ये निर्देशित किया है कि केवल एक या दो बार समाचार देखें वो भी विश्वसनीय स्रोतों से। कोविड 19 का अनुभव कर चुके स्थानीय लोगों की सकारात्मक कहानियों को किशोरों की जानकारी में लाया जाए। पारिवारिक दिनचर्या में बच्चों की आयु अवस्था के अनुरूप आकर्षक गतिविधियों के उन्हें अवसर दिए जाएँ। बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के सकारात्मक अवसर दिए जाएँ। योग प्राणायाम के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों को पूर्ण करने में अभिभावक मदद करें।

शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि आशावादी सोच हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, तनाव व नैराश्य में कमी के साथ साथ सर्दी जुकाम के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ाती है एवं स्क्रिप्स सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाती है व हृदय के स्वास्थ्य में भी लाभ पहुंचाती है।

यह शोध आलेख इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रथम दो लहरों के पश्चात कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी भी वैज्ञानिकों ने दे डाली है जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे बच्चों को प्रभावित करेगी, इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लेते हुए हमें अभी से प्रतिरोध उपाय करते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। समय चुनौतिपूर्ण है, हमें यह महसूस करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सर्वांगीण विकास हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है, सरकार का ये संकल्प है कि देश का हर बच्चा, किशोर मानसिक रूप से स्वस्थ रहे एवं मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का लाभ हर नागरिक को मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

- www-bbc-com/india
- www-jansatta-com
- thewirehindi-com/coronavirus
- hi-m-wikipedia-org/covid
- www-downntoearth-org/health
- www-unicef-org/media
- भास्कर कोरोना महामारी 24.05.2021

कोरोना काल के दौरान सुरसा की तरह बड़ी बेरोजगारी

• डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। एक तरफ वायरस के संक्रमण से लोगों की जान जा रही है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरी भी जा रही है। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अब लोगों की रोजी-रोटी पर भी संकट आ गया है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। संक्रमण रोकने के लिए के दुनिया के अलग-अलग शहरों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। एक विदेशी वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अकेले अमेरिका में अब तक 1.68 करोड़ लोगों बेरोजगार हो गए हैं। अमेरिका के श्रम ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.68 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी पैकेज के तहत सहायता राशि लेने के लिए आवेदन किया है। कोरोना संक्रमण की वजह से कनाडा में लगभग 10 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। कनाडा के लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च महीने में 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी छिन चुकी है। इससे कनाडा में मार्च महीने में बेरोजगारी दर 2.2 फीसदी से कई गुना बढ़कर 7.8 फीसदी पर पहुंच गई। जर्मनी में भी इस साल बेरोजगारी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यहां अब तक 6.5 लाख से ज्यादा कारोबारियों ने काम के घंटे कम करने के लिए आवेदन कर दिया। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार यह स्थिति 2008-09 की मंदी से भी ज्यादा भयंकर बताई जा रही है।¹

कोरोना वायरस के प्रसार के साथ ही लगभग हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र से हजारों कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी देने, नौकरियों से निकालने, वेतन में भारी कटौती की खबरें आ रही हैं। माल्स, रेस्तरां, बार,

• एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, सकलडीहा पी जी कालेज सकलडीहा चंदौली

होटल सब बंद हैं, विमान सेवाओं और अन्य आवाजही के साधनों पर रोक लगी हुई है। फैक्टरियां, कारखाने सभी ठप्प पड़े हैं। ऐसे में संस्थान लगातार लोगों की छंटनी कर रहे हैं और हर कोई इसी डर के साये में जी रहा है कि न जाने कब उसकी नौकरी चली जाए। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे लोग, छोटे-मोटे काम धंधे करके परिवार चलाने वाले लोग सभी घर में बैठे हैं और उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। बॉस्टन कालेज में काउंसिलिंग मनोविज्ञान के प्रोफेसर और 'द इंपोर्टेंस ऑफ वर्क इन अन एज ऑफ अनसर्टेनिटी रू द इरोडिंग वर्क एक्सपिरियन्स इन अमेरिका' किताब के लेखक डेविड ब्लूस्टेन कहते हैं, बेरोजगारी की वैश्विक महामारी आने वाली है। मैं इसे संकट के भीतर का संकट कहता हूँ। जिन लोगों की नौकरियाँ अचानक चली गयी हैं या लॉकडाउन के कारण रोजगार अचानक बंद हो गया है, उन्हें आर्थिक परेशानी के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि नौकरी जाने या रोजगार का जरिया बंद होने पर अपनी भावनाओं को कैसे संभालें? कैसे नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि रोजगार जाने का दुख किसी अपने को खोने के दुख के बराबर ही होता है और व्यक्ति रोजगार जाने की स्थिति में भी दुख को महसूस करने और उससे निपटने के किसी भी चरण- यानि सदमा लगना और परिस्थिति को स्वीकार न करना, फिर गुस्सा और अंत में स्वीकार भाव और आगे की उम्मीद- से गुजर सकता है।

बेन्सन कहते हैं, अपने प्रति ज्यादा उदार हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को ठीक से महसूस कर पाते हैं।² शुरुआत में लोग बेहद नाराज रहते हैं। लेकिन वह यह भी कहती हैं कि उनका अध्ययन इस संकट से पहले का है जब प्रचुर आर्थिक समृद्धि थी। वो मानती हैं कि हो सकता है इस अनपेक्षित माहौल में नौकरी जाने पर उतनी नाराजगी न हो। संतुलन बनाए रखना अध्ययनों से पता चलता है कि महामंदी के दौरान जिन लोगों को वित्तीय या नौकरी संबंधी दिक्कतों या आवास की समस्या का सामना करना पड़ा, उन्हें मानसिक बीमारियों का खतरा अधिक था। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस अभूतपूर्व परिस्थिति की मार झेल रहे लोग अपना संतुलन कैसे बनाए रखें? बेन्सन कहते हैं, किसी भी नुकसान के बाद लोगों

को अपने हालात का मूल्यांकन कर यह तय करना चाहिए कि इनमें से किन चीजों को वे नियंत्रित कर सकते हैं और किन को नियंत्रित नहीं कर सकते और फिर उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं। जो समस्या अभी सामने है, उसकी पहचान करने, जैसे नौकरी जाने पर घर खर्च में कमी लाने और उसके लिये कुछ उपाय करने के साथ-साथ अगर हम यह मान कर चलेंगे कि कुछ समय के लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं और जब तक स्थितियाँ नहीं सुधरतीं, जीवनशैली में बदलाव जरूरी है, तो कुछ आसानी होगी।³

भारत में भी सुरसा की तरह बेरोजगारी- कोरोना के बढ़ते प्रकोप और उससे निपटने के लिए जारी 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन तथा दूसरी लहर के कारण भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की आशंका है इससे उनकी नौकरियों और कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोनावायरस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोगों को और गरीबी में धकेल देगा।⁴

बेरोजगारी का सीधा अर्थ है कि रोजगार का अभाव अर्थात् जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है भारत में 18 से 60 वर्ष की आयु की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है और इसी वर्ग के कंधों पर 18 से कम और 60 से अधिक उम्र के लोगों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी होती है कार्यशील जनसंख्या के पास अगर रोजगार का उचित अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका असर सभी उम्र के ऊपर देखने को मिलता है कोरोना काल में यह देखने में आया है कि जिनके पास पहले रोजगार प्राप्त था महामारी में बेरोजगार हो गए अर्थात् बहुत सारे लोगों के रोजगार विहीन हो गए पहले से ही लोगों के पास रोजगार के अवसर सीमित मात्रा में थे और जिनके पास रोजगार था उनके रोजगार कोरोना महामारी के चलते समाप्त हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा 2 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी महीने में बेरोजगारी की दर 7.78 प्रतिशत थी और मार्च 2020 से भारत में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन का दौर प्रारंभ हुआ था और भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी समिति की ताजा अध्ययन के अनुसार अप्रैल 2021 में 75 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

कोरोना महामारी ने भारत को इस समय सबसे खराब स्थिति में पहुंचा दिया है जहां लोग ना सिर्फ बीमार हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी चरमरा गई यह महामारी की भयाक्रान्तता और दूसरी तरफ से जनित संकट लोगों के रोजगार पर संकट आया है की भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी ताजा रिपोर्ट भी मानती है कि भारत में कोरोना काल के बीच बढ़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के आगे के कारण भी सबसे अधिक गतिविधियां जो पटरी पर धीरे-धीरे लौट रही थी वह पुनः बर्बाद हो गई, पहली लहर के दौरान बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी इस साल बेरोजगारी दर में 40 करोड़ रोजगार से जुड़े थे। मार्च में यह 39.81 करोड़ और अप्रैल में 39 करोड़ रह गई। कोरोना महामारी के प्रसार के कारण लगभग हर क्षेत्र में बिना वेतन छुट्टी देने नौकरी से निकालने वेतन में भारी कटौती की खबरों से रूबरू होना पड़ रहा है। इस दौर में होटल माल रेस्टोरेंट कारखाना आवागमन के साधन बंद हो गए थे, उन पर रोक लगी थी। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे लोग छोटे-मोटे काम करने वाले लोग अपना काम बंद करके घर बैठ गए और उनके आमदनी का स्रोत बंद हो गया वह बेरोजगार हो गए उनको आर्थिक परेशानी के साथ-साथ मानसिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

एमडी श्री महेश व्यास ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में वेतन पाने वाले एक करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिकतर बेरोजगारी है और महामारी का सबसे ज्यादा असर एमएसएमई पर ही पड़ा है। भारत में एमएससी सेंटर ही सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला सेंटर है। रोजगार उद्योग वाले राज्यों में अधिक देखने को मिली है इसमें अगर सारी बेरोजगारी को देखें तो अप्रैल 2021 में 9.78 प्रतिशत थी, जो कि मई में 10.63 बेरोजगार हो गए।

कोविड-19 की पहली लहर में जिनकी नौकरियां चली गई थी, वह इस समय कहां हैं और क्या कर रहे हैं, एजेंसियों के अध्ययन के अनुसार ज्यादातर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती या खेती से संबंधित कार्य में लग चुके हैं या हो सकता है कुछ वापस अपने काम पर लौट आए हो इसका कोई विधिवत आंकड़ा न सरकार के पास में है या किसी एजेंसी के पास उपलब्ध है। कितने लोग लौटे हैं, कौन से काम कर रहे हैं, रोजगार

मिला या नहीं मिला। यह बहुत बड़ा प्रश्न उभरकर के सामने आया है। विद्वानों का मानना है कि इतने लोगों के बेरोजगारी का प्रमुख कारण छोटे कारोबारियों के सामने पूँजी का संकट खड़ा होना है पहले तथा दूसरे लॉकडाउन के कारण इनके कारोबार पर ताला लग गया, जिसके कारण उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप उन उद्योगों में लगे लोगों की नौकरी से निकाला जाने लगा और लोग बेरोजगार होते गए। इसी तरह जो अपना खुद का व्यवसाय करके अपना अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, उनके सामने भी लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो लोग दैनिक मजदूरी का कार्य करते थे, लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार चला गया। रेहड़ी पटरी पर दुकान आदि लगाकर कार्य करने वाले लोग लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए। रेहड़ी और पटरी पर कार्य करने वाले वेन्डरों की संख्या लगभग 50 लाख है। 50 लाख लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार रहे। सूक्ष्म एवं लघु एवं मझोले उद्योगों में लगे लोगों की संख्या 2017-18 में 33 करोड़ थी। एक आंकड़े के अनुसार बड़े पैमाने पर लॉकडाउनके दौरान लोग बेरोजगार हुए।⁶

भारत में बेरोजगारी की दर 24 मई को समाप्त हफ्ते में बढ़कर 24.3 फीसदी हो गई है। इससे पिछले हफ्ते भारत में बेरोजगारी की दर 24 फीसदी के स्तर पर थी। अगर बार औसत बेरोजगारी दर की करें तो कोरोना लॉकडाउन के पिछले 8 हफ्ते में यह 24.2 फीसदी रही है। अगर बात भारत में मार्च के महीने की करें तो मार्च में बेरोजगारी की दर 8.8 फीसदी के स्तर पर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी की दर 24 फीसदी रही है, यह लगभग अप्रैल के जैसा ही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में लोगों के जॉब की स्थिति में काफी कमी आ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनोमी के अनुसार, 3 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर रिकार्ड 27.11 फीसदी तक पहुंच गई थी। इसके हिसाब से हर चार में से एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया। यह देश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनोमी की हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 84 फीसदी से ज्यादा घरों की मासिक आमदनी में गिरावट दर्ज की गई है। देश में कामकाजी आबादी का 25 प्रतिशत हिस्सा इस समय बेरोजगार हो चुका है।

सीएमआईई की स्टडी के मुताबिक देश में बेरोजगारी के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। 21 मार्च को भारत में बेरोजगारी की दर 7.4 फीसदी थी, जो 5 मई को बढ़कर 25.5 फीसदी हो गई है। स्टडी के मुताबिक देश में 20 से 30 साल आयु वर्ग के 2.70 करोड़ युवाओं को अप्रैल में नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।⁶

ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है जिसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार की स्थिति उनके क्षेत्र में होने वाली खेती और खेती से संबंधित क्रियाकलापों पर निर्भर करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समय को छोड़कर कुछ न कुछ हमेशा कार्य बना रहता है इसीलिए इन क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति थोड़ी कम देखने को मिलती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है और जो बेरोजगार हुए थे कि नौद किसी भी योजनाओं से मनरेगा आदि में कार्य करने वाले लोग जो लॉकडाउन के कारण योजनाओं के बंद होने से उत्पन्न हुए लेकिन किसी क्षेत्र में कार्य अधिक मात्रा में बाधित नहीं हुआ। इसके विपरीत शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के कारण इलाका ठप्प पड़ गया और कार्य बंद होने के कारण बड़े- बड़े उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों की नौकरी तो बच गई परंतु दुकान में काम करने वाले रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले बिल्डर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में लगे लोगों जिनके पास पूँजी का संकट था, उन सभी लोगों की नौकरियां चली गई और वे बेरोजगार हो गए और तब तक बेरोजगार रहे जब तक लॉकडाउन था, लेकिन देहरी पटरी पर काम करने वाले वेंडर दुकानों में कार्य करने वाले सूक्ष्म उद्योगों में लगे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की तरफ रोजगार के लिए गए थे वह लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को वापस लौट आए उनके मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई थी जो वापस गए यह आंकड़ा कहीं देखने का नहीं मिलता, लेकिन यह निश्चित है कि वापस लौटने का दर्शन नहीं है अतः हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने शहरों की तरफ लौटने का फैसला किया और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही रह कर जो भी रोजगार उपलब्ध है उसमें काम करना बेहतर समझा।⁷

कोरोना वायरस के प्रसार और इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जो अनियोजित लॉकडाउन लगाया गया उससे ऐसे असंख्य लोगों के जीवन में आर्थिक तबाही मचाई जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनमें न केवल दिहाड़ी मजदूर हैं बल्कि अनियमित अर्थव्यवस्था में काम

करने वाले मजदूर भी है। रोजगारी बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में कुल कार्यरत मजदूर का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें से एक तिहाई कैजुअल मजदूर है, करुणा के कारण केंद्र सरकार ने करीब 40 लाख लोगों को राहत प्रदान की तथा बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। बेरोजगारी के आंकड़े बहुत स्पष्ट नहीं हैं जो मानते हैं कि एक करोड़ लोगों की नौकरी गई है रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण 15-16 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या का 80 प्रतिशत क्षेत्र में एक तिहाई दूर में उनका रोजगार गया आंकड़ों के आधार पर देखें तो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों को रोजगार छीन लिया है।⁸

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में बेरोजगारी की दर इस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। आवश्यकता है सरकार को पैकेज तथा दूरदर्शी प्लानिंग बनाकर के जो लोग बेरोजगार हुए हैं या विरोध उनको रोजगार के क्षेत्र में जोड़ा जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाए प्लानिंग के साथ किया गया कार्य निश्चित रूप से भारत के लिए एक नई आशा की किरण लेकर के आएगा पुनः भारत आर्थिक विकास के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1 Hindi News Zee Hindustan ग्लोबल नजरिया Apr 10] 2020
- 2 कोरोना वायरस के दौर में बेरोजगारी: नौकरी जाने पर क्या क्या गुजरती है, डेमियन फाउलर बीबीसी वर्क लाइफ 28 अप्रैल 2020
- 3 पेनिसेलविया स्टेट यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र, श्रम और रोजगार संबंध की एसोसिएट प्रोफेसर
- 4 The economics times कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में भारत में बेरोजगारी दर 24 फीसदी से है T;knk May 27, 2020
- 5 The economics times कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में भारत में बेरोजगारी दर 24 फीसदी से है ज्यादा May 27, 2020
- 6 शिवप्रसाद जोशी बेरोजगारी के अभूतपूर्व संकट से जिसमें की चुनौती ब्लाग
- 7 सुरेंद्र ओझा 19 जून 21 रोजगार पंजीयन की चाल पत्रिका श्री गंगानगर राजस्थान
- 8 दी वायर रितिका खेड़ा 28 3 2020

कोरोना - 19 का भारतीय समाज पर प्रभाव

• डॉ. सीमा श्रीवास्तव

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना- 19 में CO का तात्पर्य का तात्पर्य कोरोना, VI - विषाणु, D (डिसीस) बीमारी तथा वर्ष 19 बीमारी के फैलने के वर्ष को चिन्हित करता है। यह बहुत ही घातक वायरस है जो कि अतिसूक्ष्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम से भी जाना जाता है। इस महामारी का संक्रमण चीन के वुहान से शुरू हुआ था जो कि जल्द ही पूरे विश्व में फैल गया। 30 जनवरी 2020 को भारत के केरल राज्य में कोविड-19 का पहला मामला चीन के वुहान से लौटे छात्र में मिला था। इसके बाद धीरे-धीरे यह संख्या देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बढ़ती गई। इसी विकराल स्थिति से बचने के लिये प्रधानमंत्री द्वारा 24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से 21 दिनों के लिये देश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस महामारी ने पूरे विश्व की जनसंख्या को स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करने के साथ ही मानसिक, सामाजिक आर्थिक रूप से भी हिला कर रख दिया। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिये सभी देश में लॉकडाउन घोषित किया गया जिसमें किसी भी तरह से कहीं भी आने-जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी।

25 फरवरी 2021 को भारत में कुल 1,10,46,914 पॉजीटिव केस रिपोर्ट किये गये हैं। जिसमें पिछले 24 घण्टे में 16738 नये एक्टिव केस दर्ज किये गये हैं तथा 138 मौतें भी दर्ज हुई हैं।¹ दूसरी ओर 1.11 करोड़ लोग भारत में वैक्सीन लगवा चुके हैं।² चिंता की बात यह है कि लगभग 45 दिनों के बाद कोरोना मामलों में तेजी आई है, 24 घण्टों में 16 हजार से ज्यादा नये केस आये हैं तो 138 मौत हुई हैं।³ एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 14 वें स्थान पर आ गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देश है, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिकवरी भी भारत में हुई है। दूसरी ओर मौतों की संख्या की दृष्टि से

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट

अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। कोविड-19 के प्रभाव को विभिन्न श्रेणियों में बाँट कर समझा जा सकता है।

कोविड-19 का सामाजिक प्रभाव- कोविड-19 महामारी ने विश्व को स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से तो प्रभावित किया ही है, साथ ही इसके विस्तृत सामाजिक प्रभाव भी हैं। टोटल लॉकडाउन के कारण लोगों को अपने-अपने घरों में ही रहना पड़ा आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो गईं। कई लोगों के पास आय का कोई साधन न रहा। वे लोग जो लॉकडाउन में अकेले रह गये, परिवार से दूर रहने के कारण अवसाद का शिकार हो गये। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। सामाजिक बंधन कमजोर हुए। लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में बंद रहे जिससे सामाजिक संपर्क समाप्त हो गया।

कोविड-19, इस वैश्विक महामारी ने भारतीय समाज को अनेक तरह से प्रभावित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश परंपराओं का देश है, यहाँ मिलजुल कर सारे त्योहार मनाये जाते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण कई त्योहार नहीं मनाये जा सके। त्योहार जो उल्लास का प्रतीक है, इससे लोगों को वंचित होना पड़ा इस कारण भी अनेक लोग अवसाद से ग्रसित हो गये।

यद्यपि लॉकडाउन के अनेक दुष्प्रभाव थे किन्तु दूसरी ओर इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े जो कि इस प्रकार है - पूरे परिवार को एक साथ समय बिताने का अवसर मिला। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिये 'वर्क फ्रॉम होम' की शुरुआत की जिसमें कर्मचारी घर पर ही रहकर अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप पर कार्य करता है। किन्तु यह सुविधा केवल कुछ क्षेत्रों में ही संभव थी। ऐसे कार्य जो कार्यस्थल पर जाकर ही करने होते थे, बंद रहे। इसका दूरगामी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लॉकडाउन का दूसरा पक्ष यह भी रहा कि लोग तत्परता से परोपकार के लिये प्रेरित हुए।

- विभिन्न सेवा क्षेत्र अपनी सेवायें समुचित तरीके से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
- सामाजिक दूरी और अकेलेपन के कारण लोगों को मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है।
- अपने मित्र, परिवार जनों, रिश्तेदारों से दूरी के कारण अवसाद की

स्थिति दिखाई दे रही है।

- मनोरंजन की सभी गतिविधियाँ ठप्प हैं।
- धार्मिक स्थल बंद होने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है।

कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव- भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिये 20 मार्च 2020 को टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके दूरगामी प्रभाव देश की जनसंख्या पर पड़ा। कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन के कारण जनमानस को तो अनेक परेशानियाँ झेलना ही पड़ा, साथ ही देश को भी बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुई जिसकी भरपाई करने में लम्बा समय लगेगा। लोगों से रोजगार छिन गया। कारखाने बंद हो गये। सारी आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो गईं। ऐसी स्थिति में निम्न व निम्न मध्यम वर्ग को पेट भरने की विकराल समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा प्रक्षेपित की गई। जिसके लिये वित्तीय नियमों में संशोधन किया गया। सरकारी प्रयासों और लोगों के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने की प्रक्रिया तीव्रता से प्रारंभ हुई।

- भारत की अधिसंख्य जनसंख्या को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति न हो सकने के कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।
- भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार छिन गया।
- छोटे-छोटे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से जाकर बड़े शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के सामने पेट भरने की विकराल समस्या आ गई।
- रोज कमा कर खाने वाले लोगों के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं था अतः उन्हें भूखे अथवा आधे पेट रहना पड़ा।
- बेरोजगारी से परेशान हो कई लोगो ने आत्महत्या कर ली।

भारत की अर्थव्यवस्था को इस वैश्विक महामारी ने बहुत अधिक प्रभावित किया। आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारतीय अर्थव्यवस्था इस महामारी के कारण लड़खड़ा गई है। प्रतिदिन लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा है या न के बराबर हो रहा है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में जहाँ मनुष्य की

पहुँच विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक है वहीं इस बीमारी का प्रसार भी उसी क्रम में सरलता से विश्व भर में हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व का कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा है।

भारत में कोविड-19 के कारण लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गये⁴ कोविड-19 कुछ कारोबारों के लिये तो विनाशकारी साबित हुआ है⁵ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन, रिटेल और आतिथ्य क्षेत्र थे। अच्छी बात यह थी कि अनलॉक ने स्थिति में सुधार किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (सीए आई टी) के अनुसार दिवाली के सीजन में 10.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई। बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है।⁶ दूसरी ओर विभिन्न कंपनियों ने अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन किया। वर्क फ्राम होम का कल्चर विकसित हुआ।

सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तवर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धिदर घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 की दर से घट जायेगी⁷ जिसका मुख्य कारण है लोगों में आय की कमी के कारण खपत में कमी। कोविड-19 महामारी ने विश्व की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। लाखों लोग भूख और स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो लाखों लोग अति गरीबी की स्थिति में जा रहे हैं।⁸ कोविड-19 से दिन प्रतिदिन का जीवन विश्व की गिरती अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रहा है। लाखों लोग स्वास्थ्य, भूख, गिरती आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के दुष्प्रभाव के चलते देश की आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लगातार चल रहे लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी इत्यादि की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घरेलू आपूर्ति और माँग प्रभावित होने के कारण आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है।⁹ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के कथन के अनुसार “कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं है बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट भी है।”¹⁰ एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन के दौरान लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गये, लाखों लोगो के वेतन में कटौती की गई, देश के लगभग 45 प्रतिशत परिवारों की आय में कमी आई।

स्वास्थ्य पर प्रभाव- कोविड-19 वैश्विक महामारी का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। यह महामारी छूने से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में

आने से अन्य लोगों तक संक्रमण फैलता है।

सामान्य लक्षण- सबसे पहले बुखार फिर सूखी खाँसी और साँस लेने में तकलीफ होना है।

गंभीर स्थिति- कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण की स्थिति में निमोनिया, किडनी का फेल होना इत्यादि गंभीर स्थिति होने पर मृत्यु तक हो सकती है।

यद्यपि निरंतर वैज्ञानिक शोध के चलते इस महामारी से बचाव के अनेक तरीके विकसित हुए हैं साथ ही इसकी दवाईयाँ और वैक्सीन भी उपलब्ध हो चुकी है। किन्तु चिंता की बात यह है कि विभिन्न शोध में यह बात सामने आई है कि कोरोना जंग जीत चुके व्यक्तियों को पुनः साँस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, मानसिक तनाव इत्यादि कठिनाईयाँ झेलना पड़ रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार प्रत्येक 10 रोगियों में से छह को ठीक होने के बाद भी साँस लेने में परेशानी हो रही है। ठीक हो चुके 60 प्रतिशत लोग फेफड़ों की समस्या से ग्रसित हैं। 29 प्रतिशत किडनी की समस्या, 10 प्रतिशत थकान की समस्या, 10 प्रतिशत लीवर की समस्या से ग्रसित हैं।

दूसरी ओर यह भी सच है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत हो गये हैं। वे पहले की तुलना में साफ-सफाई का ध्यान रखने लगे हैं तो साथ ही अपनी 'इम्यूनिटी' बढ़ाने के लिये स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। **ग्रामीण जनसंख्या पर कोविड-19 का प्रभाव-** वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विश्व की पूरी आबादी को तीव्रता से प्रभावित किया है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो पाते हैं कि सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के चलते ग्रामीण जनसंख्या कोविड-19 के संदर्भ में पूरी तरह जागरूक रही। ग्रामीणों ने सरकारी नियमों का पूरी तत्परता से पालन किया। इसीलिये ग्रामीण क्षेत्रों में यह महामारी सीमित क्षेत्रों तक ही फैली। लेकिन इसका अन्य दुःखद पहलू यह रहा कि इस महामारी के कारण ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। रोज कमाने खाने वाली जनसंख्या को आर्थिक मानसिक समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर ऐसी ग्रामीण जनसंख्या जो नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत थी, लॉकडाउन के चलते उन्हें पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा ताकि वे अपने गृह ग्राम पहुँच सकें। रास्ते में उन्हें अनेक भीषण कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

शिक्षा- कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रभाव ने शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। केन्द्र सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को देश में स्कूल व कॉलेज बंद कराने का निर्माण लिया। इसके बाद 20 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा आठवी तक जनरल प्रमोशन और शेष परीक्षायें बाद में करने का निर्णय लिया। 24 मार्च 2020 को भारत में पहले लॉकडाउन से लगातार स्कूल व कॉलेज बंद है। मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्कूल जाने वाले बच्चों में लगभग 65 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।¹¹ दूसरी ओर अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिये तैयार नहीं है।¹²

कोविड-19 के परिणाम- यह सच है कि इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। इस महामारी के चलते लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन आये जो इस प्रकार है -

- लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हुए।
- साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाने लगा।
- पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आई।
- प्रदूषण में कमी आई।
- कठिन समय में वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता का महत्व सभी को समझ में आया।
- स्वास्थ्यकर्मियों को मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
- “वर्क फ्रॉम होम” कल्चर विकसित हुआ है।

भारत में कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है - हाथों को बार-बार धोना, मुँह पर मास्क का उपयोग करना तथा सबसे महत्वपूर्ण है- सोशल डिस्टेंसिंग जिसे फिजीकल डिस्टेंसिंग कहना ज्यादा उचित होगा। इसके अतिरिक्त उपयोग में आने वाली बाहर से आई वस्तुओं को सेनिटाइज करने के बाद ही इस्तेमाल करें। छींकते व खाँसते समय अपनी नाक व मुँह को कपड़े से ढँक लें। उपयोग किये गये मास्क को सार्वजनिक स्थानों पर न फेंके, अपने मुँह को बार-बार न छुएं, लोगों से हाथ न मिलायें, अतिआवश्यक होने पर ही बाहर निकलें।

भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस महामारी से बचने के लिये सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं हाथों को बार-बार धोने के लिये लगातार लोगो को प्रेरित किया गया। इसके साथ 24 घण्टे/ 7 दिन के लिये हेल्पलाईन नंबर +91-11- 23978046 तथा 1800-180-1104 दिया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. The Economic Times, 25 Feb. 2021
2. The Economic Times, 20 Feb. 2021
3. ABP News 25 Feb. 2021
4. बीबीसी समाचार 30 मार्च 2020
5. नवभारत टाइम्स 2 जनवरी 2021
6. नवभारत टाइम्स 2 जनवरी 202
7. हिन्दुस्तान लाइव 25 जुलाई 2020, hi.wikipedia.org
8. WHO-13 Oct. 2020
9. विकीपीडिया
10. अमर उजाला 9 जुलाई 2020
11. अमर उजाला, वैभव कुमार, 25 फरवरी 2021
12. बैरियर इण्डिया, 13 जून 2020

**Psycho- Socio analysis
of Covid-19 and effect of Gender
Inequality in the Development of Women in India**

•Dr. Mihir Pratap

••Dr. Veena

Introduction- The sense of insecurity, humiliation and helplessness always keeps a woman mum. Our whole socialization is such that for any unsuccessful marriage, which results in such violence or divorce, it is always the woman, who is held responsible. Cultural beliefs and traditions that discriminate against women may be officially discredited but they continue to flourish on the grass root levels. This is basically the problem of gender since centuries in India. Gender inequality refers to the obvious or hidden disparities among individuals based on the performance of gender. Gender bias which in simple terms the gender stratification or making difference between a male or a female.

In India, since independence a number of laws have been enacted in order to provide protection to women. For instance, the Dowry Prohibition Act, 1961, The equal Remuneration Act 1986, The Hindu Marriage Act 1956, The Hindu Succession Act, 1956, as well as Protection of the women from Domestic Violence Act, 2005 etc. However, inequality between men and women can take very many different forms. Indeed, gender inequality is not one homogeneous phenomenon, but a collection of disparate and interlinked problems. The issue of gender inequality is one which has been publically reverberating through society for decades. The problem of inequality in employment being one of the most pressing issues today. In order to examine the situation one must try to get to the root of the problem and must understand the

• Associate Professor and Head Department of Psychology, L.N. College Bhagwanpur, Vaishali, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur.

•• Assistant Professor, Department of Psychology, L.N. College Bhagwanpur, Vaishali, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur.

sociological factors that cause women to have a much more difficult time getting the same benefits, wages and job opportunities as their male counterparts. The society in which we live has been shaped historically by males.

However, in many parts of India, women receive less attention and health care than men do, and particularly girls often receive very much less support than boys. As a result of the gender bias, the mortality rates of females often exceed those of males in these countries. In some regions of India, inequality between women and men directly involves matters of concern, and takes the brutal form of unusually high mortality rates of women and a consequent preponderance of men in the total population, as opposed to the preponderance of women found in societies with little or no gender bias in health care and nutrition. Mortality inequality has been observed extensively in rural area in India.

Types of Gender Inequalities- There are many kinds of gender inequality, which are as follows:

- i. **Natality Inequality-**In this type of inequality a preference is given for boys over girls that many male-dominated societies have. Gender inequality can manifest itself in the form of the parents wanting the newborn to be a boy rather than a girl.
- ii. **Professional of Employment inequality-** In terms of employment as well as promotion in work and occupation, women often face greater handicap than men, India may be quite egalitarian in matters of demography or basic facilities, and even, to a great extent, in higher education, and yet progress to elevated levels of employment and occupation seems to be much more problematic for women than for men. The example of employment inequality can be explained by saying that men get priority in seeking job than women.
- iii. **Ownership inequality-** In Indian societies the ownership of property can also be very unequal. Even basic assets such as home and land may be very asymmetrically shared. The absence of claims to property can not only reduce the voice of women, but also make it harder for women to enter and flourish in commercial, economic

and even some social activities. This type of inequality has existed in most parts of India, though there are also local variations. For example, even though traditional property rights have favored men in the bulk of India.

- iv. Household inequality-There are often enough, basic inequalities in gender relations within the family or the household, which can take many different forms. Even in cases in which there are no overt signs of anti- female bias in, say, survival or son preference or education, or even in promotion to higher executive in terms of sharing the burden of housework and child care. It is, for example, quite common in many societies to take it for granted that while men will naturally work outside the home, women could do it if and only if they could combine it with various inescapable and unequally shared household duties.
- v. Special opportunity Inequality- Even when there is relatively little difference in basic facilities including schooling, the opportunities of higher education may be far fewer for young women than for young men. Indeed, gender bias is higher in education and professional training in India.

The Change and The Cultural Values- Societies and cultures are not static. They are living entities that are continually being renewed and reshaped. As with culture more generally, gender definitions change overtime. Change is shaped by many factors. Cultural change occurs as communities and households respond to social and economic shifts associated with globalization, new technologies, environmental pressures, armed conflict, development projects, change also results from deliberate efforts to influence values through changes in the law or government policy, often due to pressure from civil society. There are many examples of efforts to influence attitudes about rate relations, the rights of workers and the use of the environment, to name three areas in which cultural values shape behavior. Efforts to reshape values about women and gender relations have focused on concerns such as the number of girls sent to school, women's access to paid work, and public attitudes

to domestic violence. New cultural definitions are formed through a process in which some segments of society promote change through advocacy and example, while others resist it. In other words, societies are not homogenous and no assumptions can be made about a consensus on “cultural values”

Cultural values are continually being reinterpreted in response to new needs and conditions. Some values are reaffirmed in this process while others are challenge as no longer appropriate. Gender discrimination has been a global phenomenon for ages and castism some seems like a South Asian nuisance affecting all societies and religion that breed here. However, Hinduism being the oldest culture and fountainhead of all other religions has to accept the blame of polluting the source. Because their two new nuisances where tolerated. The society was weakened and deluged with so many different cults and religions leading to further weaknesses all leading to present mess and all the message of past that we know from history.

Different Interests- Gender identities and gender relations are critical aspects of culture because they shape daily life. Changes in gender relations are often highly contested in part because they have immediate implications for everyone, women and men. This immediacy also means that gender roles and particularly women's role can be potent symbols of cultural changes or cultural continuity. The political potential of such symbols is evident in the ways that religious and political movements have focused on women's roles. This has served to highlight adherence to religious and cultural values and resistance to "western influences" in such contexts, internal efforts for change become even more complex as those advocating change can easily be dismissed as unpatriotic, irreligious, or tainted by the west. However, religious beliefs and national identity are also important to women. This is evident in the efforts by different groups of women to review interpretations of religious text and to reaffirm values and traditions that support freedom and dignity for women.

This example reinforces two points made earlier; that cultural values are constantly evolving rather than fixed and that there are different interests intervening in the process. Views

about the role of women and about gender equality that are held by one person or group will not necessarily be held by others (and views will differ among women as well as among men.) A balanced assessment of the potential for gender equality initiatives requires consultations with a range of actors, including those working for equality.

Post-Soviet countries provide another example. There the rhetoric of gender equality is associated with the propaganda of Soviet period. That women are "free to be women" - free of the requirement to be in the labour force has been referred to as a benefit of the transition by politicians and officials. Women's organizations have noted that this serves to justify discrimination against women, when there are too few jobs for all. Such organizations have been struggling to gain recognition from male dominated political and bureaucratic structures that women want and need to participate in the labour market and to maintain their human rights.

Women's Empowerment- Strategies that support women's empowerment can contribute to women's ability to formulate and advocate their own visions for their society including interpretations and changes to cultural and gender norms. Policy on gender equality emphasizes the importance of women's empowerment to the achievement of gender equality full stock it provides a definition of empowerment and indicates a role for development Corporation. "Empowerment is about people both women and men taking control of their lives, setting their own agendas, gaining skills, building self-confidence, solving problems and developing self-reliance" ourselves to make choices or speak out on their own behalf. However, Institutions include International cooperation agencies to develop their self-reliance and help them set their own agendas.

UNDP's 1995 human development report in making the case for an "engendered approach" highlights the importance of women's empowerment to social and cultural change; " The engendered development model, though aiming to widen choices for both men and women, should not predetermine how different cultures and different societies exercise these choices. Important is that equal opportunities to make a choice exist for both women and men.

Measures to Solve Gender Inequality

- i. Changes at District level mechanism: A clear cut administrative should be made available at the district level for monitoring and reviewing the incidence of inequality against women. This district level machinery headed by District Magistrate should consist of representative of police, prosecution machinery, judiciary and the representatives of prominent individuals of women's organizations in the districts. This committee should review progress of investigation and prosecution. At least one special cell should be established at the district level for ensuring better registration and progress of investigation and monitoring of crimes against gender equality.
The reporting of violence against women from the police station to the district level and from district level to the state level gets obscured in the overall mass and complexities of the currently prescribed reporting system. Specific format should be established and implemented for reporting on gender related crimes.
- ii. Changes at State level mechanism: Similarly, like district level mechanism there should be state level machinery at the state level, in which there should be special entry for those cases which needs prompt actions. This institution will make a full control over the district level machinery so that there should not be any corruption or fraud with innocent persons.
- iii. Family Law: In this situation, the accused can be punished under Domestic Violence Act, 2005 and Dowry Prohibition Act,1987. Other laws relating to family disputes. An area of Civil tort law. Tort law is probably one of the most under-utilized area of the law with respect to the problem of gender injustice. The police officers, prosecutors and judges at all levels of hierarchy need to be exposed to the gender equality education which would enlighten them on existing assumptions , the myths and stereotypes of women and

how these can interfere with fair and equitable administration of justice.

Conclusion- On analyzing the psycho-socio scenario of Covid-19 and effect of gender inequality in the development of women in India, we can conclude that the most significant factor in continued use of law to enforce patriarchal privilege is that men still control not only the legal process and the interpretation of laws. If the subject matter of law is male concerned and if the perspective employed within the the legal process are those of men, then women should actually have no reason to expect that mere reform of existing law will materially improve the condition of women. This is particularly true, when attempts to improve the status of women are made through incremental reforms that are not grounded in an understanding of how women's oppressions are constructed. The Indian Constitution explicitly enshrines formal equality for women. However, the lives and experiences of Indian women relentlessly continue to be characterized by substantive inequality, inequity and discrimination. Gender justice may not be then significant. Finally, one must at least, clearly suggest, what ought to be done. The present Feminist analysis is such a modest endeavour which not only attempts to understand the reality but also tries to explain, how to change it.

The psycho-socio analysis of Covid-19 and the effect of the lockdown in India can be seen that still in India, there is gender inequality in the society, not only in towns and cities but also in rural India, that is, in villages and countryside. India is a developing country and there are many policies and programmes for the upliftment of girl child and women in the society, even though on analyzing the overall situation of Covid-19 in its first phase, that is in 2020 and the situation of Covid-19 in its second phase, that is in 2021, we can conclude in the findings that the gender inequality is prevailing in the educated as well as uneducated families. Psychologists, Sociologists and Policy planners should play an important role in the society to bring gender equality and lessen gender inequality in the society, to a large extent.

References-

1. Article 1 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. (UDHR)
2. Azad India Foundation Gender inequality and women, www.sociologyguide.com
3. Bridger. S. et al, No More Heroines, Russia, Women and the Market.
4. Frontline, English edition
5. Gulati, Urvashi (1995) : Women's Development in India with special reference to Rural women, Kurukshetra, August
6. Hindustan Times, New Delhi edition
7. Issue on "Gender Religion and Spirituality", Gender and Development(OxFam) Vol.7(1) (March 1999) and issue on "Women and Culture", Gender and Development (OxFam) Vol.3(1)(February 1995).
8. KapurPromila, "Empowering the Indian Women", Publication Division, 2001, Pg. 126-127.
9. Mayne's Treatise on Hindu Law and Usage (13th edition, New Delhi : Bharat Law House, 1998)
10. "Men and Masculinity", Gender and Development (OxFam) Vol.5(2)(June 1997).
11. On the extensive role and reach of capabilities of women, See particularly Martha Nussbaum, women and Human Development: The capabilities Approach (Cambridge University Press. 2000)
12. Quoted in SunamNaroghiAnderlim, Women at the Peace Table: Making a Difference. UNIFEM,2000.
13. Sahay Sushama, "Women and Empowerment" Discovering house, New Delhi, 1998, Page no. 11
14. The Times of India, New Delhi edition
15. The UNDP website and men and gender equality provides useful links to various groups and to other resources .<<http://www.Undp.org/gender/programmes/men/men ge.html>>
16. UNDP's 1995 Human Development Report.
17. UNESCO website on culture and development. <http://www.unesco.org/culture/Laws/Mexico/html eng/Page 1.html>.

18. World Health Organisation, Handbook of Human Nutrition Requirement (Geneva : WHO,1974); this was based on the report of a high level expert committee jointly appointed by the WHO and FAO – the Food and Agriculture organisation

Impact of Covid-19 on Indian Economy- An Economic Analysis

•Dr. Vikram Singh

The outbreak of the Covid-19 pandemic is a drastic shock to the Indian economy. This will have longer lasting impact on different sectors like agriculture sector, service sector, financial sector etc. It is estimated for India's gross domestic product (GDP) growth rate to 1.9 percent for 2020-21. This will be lowest after India recorded growth rate at 1.1 per cent in 1991-92. This paper depicts the impact of Covid-19 on different sectors of Indian economy considering the data which are secondary in nature. On the basis of findings suggestions are made to overcome these adverse situations.

Introduction- The global economy is expected to shrink by over 3 % in 2020- The steepest slowdown since the great depression of the 1930s- IMF Report

Covid-19 is a disease caused by a new strain of corona virus. CO stands for corona, VI for virus and D for disease. Covid is a large group of viruses that create illness. It ranges from common cold to severe 'Acute Respiratory Syndrome' and 'Middle East Respiratory Syndrome.' We have been pondering many questions in our mind like will Covid-19 change the way world works, will things go back to normal as before Covid-19 , what will be the fundamental change takes place in common public, business people, industrialists and economies.

The Government of many countries have given support to the employers to pay salaries to their employees and in service sector India spent about US \$ 1.8 billion on space programmes in 2019-20 and the agriculture sector came up with a robust growth rate of 3.4% at constant prices during 2020-21 (first advance estimates) under the Atma Nirbhar Bharat announcements. The lockdown was primarily intended to buy time to prepare the health system and to put together a plan of

• M.A. Economics, C-9, Durga Nursery Road, Udaipur (Rajasthan) 313001

how to deal with the outbreak once the case-load started accelerating. India's public health system is relatively weaker than other countries.

The Government spends only 1.5% of the total GDP on public health as a result of which the system remains grossly under - prepared to deal with a health crisis such as this .In this research paper, we will explore and describe the impact of Covid-19 on different sector of Indian economy.

Review of Literature- This section focuses on the theoretical and empirical findings of the Covid-19 outbreak and the agriculture sector as well as service sector. Mahesh Vyas¹ analyses the world travel and tourism council has projected that travel could fall by 25% in 2020. Putting to risk 12-14% of the jobs in the sector. This translates into 50 million jobs at risk, globally. According to estimates from CMIE's consumer pyramids household survey, travel and tourism account for five percent of total employment in India (nearly 20 million jobs). Hotels and restaurants account for another 4 million jobs. These sectors are going to be disproportionately affected during the on-going crisis.

Himanshu², analysis that the agriculture sector is critical as large number of workers and the entire country's population is dependent on this sector. The performance of agriculture is also key to the state of rural demand. In the pre Covid-19 period, agricultural GDP experienced an average growth rate of 3.3% per year in the six-year period 2014-15 to 2019-20 with intermittent fluctuations.

Himanshu³, Interpreted it may be noted that in rural areas, non farm incomes and employment have been raising. In fact, a NABARD survey shows that only 23% of rural income is from Agriculture (cultivation and livelivestock) if we consider all rural house hold around 44% of Income is from wage labour. 24% percent from government private service and 8% from other enterprises. It Shows that income from Non- farm sector is the major source in rural area. In the pre-Covid-19 period, rural income was partly affected because of lower real wage growth. The success mantra in this Covid-19 period is “You need to live, to be in the game”.⁴

According to official statistics, GDP growth slowed down to 4.2% in 2019-20, the lowest level since 2002-03. Industry which accounts for 30% of GDP, shrunk by 0.58% in Q4, 2019-20. Unemployment reached a 45 year high. The total outstanding investment project between 2015-16 and 2019-20 declined by 2.4%, whereas new projects announced fell by 4% as per data from the CMIE (Center for Monitoring Indian Economy). India has a vast informal sector, the largest in the world, employing closed to 90% of its working population and contributing more than 45% to its overall GDP. This sector will hit by two consecutive shocks in a short span of time, from 2016 to 2019. The first shock was demonetization in November 2016 when 86% of the money in the economy became unusable overnight owing to a government decree, followed by the haphazard introduction of the goods and services tax in 2017. The contact intensive services sector was severely impacted, particularly sub- sectors such as tourism, aviation and hospitality. The first half of FY2020-21 saw services sector contract by almost 16 percent year over year (YOY) was led by a sharp contraction in all sub-sectors particularly 'trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting,' which contracted by 31.5 % in half FY2020-21. Gross value added (GVA) of service sector is estimated to contract by 8.8% in 2020-21 whereas it grew by 5.5% in 2019-20.

Table: 01
Growth in bank credit to services sub-sectors (YOY)

	November 2020	November 2019
Services	8.76	4.84
Transport Operators	10.73	8.14
Computer Software	0.36	-0.39
Tourism, Hotels & Restaurants	18.04	13.09
Shipping	-20.51	5.13
Professional Services	-24.66	1.30
Commercial Real Estate	5.69	6.04
NDFCs	5.65	17.60
Retail Trade	7.84	29.06
Wholesale Trade(excl. food procurement)	15.81	-19.53
Other Services	-3.5	11.3

Source: RBI

Bank credit growth YOY to service sector had moderated significantly between September 2018 and December 2019. However, credit growth to the services sector was stranger in 2020, increasing to 8.76% YOY at the end of November 2020 as compared to 4.84% a year ago. The initial lockdown affect agricultural and necessary supply chains through several channels: input distribution, harvesting, transport hurdles, marketing and processing.

A study by Narayanan (2020) indicates that when initial lock down was imposed in March, farmers were stuck with harvest as APMC (agricultural product market committee) mandis closed in several states. The study indicates that the government should focus on post harvest activities.

Objectives of the Studies

- To focus on the impact of pandemic on different sectors of economy
- To reflect the need for policy intervention

Methodology- This review used secondary data for analysis. As the first step of secondary research, the study developed a research question, “What is the impact Covid-19 outbreak on the agriculture sector as well as service sector in India? “ News articles & Web pages were referred to collect the secondary data. As the first step of the analysis process, a literature review as conducted using the journal articles and various reports available. Thus, the descriptive analysis regarding the agriculture as well as services sector and other supporting sector was conducted using the available data.

Discussion- Globally, the Covid-19 outbreak creates a riskier situation in the service as well as agriculture sector. Governments imposed lockdown, the services and agriculture sector faced depression. Thus, the outbreak of Covid-19 pandemic is drastic shock to the Indian economy, the intense lockdown implemented at the start of the pandemic when India had only a hundred confirmed cases. Characterized India's unique response in several ways. Specially, the policy response was driven by the findings from both epidemiological and economic research.

The policy implemented the Nobel- prize winning research in Hansen and Sargent (2001) that recommends a policy focused on minimizing losses in a worst case scenario.

The spread and intensity of Covid-19 induced twin economic shock can be broadly captured through impact on output/ gross value added (GVA) and employment. In terms of employment shock, contact sensitive sectors like trade, hotels, transport, tourism etc are likely to undergo a shock proportional to the respective employment share. Agriculture was largely insulated from the lockdown in India as timely and supply chain disruptions impacted the flow of agricultural goods leading to high food inflation and adverse initial impact on some major agricultural exports. Agriculture is set to defend the shock of Covid-19 pandemic on the Indian economy in 2020-21 with a growth of 3.4% in both Q1 and Q2 with finding of positively contributed to the overall gross value added (GVA). Rural demand empowered by the governments thrust on the rural economy and infrastructure like rural housing and sanitation, provision of basic amenities under various government schemes and creation of durable assets through MGNREGS. Initiatives for skill development, entrepreneurship, self help groups and livelihoods have empowered rural economy critical steps such as Pm-Kisan, adoption of cost plus 50 percent formula for MSP. Focus on irrigation via PM Krishi Sinchai Yojana, promoting economies of scale through FPO's and institutionalizing e-nam (Electronic National Agricultural Market) which remains a silver lining to India's growth story of FY2020-21. The index of 8 core industries, which make up around 40 Percent of the index, registered a growth of (-) 2.6 % in November, 2020 as compared to a growth of 0.7% in November; 2019 and (-) 0.9% October 2020.

Table: 02
Informal Employment: Number and shares

	Total Employment (in millions)	Informal Employment (in Millions)	% Share of Informal workers in total employment
2004- 05	459.4	430.9	93.5
2011- 12	474.2	436.6	92.5
2017- 18	465.1	421.9	90.7

SouRef: Mehrotra and Parida (2019)

The revitalized inter and intra state movement along with a sustained spurt in industrial and commercial activity heralded the economy's returning to normalcy. E-way bills, electronic toll collection, rail freight and port cargo traffic not just recovered but surpassed previous year level in Q3: 2020-21. The bank credit remain subdued in FY2020-21. While over all bank credit growth and credit to commercial sector gradually picked up from its April lows to reach 6.7% and 6.2% YOY respectively as on 1st January. Credit growth to agriculture and allied activity accelerated to 7.4% in October 2020 from 7.1% in October 2019.

Table 03
Sanctioned Projects and
Completed/Operational Project under PMKSY

Sl. No.	Name of the Scheme	Number of sanctioned Projects	Number of Completed/operational Projects
1	Mega Food Park	37	21
2	Cold Chain	327	210
3	Agro-processing Clusters	55	0
4	Unit Scheme	287	44
5	Backward & Forward Linkages	62	21
6	Operation Greens	5	0
	TOTAL	773	296

PM Garib Kalyan Ann Yojana is announced to aimed at ensuring food and nutritional security to around 80 corer ration card holder who were affected due to Covid-19 induced national lockdown. ₹ 1 lakh crore Agri infrastructure fund is announced for objectives of financing provided for funding agriculture infrastructure project at farm gate and at aggregation points and for financially viable post harvest management infrastructure.

One Nation One Ration Card Scheme is announced for objectives to enable migrant worker and their family members to access PDS benefits from any fair price shop in the country.

Conclusion- This is high time to reset everything as the world become stand still due to the outbreak of Covid-19. We all are allowed to rethink, redesign and restructure everything. Covid-19 has posed an unprecedented challenge for India. Given the large size of the population, the precarious situation of the economy,

specially of the service sector in the Covid-19 period, and the economy's dependence on informal labour, and other measures are turning out to be hugely disruptive. Involvement of state and central governments may also be crucial in the effective implementation of further policies for agriculture and service sector. Policy makers need to be scale up the response as the unfold so as to minimize the impact of the shock on both the formal and informal sector and make the way for a sustained recovery.

References-

1. Economic survey, 2019-20; <https://www.indiabudget.gov.in/economic-survey/>
 2. "A third shock," Mahesh Vyas, CMIE Economic outlook, 16 march, 2020.
 3. Himanshu (2019) Reports that farm incomes grew at around 5.5 % per annum during 2004-05 to 2011-12 but declined to around 1.3% per annum during 2011-12 to 2015-16 and the trend of deceleration continued till 2017-18.
 4. According to Himanshu (2019) the growth rate of real rural wages was more than 6% annum between 2008-12. But, real wages of agricultural labourers grew at 0.87% per annum between may 2014 and December 2018, Whereas for non-agricultural labourers they grew by only 0.23% per annum.
- Chadha, N A DAS, S Gangopadhyay and N Mehta (2017), "Reassessing the impact of demonetization on agriculture and informal sector," India development foundation (IDF), New Delhi, January
 - Himanshu (2019), "India's farm crisis ; decades old and with deep roots," The India forum,
 - IMF (2020), " Policy responses to Covid-19," international monetary fund Washington DC.
 - <https://indianexpress.com/article/explained/explained-how-has-Covid-19-affected-the-global-economy-6410494/>
 - <https://www.livemint.com/news/india/coronavirus-outbreak-in-india-could-cost-the-economy-29-9-billionadb-11583480504316.html>

- Khera,Reetika(2020) “Covid-19: what can be done immediately to help vulnerable population,” ideas for India.
- https://www.ideasfromindia.in/topics/poverty_inequality/Covid-19.
- Narayanan, Sudha(2020), “Food and agriculture during a pandemic: managing the consequences,”
- <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-impact-of-coronavirus-on-indian-economy-1582870052-1>
- <https://bfsi.eletsonline.com/Covid-19-and-its-impact-on-indian-economy/>
- Economic survey, 2019-20; https://www.indiabudget.gov.in/economic_survey/
- Economic survey, 2020-21; https://www.indiabudget.gov.in/economic_survey/

Abbreviations-

- 1- YOY: Year over Year.
- 2- E-NAM: Electronic National Agricultural Market.
- 3- GVA: Gross Value Added.
- 4- ARS: Acute Respiratory Syndrome.
- 5- MERS: Middle East Respiratory Syndrome.
- 6- GDP: Gross Domestic Product.
- 7- ANB: Atma Nirbhar Bharat.
- 8- PMKSY: Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana.
- 9- PMGKAY : Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana.
- 10- APMC: Agricultural Product Market Committee.
- 11- CMIE: Center for Monitoring Indian Economy.
- 12- PDS: Public Distribution System.

Covid-19 Pandemic and Use of ICT in education

• **Dr. Alka Saxena**

Corona virus are a large family of zoonotic viruses that cause illness ranging from the Common Cold, and respiratory diseases. Such as dry cough, fever, shortness of breath, and breathing difficulties. The COVID-19 infection is spread from one person to others via droplets produced from the respiratory syndrome (MERS-COV) of 2012 was found to transmit from dromedary camels to humans. In 2002, severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-COV) was found to transmit from Civet Cats to humans. The COVID-19 pandemic has disrupted the normal functioning of schools and universities.

The WHO officially declared it a Pandemic on March 11, 2020. Countries experiencing the greatest number of cases include China, Iran, Italy. An international Panel of experts undertook a comprehensive assessment and benchmarking of health security and response capabilities across 195 countries. There is obviously no tried and tested method to deal with this situation on hand. The COVID-19 pandemic has disrupted the normal functioning of schools and universities, leading to the necessity of designing alternative methods for transaction of course content and activities.

Due to the contagion of compassion, the concept of Education Always Continues even college, school closed while imparting such education, education is imparted on the basis of various Information Technologies. Teachers and students today are communicating with current new technologies available. Education started with the concept of school from home and online education system. Created in various forms from primary level to higher education teachers in schools, colleges and universities globally have suddenly been forced to upgrade their skills, whether it is in using zoom. Google classroom, registering learners online, developing course ware in LMS

• Associate Professor, D.B.S. College, Kanpur (U.P.)

platforms like Moodle, Canvas, Chamilo, etc. to complete their portions, tutoring, learning how administer quizzes, evaluating homework and assignments, taking attendance, evaluating a students and so forth. For keeping the course's requirements teacher have been forced to handle online platform as the pandemic runs its own course.

Difficulties in use of Technology - Teachers have hesitation to use technology access connectivity is difficult. Many of the students in the schools lack smartphones, computers and Internet Connectivity making it difficult for attending the online classes. Timing of the classes proved inconvenient for many of the teachers as well as the students.

The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning whereby teaching is undertaken remotely and on digital platform research suggests that online learning has been shown to increase retention of information and take less time, meaning the changes corona virus have caused might be here to stay with this sudden shift away from the classroom in many parts of the globe. Some are wondering whether the adoption of online learning will continue to persists post pandemic, and how such a shift would impact the worldwide education market.

In response to significant demand, many online learning platforms are offering free access to their service, including platforms like BYJU'S, a Bangalore- based educational technology and online tutoring firm founded in 2011 which is now the world's most highly valued edtech company.

In case of teacher training, there is a need for training of teacher, both online and offline mode. This in turn necessitates the training of teacher to observe the progress of their students, as well as the training of the mentor teacher in the cooperating schools to be able to monitor the students allotted to them. Mishra and Koehler (2006) identifies three type of knowledge, content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, these three types of knowledge results in successful integration of technology in the teaching learning scenario leading to flexible knowledge. The framework of these three

type of knowledge results in successful integration of technology in the teaching learning scenario leading to flexible knowledge. Punya Mishra and Matthew J. Koehler in 2006 put forth the TPACK frame work which is based on Shulman's (1986, 1989) work on pedagogical content knowledge and technology knowledge.

Conclusion- The TRACK is very important of COVID-19 for effective teaching students should be part of learning community. For this it may be preferable to form groups to work on assigned online activities.

In blended learning also called hybrid learning students have a mix of face to face and online instruction, there are several levels of integration of ICT in educational practice.

In conclusion we can say that use of planning, Review Innovations, Regularity, Actions helped to make students effective through online education. Online education gives learners a more interactive platform for learning and assessment. Online education gives students a opportunity to plan their future course of action and fast track their careers.

References-

1. Novel Coronavirus (COVID-19) situation Dashboard, Centers for Disease Control and Prevention. <https://experience.arcgis.com/experie>:
2. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), NHS Choices, United Kingdom: National Health Service, 3 October 2014.
3. Middle East respiratory syndrome. Zumla A, Hui DS, Perman S. *Lancet*, September 2015.
4. Sarah G Anthony Michaels keating online journal of Distance Learning Administration 16(2), 2013.
5. Radha Mohan's Article published in Edutracks Dec. 2020 pp. 20, 21 <https://www.punyamishra.com/wp-content/uploads/2008/01/Mishra-Koehler-for-2006.pdf>.
6. Best J.W. Khan, J.V. (2010) *Research in Education* (10th Ed). New Delhi.

Companies and Policy Makers Can Create a Happier Future of Work

•Dr. Rajendrakumar Muljibhai Parmar

•• Miss. Dipti Verma

Introduction- Business executives and policymakers have a variety of options to help workers make the challenging skill transitions that COVID-19 has imposed on the most vulnerable members of the workforce. Already, innovative changes they introduced in 2020 suggest a path towards the future.

The COVID-19 crisis demonstrated that workers and companies have greater capacity to adapt more quickly than previously thought. Companies that could shift large segments of their workforces to remote work in a matter of weeks. Most employees adapted easily to online videoconferencing, document-sharing apps, online collaboration systems, and new ways of interacting. Companies without digital channels to reach customers quickly built them, and many consumers embraced digital interactions for the first time. Essential workers in manufacturing and utilities learned to use virtual reality headsets to guide maintenance and repairs from a distance.

The challenge of retraining and redeploying workers into new occupations long-term is greater than adapting to the crisis as it unfolded. As companies look beyond the pandemic, they have an opportunity to reimagine work, their workforce, and their workplace by focusing on specific tasks and activities, not entire jobs. Rather than simply returning to the office and processes previously in place, leading firms are using the pandemic to reconfigure their workforce in ways that boost productivity and engagement, and set a path for future growth. Policy makers could play an important role in expanding the digital infrastructure, supporting workers between jobs, ensuring that lifelong learning becomes a reality and easing

● Assistant Professor, Department of Psychology, Parul Institute of Arts Parul University, At. Po. Limda, Ta. Waghodia, Dist. Vadodara, Gujarat, India

●● Assistant Professor, Department of Psychology, Parul Institute of Arts, Parul University, At. Po. Limda, Ta. Waghodia, Dist. Vadodara, Gujarat, India

barriers to workforce mobility.

An ecosystem approach that brings together businesses, policymakers, educators, and other stakeholders might prove more effective than isolated efforts at addressing workforce challenges, based on past experience. Company initiatives to reskill workers are more robust when supported by educational institutions. The work of educators and social enterprises to train workers in more sought-after skills is most effective when coordinated with efforts by government agencies aligned to company needs. Given the accelerated disruption to work that this report suggests over the coming years, a closely coordinated, comprehensive response could help more workers make the challenging job transitions ahead.

Businesses have an opportunity to reimagine where and how work is done- Businesses looking beyond the pandemic have an opportunity to reimagine how and where work is done, harnessing lessons learned during the pandemic. The virus forced organizations to quickly adapt to unforeseen circumstances. Companies and their employees demonstrated in real-time that rapid changes in work practices and how people do jobs can be accomplished quickly. The same level of quickness can be applied in designing how work will be reorganized and workers retrained and redeployed to meet the needs of the future. Increasingly, technology will be core to the process of work reorganization. In 2017, McKinsey's Global Leadership survey found that 48 percent of business leaders saw technology primarily as a means to reduce costs, often accompanied by labour displacement. The same survey in fall 2020 finds that the vast majority of companies now see technology as a way to build a competitive advantage, expand new products and services, and enable new customer channels and ways of working. Against this backdrop, we offer four thought starters for business leaders as they transition to working in a post pandemic economy.

Assessing who can work remotely by focusing on activities rather than whole jobs- Given that most jobs with remote work potential moved offsite during the pandemic, the first challenge for many companies is to determine what forms of hybrid remote work may endure once vaccines have reduced the virus's

threat. Many organizations are already putting together hybrid remote working strategies with the goal of increasing employee satisfaction and reducing real estate costs.

Creating a successful remote work program requires intentionality. IBM and Yahoo are among the companies that tried and discarded remote work in the prepandemic era. Those prior attempts at widespread telecommuting largely stumbled because companies failed to identify which activities benefit from in-person connections, such as training and onboarding new employees, engaging in critical decision-making, feedback meetings, and building a strong company culture. They also failed to innovate new ways of working and adopt technologies to make remote working a success (although in fairness, many such tools are new).

During COVID-19, some companies began providing “work from home” packages to employees learning to work remotely, offering laptops, video-cameras, MiFi devices, and other supporting technology. To ensure long-term success, companies could first figure out which roles can be fully or partially remote and which need to be done in person. A next step is to define key metrics around productivity, employee satisfaction and connectedness, and innovation, then rigorously measure outcomes across these metrics. Businesses can successfully make the shift to a distributed work operating model by scaling practices that work and changing those that do not making sure to involve employees from the beginning to ensure they feel their voices matter in shaping decisions,

Companies could play a larger role in retraining workers- Companies know best the training they need to develop the skills they want. The changes wrought by COVID-19 open the door for them to play a larger role in retraining workers for new jobs and creating career pathways with upward mobility for their employees in order to ensure a supply of workers with the right skills. Some percent of executives report existing skills gaps or expect to face gaps within the next five years. While companies might be tempted to trim training budgets amid the ongoing crisis, experience shows that investing in retraining can pay off in the long run.

Over the last several years, many large companies

created major reskilling and workforce transformation programs as technology changed the way work was done. Now those programs have taken on new urgency. Faced with a shortage of tech talent, companies like IBM, Bosch, and Barclays started apprenticeship programs to recruit and train workers from non-traditional backgrounds for these roles. Merck, Nike, and more than 30 other companies came together with more than \$100 million to back a new organization, One Ten that aims to train Black Americans and place them in one million new jobs over the next decade. In India, NASSCOM started Future Skills, an initiative that aims to help two million workers acquire skills needed to capitalize on emerging technologies.

Companies could partner with universities, government agencies, and non-profits to retrain workers. In November 2020, the European Commission initiated the Pact for Skills, which provides incentives for businesses and other stakeholders to help in overcoming the mismatch between skills and available jobs. One of the Pact's goals is to build the skills of 5 percent of workers in the automotive industry each year, investing €7 billion to reskill 700,000 employees annually.

Focusing on skills rather than academic degrees when listing jobs and recruiting can ease occupational transitions- Focusing recruitment on skills rather than academic degrees can expand the pool of available job candidates and increase diversity for companies while helping ease the broad workforce transitions likely to play out after COVID-19. The number of major employers hiring based on skills needed rather than on educational achievement has grown, offering viable models for others. Google, Hilton Hotels, Ernst & Young, and IBM are among the companies that have made that change, and they report a marked increase in new hires without college degrees. The United States' Business Roundtable is developing an initiative that encourages organizations to focus on skill-based hiring as a way to drive diversity in the workplace.

Such hiring requires the ability to quickly identify and verify skills of potential employees. Easily accessible tools to consistently recognize skillsets across workers have only recently come online. Workday has developed an AI system

that gathers data on skills and matches workers to roles or suggests new training opportunities. Eightfold.ai, FMI (The Food Industry Association), and McKinsey & Company partnered to create Talent Exchange, a platform that uses AI to match workers in arenas hit hard by the pandemic, such as travel and leisure and on-site customer interaction, to roles in companies that are expanding. Deployment of more such technology solutions could enable organizations to lower barriers to transitions by hiring based on skills rather than degrees or qualifications.

Diversity and inclusion measures can help counter COVID-19's regressive impact- As this report has demonstrated, women, younger workers, less educated workers, and diminished ethnic groups are likely to grapple with a disproportionate number of occupation transitions over the next decade. With school closures and higher risks of becoming sick, pressures on at-home caregivers more often women and people of colour is higher than ever. Research consistently shows that efforts to promote diversity and inclusivity improve employee wellbeing and performance, as well as economic outcomes for businesses.

Some companies have offered greater work flexibility to support these employees. Starbucks temporarily expanded its Care Work program, which subsidizes paid care for children and elderly adults. Up work partnered with Awaken, a diversity and inclusion consultancy, to hold a forum addressing the uptick of racism and discrimination during the pandemic.

Policy makers have a range of options, including expanding the digital infrastructure and supporting workers in transition- Policymakers have an important role to play in easing the workforce transitions necessary to avoid high unemployment and workers dropping out of the labour force. There are many ways to do this, and we offer a few options to consider and examples from around the world here.

Expanding the digital infrastructure- Even in advanced economies, up to 19 percent of households lack access to internet services. This excludes their members from educational and work opportunities, not to mention participating in the online economy that boomed during the pandemic. McKinsey

research in the United States found that learning losses from the pandemic could wipe out the equivalent of one year of salary on average and more for underrepresented ethnic groups. In some school districts, as many as a third of the students were unable to log into online classes during the pandemic, putting them further behind academically. The number of drop-outs from college and high school is set to rise due to the pandemic as some students lacked the online access needed to participate in remote classes. Besides students, workers with insufficient internet connectivity to work from home also were at a disadvantage the state of Connecticut, for example, provides funding to help small towns get wired through the Community Connectivity Program. Enabling all individuals to participate in and benefit from the growing digital economy will require more public investment.

Supporting workers during occupational transitions- Many countries extended financial support to workers who lost jobs in the early days of the pandemic. Data on personal income and spending in subsequent months confirmed that these actions supported personal income and helped stave off more severe and sustained economic damage in the India. In an era in which mid-career workers are likely to need to retrain to change occupations, new or expanded forms of income support may be warranted.

Among possible options, policy makers could consider new ways to modernize and strengthen the social safety net to support people transitioning between jobs or facing significant wage cuts due to automation. Support could take many forms, including more flexible income support programs, relocation assistance, training grants, increased minimum wages, and reformed tax systems. In the United States, individuals qualify for unemployment benefits only when laid off, not when they leave a job voluntarily. This discourages workers from capitalizing on better opportunities, taking time to gain new skills, or shifting to more in-demand occupations. Tax incentives to encourage employers to offer and allow employees to take advantage of job retraining could head off potential displacements before they occur beyond supporting workers financially and helping them reskill, public leaders can help workers better navigate the transition process. The Harvard Business Review found that in many cases, workers struggle to

find a new job not because they lack skills but because they lack access to relevant and actionable information needed to navigate the job transition process. Many workers don't know what jobs their skills equip them for. By providing greater transparency to workers about their occupation transition options, and by adopting skills centric rather than an experience-centric or credential-centric approach when connecting workers to new employment opportunities, government agencies can improve the match between workers and jobs.

Expanding workforce benefits and protections to cover independent workers- Many jurisdictions are considering how they might revamp labour market policies and benefits for the growing independent workforce. For the first time during the pandemic, many independent workers show across countries were temporarily offered similar support extended to hourly wage employees. Crafting sustainable benefits policies to cover a larger share of the workforce and better suited to a modern labour market could merit further consideration.

Many types of policy changes could help. Some countries and companies are defining an intermediate class of worker who has some protections of traditional employees. In response to proposed legislation in California to reclassify drivers as employees rather than contractors, Uber has proposed that show platform companies establish benefits funds for independent workers, giving those cash to spend on the benefits they want. In 2019, the European Parliament approved new rules to protect performance economy workers in the European Union, ensuring more predictable work hours and payment for cancelled work.

Discussion is under way about how to modernize the social safety net for traditional workers who change jobs more often than in the past, as well as for independent workers who do not have a single employer. Where companies rather than governments provide many worker benefits, policymakers have for several years discussed creating a more portable system of benefits tied to workers themselves, not to a single employer. One option is allow independent workers to form pools to create their own marketplaces and delivery systems for benefits. This model already has a long and successful history in industries ranging from Hollywood to construction: workers shift from

project to project, and their unions or guilds deliver a range of benefits such as health insurance. Alia is an online platform for portable benefits, which enables its clients to pool benefits from multiple employers in a single pot that they can draw on to cover sick pay, life insurance, and paid time off. Another proposal involves a so-called “hours bank.” Policymakers might consider working to resolve the many hurdles such proposals face, starting with who would pay for such benefits and how they would be earned and tracked for workers with multiple clients and employers or working independently.

Supporting lifelong learning and expand mid-career training options- Lifelong learning is critical to enabling the large-scale workforce transitions approaching. Individuals might consider embracing the idea of periodically reinventing themselves that is, creating a mind-set of lifelong employability. Jamie Merisotis, president of the Lumina Foundation, calls these workers “worker-learners.” As technologies shift the tasks required in an occupation, education will also need to shift focus and teach the social and emotional skills that machines cannot master.

Transparent, nationally recognized credentials that verify workforce skills particularly those learned on the job—could help ease transitions. Ideally, individuals would continually earn new, verifiable skill credentials throughout their career, through job experience and training programs.

Education need not only occur early in life. Higher education has long been a stepping stone between high school and work, but the typical student of the future may be a 35 or 45 year old looking to reboot her education. Mid-career workers also need short-term continuing education programs, and some schools are already seizing this opportunity. At the other end of the spectrum, “early college high schools” combine a high school degree with an associate degree, which is all that's needed for many jobs. Now, in more than 30 US states, early college high schools allow students to earn an associate's degree or college credits towards a bachelor's degree while still in high school.

Lowering barriers to physical mobility- In some countries, workers cannot easily move locations, which restrict their ability to adjust to rapid changes in labour demand. Workers who can work remotely may move out of major cities to suburbs,

smaller cities, or even other countries. Several mid-size and smaller cities in the India are offering financial incentives for workers to move. For emerging economies such as India, migration to urban areas will remain significant, as job growth in those countries will likely be concentrated in cities over the next decade. Even so, many workers face barriers to moving into cities. Affordable housing schemes could be expedited, such as one launched in India for domestic migrant labour under the government's Pradhan Mantri Awas Yojana program.

Lowering barriers to occupational mobility- Licensing ensures professionals have the requisite skills and training and protects consumers, but it can also limit competition and limit occupational mobility. Indeed, across the United States, there is evidence that the greater the licensing requirements across a workforce, the lower the mobility of workers between occupations. The Harvard Business Review found that opticians received a 5 percent premium from consumers for each additional exam required by the state. National and local policymakers have opportunities to reconsider licensing in ways that preserve safety and protect consumers yet also enable labour market fluidity.

The job disruptions and transitions that COVID-19 has kick-started will affect more workers and more disadvantaged workers more quickly, according to our research. Companies and governments proved during the pandemic that they can move swiftly to help workers. To help workers make job changes in the future, more innovations may be needed. The reward would be a more resilient, more talented, and better-paid workforce—and a more robust and equitable society.

Investment in new technology- We identify trends between rising GDP per capita and spend on information technology. For enterprise IT spending, we find that a country's GDP is correlated with the amount spent on hardware, software, and IT services. For consumer technology spending, we consider only the hardware and software components of spend, finding that the richer a population (meaning the higher the GDP per capita), the higher it's spending on technology. We use univariate linear regression analyses to find a relationship between 2018 GDP per capita as the independent variable and each category of IT

spending per capita in 2018 (including consumer and enterprise spending) as the dependent variable across all 53 countries. These categories of IT spending are then multiplied by productivity-adjusted job multipliers for 2018 and 2030 to calculate net new jobs. All data are based on historical baselines from the IDC Worldwide Black Book published in November 2020. Finally, we use indirect multipliers to capture jobs created in sectors supplying to the IT sector.

Because the consumer technology element of rising incomes is captured within this driver, we omit it from the rising incomes driver. Likewise, since the infrastructure driver captures telecommunications and electric utilities, we do not consider increase in technology infrastructure spend as part of our technology definition, in order to avoid double counting. Finally, this driver assumes that technology spend grows according to current trends and thus does not consider the scenarios of extraordinary technology spend that are possible in more rapid automation scenarios.

Shift away from fossil fuels and greening of the economy-

This labour demand driver captures the potential job creation due to the shift in mix of electricity generation. The potential increase in jobs in electric power generation due to increase in demand for power is captured in the utilities category of consumer spending driven by rising incomes. We avoid double counting by isolating the mix shift effect in this driver. Using McKinsey modelled scenarios for gigawatt capacity in 2030, we multiply projected GW capacity by jobs per GW multiplier across manufacturing, decommissioning, fuels, construction and installation, operations, and maintenance by energy type, such as solar, coal, and gas. Given the rapid and hard-to-predict changes in productivity in the renewables value chain, we model a minimum scenario in which rapid productivity growth continues and a maximum scenario in which productivity gains plateau. We then shift GW capacity toward renewables targets that could help slow global temperature increases to two degrees Celsius above preindustrial levels. This shift results in greater numbers of jobs created to change the energy generation mix by country.

Marketization of currently unpaid home work- We use

local time-use surveys to understand the amount of time spent in various countries on unpaid domestic work, including cooking, cleaning, childcare, and eldercare. We estimate the number of hours that can be professionalized by reducing the number of hours spent on a given domestic activity closer to the lowest value among peer countries, taking into account what reduction can be realistically achieved by 2030. We then make assumptions about productivity gains in each activity through professionalization to estimate the potential for new labour demand creation.

Increased remote work and virtual meetings- This trend consists of two effects: the fall in demand for certain goods and services due to increased remote working and the fall in spending in the travel and hospitality industry from reduced business travel. For remote work, we first identify occupations that may be affected by a fall in demand for commuting services and office management for instance, subway drivers and office custodians. We then estimate the number of jobs displaced due to increased remote work by applying remote work potential estimates from the effective potential scenario described above; an increase in remote work causes a commensurate fall in demand for these services and thus labour demand for identified occupations. For job displacement due to reduced business travel, we create two scenarios for spending using data and forecasts from the Oxford Economics Tourism Model: pre-COVID-19 and post-COVID-19. In the pre-COVID-19 scenario, spending in 2030 is estimated by applying historical trends from 2019. In the post-COVID-19 scenario, spending in 2030 is estimated by applying historical growth rates from 2022; business travel that did not return by 2022 is assumed to be replaced by virtual ways of working. The difference in spending between the pre- and the post-COVID-19 scenarios is converted to job displacement using job multipliers.

Scale employment proportionally to return to full employment- To calculate final net labour demand in 2030, we sum the sized job gains and losses from the relevant trends and 2030 baseline employment. In the pre-COVID-19 scenario, this is displacement in MGI's midpoint automation scenario and job

gains from seven long-term trends. In the post pandemic scenario, it is all the effects from the pre-COVID-19 scenario and the job gains and losses from the three COVID-19 trends. This gives us a new distribution of jobs across our more than 800 occupations. After summing job losses and gains, national employment may not correspond to the initial calculated employment—we add or subtract jobs across occupations using the distribution after applying our trends to return to the calculated full employment baseline; this preserves a mix of occupations after applying our trends while assuming we return to full employment by 2030.

Impact of labour demand changes by demographic group-

We estimate the impact of labour demand changes by different demographic groups, and measure the impact of labour demand changes, on the change in distribution of workers across wage brackets.

The different demographic groups we investigate are women, low-wage workers, young workers, those without a college degree, members of ethnic minority groups, and immigrants. For the United States, we use data from the Bureau of Labour Statistics, and for Europe we use data from Eurostat for the number of hours worked by a full-time employee in a year. For occupations with no published hourly wage, the annual wage is calculated from reported survey data. We calculate three wage brackets: the low-wage bracket includes the 30 percent of the workforce that earns the lowest wages; the high-wage bracket includes the 30 percent earning the highest wages, and the middle-wage bracket includes the 40 percent of the workforce earning wages in between those earned in high- and low-wage brackets. In India, 41 percent of the workforce as of 2018 was employed in agricultural occupations, which are typically low wage. So we use different wage bracket classifications for India's workforce: The high-wage bracket covers the top earning 20 percent of the workforce, the low-wage bracket the lowest earning 40 percent, and the middle-wage bracket includes the 40 percent earning wages between the low- and high-wage brackets.

Job transitions and skill shifts- For advanced economies, namely France, Germany, Japan, Spain, the United Kingdom, and the United States, job transitions are defined as jobs in net

declining occupations compared to the 2030 baseline. For developing economies, namely India and China, due to data accuracy challenges, we put each occupation in one of 60 categories—for example, production workers—and one of five skill levels. A worker would need to make an occupational transition if their job is in a category and skill combination that is, on net, seeing labour demand declines compared to the 2030 baseline. For details on how we estimate baseline and net labour demand by occupation, see section 3, above.

Skill shifts- We seek to quantify skill shifts using a set of 25 workforce skills in five categories: physical and manual, basic cognitive, higher cognitive, social and emotional, and technological skills. These skills are based on previous MGI work, primarily the 17 skills used in the report *Artificial intelligence: The next digital frontier?* (2017) as well as other frameworks used externally.

While workers use multiple skills to perform a given activity, for the purposes of our quantification, we identify the main skill used. For example, in banking and insurance, we map “prepare business correspondence” and “prepare legal or investigatory documentation” to the skill “advanced literacy and writing,” which is grouped in the category of higher cognitive skills. In retail, we classify “stock products or parts” in “gross motor skills and strength” in the category of physical and manual skills, while “greeting customers, patrons, or visitors” is mapped to “basic communication skills” in the basic cognitive category.

Since our approach draws each individual activity to a single skill, only pure IT activities such as operating a computer are tagged under “basic digital skills.” This understates the importance of this group of skills, as workers' aptitude at working with digital technologies has increasingly become a core part of many positions that are not typically thought of as IT jobs. For example, designers today need to be able to work with computer-based design software, and fluency with digital tools is a prerequisite. We consequently apply a refinement to correct for the digital component of work not being fully reflected in the activities associated with most jobs. We reallocate a portion of hours from activities requiring non technological skills to basic digital skills to account for their digital requirements. For

example, professional driving now often requires the use of GPS and thus some basic digital skills.

Potential limitations- In addition to smaller warnings we have noted, we acknowledge some larger limitations to our research. This report models only one post COVID-19 scenario out of the numerous possible outcomes; it is not an attempt to forecast conditions in 2030. Our models rely on macroeconomic forecasts, for example of GDP growth and unemployment, as of the fourth quarter of 2020. Many factors could cause our macroeconomic assumptions to diverge from reality, including geopolitical tensions, a new recession or unforeseen national events, and changes to government policy. Many governments have also announced large COVID-19 budgets, and how these are spent could affect the shape of the labour market; for instance, some countries are aiming to spend more on environmental investment, which could shift jobs to the green economy.

We also make the following simplifying assumptions, which may cause our analysis to over- or understate the disruption we could see in the next decade:

- **Modelling a limited set of trends-** We model only the effects of our short-listed long-term and COVID-19 trends. Other factors that we have left out could affect labour markets.
- **Using Non dynamic and unlinked models-** Our models do not take into account dynamic adjustments that will occur after the impact of each trend; wages may fall, for example, reducing the incentive for firms to adopt automation and reduce displacement rates. Our trends are also modelled separately and do not account for the interconnectivity between trends; for instance, automation may boost productivity, which may cause incomes to rise further and boost job creation among higher-wage occupations
- **Assuming a return to full employment-** We assume that employment levels will not be affected by the pandemic in the long run. In particular, we assume that

the unemployment rate will return to the long-term trend rate and that participation rates and population growth will continue in line with prepandemic expectations. This may not be the case; for instance, long-term structural unemployment could result if workers lose skills and cannot return to the labour market (so called labour market scarring) or if workers cannot retrain quickly enough to match changing demand for skills.

Variation in government response to the pandemic: Many governments are spending large sums on responding to the COVID-19 pandemic and plan to continue doing so. Where they choose to invest these funds may affect some of the assumptions we have taken in our modelling.

References-

- Engaging the Online Learner Activities and Resources for Creative Instruction (Jossey-Bass Guides to Online Teaching and Learning) by Rita-Marie Conrad, J. Ana Donaldson
- Lessons from Lockdown The Educational Legacy of Covid-19 by Tony Breslin
- Industry 4.0 Industrial Revolution of the 21st Century by Elena G. Popkova, Yulia V. Ragulina, Aleksei V. Bogoviz
- The Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab
- The future of work after COVID-19 by McKinsey Global Institute
- Impact of the Covid-19, Pandemic on Trade and Development, Transitioning to a New Normal by United Nations Conference on Trade and Development
- Together Apart The Psychology of COVID-19 by Jolanda Jetten, Stephen D. Reicher, S. Alexander Haslam, Tegan Cruwys
- Global pandemic threats a reference handbook by Michael C. LeMay
- The Psychology of Covid-19 Building Resilience for Future Pandemics by Joel Vos
- The Psychology of Pandemics Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease by Steven Taylor

- The Psychology of Pandemics Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease by Steven Taylor

The Challenges of Parenting during Covid Times

• **Dr. Sonal Singhvi Choudhary**

Even in the wildest of dreams did the world even imagine that a virus, hitherto unheard of, would create such havoc driving the entire planet topsy turvy? It has transformed nearly every aspect of our lives. From lockdowns and social distancing to working from home, our daily routines have been completely overhauled. It has led to a dramatic loss of human life worldwide and presents an unprecedented challenge to entire mankind. The economic and social disruption caused by the pandemic is devastating. Human civilization itself faces an existential threat. It is a social and an economic crisis just as much as it is a health one – its repercussions, severe and far-reaching, are being felt across the world. From school closures to devastated industries and millions of jobs lost, the social and economic costs of the pandemic are many and varied. Covid-19 is threatening to widen inequalities everywhere, undermine progress, and has put life on a standstill. It has set us back on decades on progress.

Parenting was never an easy job, and the pandemic has made it even more difficult. Parents and children have both reported positive and negative psychosocial impacts of the virus. A Parent would always want to do everything to protect his/her child. The pandemic has brought with it new challenges for families across the globe. It has shaken up families all over the world. As homes function simultaneously as school, office and living space, parents are finding themselves in a fix. Even though parents now have more time for their children, the pressure to juggle multiple roles is stressful. As children and parents stay confined to their homes, parents are finding it difficult to focus on different aspects of their child's overall development.

With [schools closed](#), parents have had to take up the role of being both parent and teacher. At this time, most parents

• Assistant Professor, Department of English, Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)

may feel like their space has been raided by their children and we are all trying to figure out how to balance between [working from home](#) and ensuring our children stay on track with their [learning](#). Parents are adapting to a new routine and as hectic it may seem, it is important that children feel supported in their academics as this is also a new adjustment for them. Parents have become the de facto home school teachers and tuition teachers. Unfortunately, they are finding it difficult to keep their children on track and help them with assignments. The difficulty becomes multifold if the children happen to be in different grades. Ensuring that children attend the online classes as per the timetable, complete their homework and send it to the teacher and prepare for the next day's class has been a cause of worry for many parents.

Parents play a pivotal role in shaping the character of children as they grow towards adulthood. As a parent and teacher, the [COVID-19 period](#) presents the opportunity for parents to be engaged in the lives of their children like never before. Every parent should develop a habit of keeping constant and continuous communication with the teachers who engage with their children. With remote learning in place, it has become much easier for families to have one on one contact. Parents could schedule a virtual meeting with the teacher to catch up with their child's progress. This not only shows children that you care but also assures the teacher that you value what they are doing and that you are committed to supporting the benefit of your child. Parents should keep monitoring the academic progress of their children, but at the same time they should be careful enough not to keep nagging them all the time. Now that the children are learning from home, parents have so much visibility into the lessons that happen in class. They could spare some time and discuss lessons or assignments. This is also a great opportunity to go through their academic reports with them and prompt questions on their performance on areas they need assistance on.

Children will be spending most of their time at home at the moment, so it is worth making your environment as comfortable as possible. Think of ways how you can make it a

more pleasant place to be. It is also a great idea to share one's personal school experiences with one's children. Parents should always create time to interact with their children and share their experiences both positive and negative during their days as students. Feel free to share their moments of glory as students and those painful moments that shaped them into the people they are. Such stories make children feel easy around their parents and will no longer look at them as super humans that only lead perfect lives devoid of mistakes. This will, in turn, encourage the child to open up and share any academic challenges that they are encountering.

Normalizing failures and making it part of everyday life creates a safe space for learners to be innovative and risk-takers. Parents who encourage their children to constantly try new things without fear of being reprimanded stand a better chance of raising children into adults that are innovating and critical thinkers. Successful people will always tell you that the best way to succeed in life is not to be afraid of failing. Trying to rule your children with an iron fist may work only when they are still young but upon attaining the adolescent age, this may be a difficult road to travel. Parents should be open to their children and must demonstrate the commitment to supporting them in whatever way possible. Create opportunities for them to bring their thoughts onto the table and see how they can support them. Children who feel listened to by adults also grow up to be people who are considerate and accommodative of others.

Students who perform well will maintain their good results if they are regularly appreciated. Parents should devise a way of appreciating their learners every time they bring improved results home. This will continue to motivate them to work hard at all times and maintain high expectations. However, parents should be careful when rewarding good performance. They should make it very clear to their children that it is not a bribe to maintain good performance but rather an appreciation for doing well.

Having a structured routine for children always helps, or else the children end up spending a lot of time with their mobiles and laptops. As it is, attending online classes puts an immense stress on the eyes, and young children start slouching. A

structured routine helps maintain the physical and mental health of the child. Regular physical exercise keeps the child fit and happy. It also boosts the immunity and helps the child to fight infections and diseases. Yoga and meditation would work wonders for children. Meditation makes them calm and cool and helps them to reduce any kind of stress. It also helps in increasing the concentration levels by teaching the child to focus her mind.

It is the love, support and empathy of parents that can help children fight every kind of tricky situation in these tough times. One should also always remember that it is impossible to be a perfect parent, but it is great to be a real one.

**“Effect of Online Classes
on Children and Teen's Mental Health:
A Case Study of Howrah District, West Bengal.”**

• **Dr. Anuradha Guha Thakurata**

Corona pandemic has affected all aspect of human life including children. Whether it's the mental health physical health or a combination of both. Children lost their normal childhood; students have lost their mainstream and regular mode of studies. They cannot go to schools. They are deprived from the company, from the peer learners and friends. Increasing eyesight problems with frequent headaches are attributed to prolonged screen time. In addition, increasing anxiety and depression due to home confinement along with sleep disorders are also on the rise. Children attending online classes at home are not bound to have class room professionalism.

Introduction- COVID-19 has rapidly and dramatically altered our lives. Unfortunately, teenagers and young adults are among those who may be most impacted as a result of the virus. In the spring and summer month of 2020, the COVID-19 pandemic drove many schools to cancel in-person classes and graduation ceremonies. Now as we enter fall, many schools and colleges continue to rely on virtual learning to keep students and teachers safe.

While the safety of students and teachers is of the utmost importance, online learning can have impact on the mental health of teens as well as on children. Online learning affects everyone from young children to young adults, teachers and professors. For many students, virtual classes may worsen existing mental health disorders. For others, the impact of the pandemic and online learning can trigger new changes in mental health and mood.

The wave of Corona virus in India has Left many children without access to health, education, since the floods of cases on the rise, they were advised to acquire their education in a distance or in virtual learning environment. However, in a country like ours when only a privileged minority has access to

• Assistant Professor in Geography, Syamsundar College, East Burdwan West Bengal

the internet, learning has been tough for many kids. The pressure still continues as they are required to catch up with their syllabus using their limited resources and hence suffering through significant stress and other mental problem.

The major factors affecting the mental health of children can be narrowed down to parental angst, social isolation, uncertainty, lack of proper schedule. What may seem irrelevant to us may possibly be the biggest concern for the children like not being able to see their Friends, inability to focus in online classes unable to have a gateway and fear of missing out.

Like adults, children also have emotional needs that sometimes parents fail to acknowledge and children fail to communicate which leads to unexplained anxiety that in their personality leading to long term issues with attachment patterns and self esteem.

The concept of online classes was something that none of them were really prepared for adapting to something that drastic all of a sudden is a big move. Some kids responded to it positively, but studies show that most focus on online classes. It is easy to be distracted as they have their devices with access to the internet. They struggle to do assignments and projects especially introverted children find it extremely difficult to participate in online classes. This absence of a structured routine of going to school and having a strict time table was designed for holistic development is affecting the children in noticeable ways.

There is a lack of innovative ideas, barely any engagement and lack of extracurricular which is making the curriculum really mundane and uninteresting hence difficult for the children to concentrate on. Among teenager students who had to give their board exams or students who are transitioning from schools to colleges. These people have had to face severe stress and anxiety due to uncertainty, confusion and fear of failing to make the right career choice.

Objectives- The main objectives of this paper is to highlight the mental health of children and teenager students during COVID-19 pandemic situation as they are the major as well as younger segment of population. This paper tries to highlight the mental condition of those students of Howrah district who are going to appear in board exam both in secondary and higher secondary level.

Methodology- This study is based on primary data. To elicit information about mental condition of student's total 185 students of different classes and age groups were interviewed over mobile conversation. Around 15-20 minutes were taken to complete each interview over telephone. Due to pandemic situation survey was conducted only in Howrah suburban area. Survey was conducted among local school students who are living in and around about 15 kilometer radius from Bally. Both rural and urban children were considered as it is general issue. Mobile numbers of the students were collected from friends, different school students oriented whatsapp groups and also from surrounding neighbors and private tutors belonging to different cultural and academic groups. Information also gathered from parents

Findings- The findings of the paper are as follows –

1. **Social Isolation-** School is also the centre of many teens and children's social lives. School offers teenagers and children an opportunity for them to socialize and express themselves. However, with schools and colleges moving to virtual formats, teens may feel lonely, unmotivated or discouraged without regular social interaction. Numerous studies have shown social isolation can cause higher rates of negative outcomes for the mental and physical health of individuals. The face to face interactions can help reduce depression and anxiety. Less social interaction may increase feelings of social anxiety and pressures. The survey reveals that out of 185 students total 53 teenagers (28.6%) and 12 (0.6%) children are facing mental depression and anxiety. Few of them are also consulting with psychiatrist regarding this issue.

2. **Increased stress and anxiety-** lack of social interaction and online class structure are affecting teens and children in a number of ways. They are feeling heightened anxiety about keeping up to date with their school work. Out of 185 students 42 students (22.7%) are facing this problem. Parents are also getting panic on this matter. Among children this problem is a serious issue. On an average 31.5% students including children and teenager are getting difficulty to concentrate in their study at home. Total 14.8% teenagers and parents of 20.5% children

have shared their views that they are facing problems as well as anxieties to appear in front of others on video call. Most of the suburb students (42.6%) are facing difficulties to receive the extra education support that they need to succeed. Students belonging to lower income group (6.5%) are facing huge problems because most of them do not have android set and are depended on relatives, friends. Extra payment for internet connection sometimes are causing economic burden for them and unaffordable also. On an average 58% students are facing network problem.

3. Virtual learning Fatigue- Spending a significant amount fatigue both on students and teachers which is commonly known as “Zoom fatigue”. Full day video interaction are causing headache, eye problem and body pain among students. On an average 19.5% students are facing such problem. Prolonged confinement at home has made them excessively dependent on the internet and resulting in them finding unhealthy coping mechanism and makes them vulnerable to online bullying. They turn irritable, short tempered, go distant from family members.

“Technology has been integrated into every aspect of modern life. It is not possible in all but the most remote cultures to not be exposed to some sort of technology allows human to connect without the limitations of geography. It makes processes more efficient and if supplements the intellect and effectiveness of the human brain. Although it has a very significant number of very positive attributes, the populace as a whole often does not consider it also has negative attributes as well. Youth are particularly susceptible to these potentially negative effects”¹. According to the few Research center “Over 88% of teens have access to cell phones and many teens sleep with their phones”².

Steps To Control This Issue

1. Guardians and educators are urged to encourage the kids to give their hand in arts which helps them cope with emotions like anxiety, aggression and sadness.
2. The free time could also be utilized by the kids to find their interest and engage in co-curricular activities. At the end of the day, the kids should learn how to freely express themselves and cope with their feelings in a healthy way.

3. For parents of teenagers it is advisable to focus on healthy parenting, regular engagement with their children is interactive, show interest in their day to day activities, help in maintaining a consistent routine for their children. So the child doesn't feel lost.
4. For slightly olden parents it is recommended to try and have healthy and open communication with their children be positive role models, promote adaptive coping, play a supportive role, and if required help their children seek help.
5. “When learning resumes on campus the educations have to focus on making up for the lost time without putting excessive pressure on the children. Identify children who are struggling and help them in collaboration with their parents or by referring them to school counselors.”³
6. “With online classes, students may experience challenges as it relates to increased screen time.”⁴
7. “Despite the potential for virtual classes to impact a teen's mental health negatively there are still some positive benefits.”⁵
8. For some students, being home and around family, particularly during the COVID-19 pandemic, can offer feelings of safety and reassurance. For these students, their home can become a safe learning environmental where they feel more productive.
9. In addition, while school is a place for teens to socialize and from friendships not all social interactions are positive. Students may become victims of bullied at school. For these students, virtual learning offers escape from depression and anxiety caused by the fear of being bullied. For other Students, virtual classes can also provide an escape from the constant weight of peer pressure.

Conclusion- COVID-19 has changed our overall lifestyle. All the educational institutions are closed which causes huge impact on childhood. Their lives become so miserable. They lost their normal childhood. They are deprived from the company, from the peer learners and friends. A good night of sleep, a healthful

diet, extra co-curricular activities, regular exercise can help and boost up their mood which have finally create a positive impact on their mental well-being.

References-

1. Halupa Colleen. (Nov, 2016), “Risks: The impact of online learning and technology. On student Physical, Mental, Emotional and Social health, A.T. Still Healthy sciences university, USA, PP. 130-136.
2. Pew Research Centre (2015), “Teens Social Media and Technology Overview 2015”. Smart Phone facilitate Shifts in communication landscape for teens”, Retrieved from <http://www.pewinternet.org/2015/04/09/mobile-access-shifts-social-media-use-and-other-online-activities/>
3. “How remote learning is affecting students mental health: Check 5 steps to tackle the issue”, India Today Web Desk, New Delhi, March 2,2021, 15.27 IST Retrieved from <https://www.indiatoday.in.cdn.ampproject.org>
4. Wiles, Giffin., (July 30,2020) “students share impact of online classes on their mental health”, The state news, Retrieved from http://statenews.com/article/2020/07/students-share-impact-of-online-classes-on-their-mental-health.tt.act=content-open&cv=cbox_featured
5. “Online learning and teen mental health”, Retrieved from <http://highfocuscentres.pyramidhealthcarepa.com.cdn.mpproject.org>.

- सम्पादक परिचय -

डॉ. एस. अखिलेश एक ऐसे युवा समाज वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिये छः बार प्रतिष्ठित 'पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त एवार्ड' तथा सन् 2006 में भारत सरकार द्वारा 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड' से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल प्रारम्भ से ही एक मेधावी अध्येता रहे हैं। जिन्होंने 'जुविनाइल डिप्लोमार्केंसी' जैसे गूढ़ विषय पर शोध कार्य पूर्ण करके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से डॉक्टर आफ फिलासफी की उपाधि 1994 में अर्जित की।



1997-98 में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, भारत सरकार द्वारा 'गोल्डन जुबली रिसर्च फेलोशिप' स्वीकृत की गई थी। डॉ. अखिलेश को 'प्रो. रमाकुमार सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल' (1990) से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल की अभी तक 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. अखिलेश के 300 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिसर्च जरनल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक शोध पत्र प्रकाशनाधीन हैं। डॉ. अखिलेश इस समय शासकीय टी.आर.एस. आठेनामस कालेज (एक्सिलेन्स सेन्टर) रीवा में कार्यरत हैं। इनके निर्देशन में अनेक शोधार्थी समाजशास्त्र एवं अपराधशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. अखिलेश रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0973-3914) तथा रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0975-4083) के ऑनरेरी एडिटर का कार्य भी सम्पादित कर रहे हैं।

GAYATRI PUBLICATIONS

Rewa - 486001 (M.P.) INDIA

Mobile : 07974781746

E-mail : gayatripublicationsrewa@gmail.com

www.researchjournal.in



978-81-87364-81-8